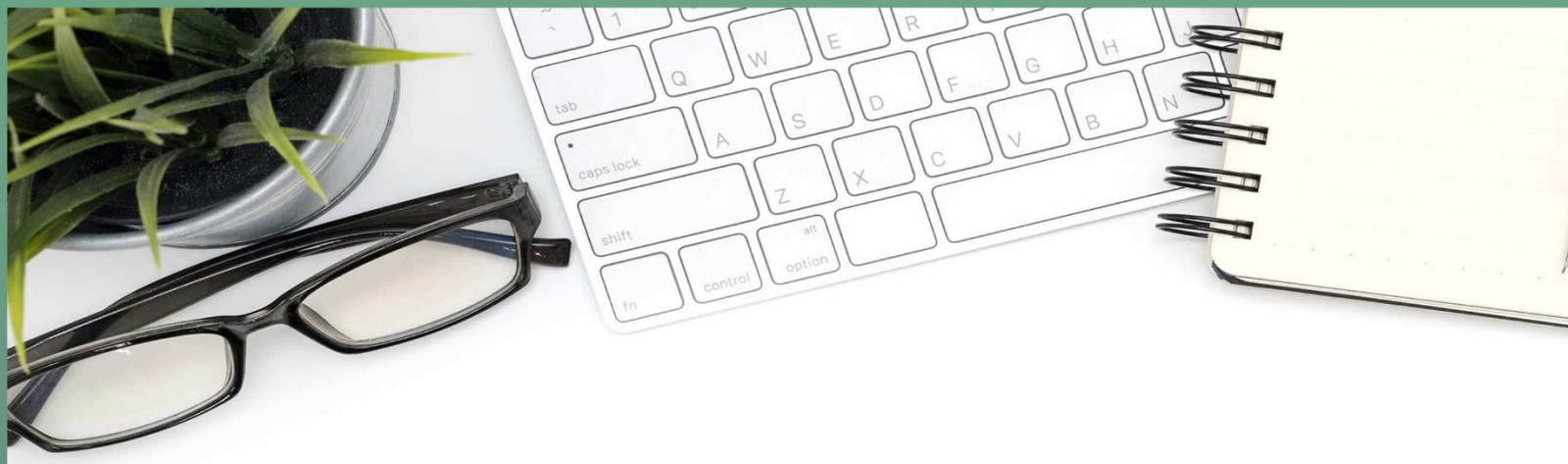

मासिक करंट अफेयर्स यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं के लिए

नवम्बर 2018

Powered by :

gradeup

दैनिक सामयिकी यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिये

01.11.2018

1. **भारत 77 वें स्थान पर पहुंच गया: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स**

- भारत ने विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 190 अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापारिक विनियमन के मूल्यांकन में अतिरिक्त 23 अंक प्राप्त कर 77वां स्थान प्राप्त किया है।
- भारत अब पहली बार दक्षिण एशियाई देशो में शीर्ष स्थान पर और ब्रिक्स देशों के मध्य तीसरे स्थान पर है।
- निर्माण परमिट के क्षेत्र में सबसे बड़ा लाभ हुआ था जहां भारत ने बाधाओं को दूर करने के लिए लक्षित सरकारी प्रयासों के सहारे 129 स्थानों की छलांग लगाकर 52वां स्थान प्राप्त किया है।
- अब भारत तीन संकेतकों पर विश्व के शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त कर चुका है। ये संकेतक विद्युत प्राप्त करना है, ऋण प्राप्त करना और अल्पसंख्यक निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की रक्षा करना है।
- डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, सीमा से दूरी (डी.टी.एफ.) के आधार पर देशों को स्थान प्रदान करती है, यह स्कोर है जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक अभ्यासों पर अर्थव्यवस्था के अंतर को दर्शाता है।
- पिछले वर्ष की तुलना में भारत के डी.टी.एफ. स्कोर में सुधार हुआ है, यह 67.23 से घटकर 60.76 हो गया है।

संबंधित जानकारी

भारत द्वारा किए गए सुधार:

- इस वर्ष की रिपोर्ट में 6 सुधारों को पहचाना गया है, वे एक व्यवसाय शुरू करना, बिजली प्राप्त करना, निर्माण परमिट से निपटना, ऋण प्राप्त करना, करों का भुगतान करना और सीमापार व्यापार करना हैं।
- निर्माण परमिट से निपटने हेतु भारत ने एक ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली लागू की है, प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इन परमिटों प्राप्त करने के लिए लागत कम कर दी गई है।
- विद्युत क्षेत्र में, एक नया कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लिया गया समय 105 दिनों से घटकर 55 दिन हो गया है।
- दिवालियापन को हल करने के लिए, भारत ने कॉर्पोरेट देनदारों के लिए समयबद्ध पुनर्गठन प्रक्रिया और एक नई दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता स्थापित की है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – महत्वूपर्ण सूचकांक

स्रोत- द हिंदू

2. **विश्व की पहली जैव-ईंट, CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है।**

- केप टाउन विश्वविद्यालय (यू.सी.टी.) ने मानव के मूत्र से विश्व की पहली जैव-ईंट विकसित की है जिसके अपशिष्ट रीसाइक्लिंग हेतु बड़े परिणाम हो सकते हैं।
- इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है जिसे माइक्रोबियल कार्बोनेट प्रेसीपिटेशन कहा जाता है जिसमें ढीली रेत को जीवाणुओं के साथ स्थापित किया जाता है और यूरियाज नामक एंजाइम उत्पन्न होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करते समय यूरिया को मूत्र में परिवर्तित कर देता है।
- जैव-ईंट, पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयुक्त हैं क्यों कि सामान्य ईंटों को 1400 डिग्री सेंटीग्रेट के तापमान पर गर्म किया जाता है, जैव-ईटों को सामान्य कमरे के तापमान पर गर्म किया जाता है, अत: यह उतनी अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड नहीं उत्सर्जित करेंगी।
- जैव-ईंट बनाने की प्रक्रिया में उत्पादन उत्पादों के रूप में नाइट्रोजन और पोटेशियम का उत्पादन होता है, जो वाणिज्यिक उर्वरकों के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।
- ईंट को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है।

संबंधित जानकारी

- दक्षिण एशिया में प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ईंट की भट्टियां हैं।
- भारत, विश्व में ईंटों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्रति वर्ष 200 अरब ईंटों का उत्पादन करता है।
- एक अध्ययन के अनुसार, वायु को प्रदूषित करने के अतिरिक्त ईंट भट्टियां शीर्षतम मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करती हैं। भारत में लगभग 65 प्रतिशत ईंटों का निर्माण भारतीय-गंगीय मैदानों में किया जाता है।
- 2017 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में सभी भट्टियों को ज़िगज़ैग प्रौद्योगिकी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।
- ईंटों की भट्टियों की ज़िगज़ैग तकनीक में परंपरागत ईंट भट्टों की तुलना में 70 प्रतिशत कम कणिका तत्व उत्सर्जित होते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

3. **<u>गरीबी की अवस्थाएं: बहुआयामी गरीबी सूचकांक का अन्वेषण</u>**

- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) की गणना ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल और यू.एन.डी.पी. द्वारा की जाती है।
- एम.पी.आई. की गणना 105 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए की जाती है।
- इस सूचकांक में वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2016 में भारत में कुल गरीबी में कमी आयी है, राज्यों और समुदायों के मध्य प्रगति असमान रही है।

संबंधित जानकारी

एम.पी.आई. क्या है?

- एम.पी.आई. एक मापक है जो गरीबी की व्यापकता और हानियों के विस्तार की गणना करता है।
- एम.पी.आई. मौद्रिक उपायों से ऊपर उठकर विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
- यह तीन आयामों: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में गरीबी को मापने के लिए 10 संकेतकों का प्रयोग करता है।

वैश्विक तुलना

- भारत का एम.पी.आई., वैश्विक औसत 0.15 और दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में कम है लेकिन ब्रिक्स देशों (रूस को छोड़कर) की तुलना में अधिक (बदतर) है।
- अपने वर्ष 2018 के अपडेट में, वर्ष 2018 में भारत का एम.पी.आई. इंडेक्स 0.121 था, जिसके कारण 105 विकासशील देशों में भारत 53वें स्थान पर था, जिसके लिए डेटा उपलब्ध था।
- भारत की बहुआयामी गरीबी में कुपोषण सबसे अधिक योगदान देता था, जब कि स्वच्छ पानी तक अपर्याप्त पहुँच और बाल मृत्यु दर सबसे कम योगदान देती थी।

नोट: गणना करने पर मान 0 से 1 के मध्य ही रहता है। 1 एम.पी.आई. मान उच्चतम वंचित स्तर को इंगित करता है, जब कि 0 एम.पी.आई मान निम्नतम वंचित स्तर को इंगित करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

4. **<u>उड़ीसा में सौराजलानिधि योजना शुरू की गई है।</u>**

- ओडिशा सरकार ने सौराजलानिधि योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाकर किसानों की उनकी भूमि को सिंचित करने में मदद करना है।
- 'सौराजलानिधि', अभिसरण प्रणाली में खोदे गए कुएं पर आधारित एक सौर पंप सिंचाई प्रणाली है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को 90 प्रतिशत की सब्सिडी पर सौर पंप प्रदान किए जाएंगे।

संबंधित जानकारी

- किसानों के पास वैध किसान पहचान पत्र होना चाहिए, वे छोटी और सीमांत श्रेणियों से संबंधित होने चाहिए जिनके पास न्यूनतम 0.5 एकड़ की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए और इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोदा गया कुआं भी शामिल किया जाएगा।

- यह योजना किसानों पर लागत के बोझ को कम करेगी।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – सरकारी योजना

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

5. **<u>भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है।</u>**

- डॉ. अब्दुल कलाम आइलैंड से रणनीतिक बल कमांड (एस.एफ.सी.) द्वारा आवधिक प्रशिक्षण गतिविधि के भाग के रूप में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को लांच करने का कार्य शुरू किया गया था।

संबंधित जानकारी

अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल

- अग्नि-1, कम दूरी तक मार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल है जिसे एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित किया गया है।
- अग्नि -1 एक एकल चरणीय, ठोस ईंधन, सड़क और रेल गतिक, कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (एस.आर.बी.एम.) है।
- यह 1000 किलोग्राम का पारंपरिक पेलोड (2,200 पाउंड) अथवा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
- अग्नि-I मिसाइल की रेंज 700-900 कि.मी. है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

6. **<u>वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 19वीं बैठक</u>**

- हाल ही में, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफ.एस.डी.सी.) की 19वीं बैठक आयोजित की गई थी।

संबंधित जानकारी

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफ.एस.डी.सी.)

- यह भारत सरकार द्वारा गठित एक शीर्ष-स्तरीय निकाय है।
- यह एक वैधानिक निकाय नहीं है।
- हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व में सरकारों और संस्थानों पर अपनी आर्थिक परिसंपत्तियों को विनियमित करने हेतु दबाव डाला था। इस परिषद को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर स्थिति में भारत की पहल के रूप में देखा जाता है।
- नए निकाय के द्वारा वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अर्थव्यवस्था के मैक्रो-प्रुडेंशियल विनियमन की निगरानी के साथ अंतर-नियामक समन्वय को बनाए रखने के तंत्र को मजबूत और संस्थागत करने की कल्पना की जाती है।

परिषद की संरचना

अध्यक्ष: भारत के केंद्रीय वित्त मंत्र

अन्य सदस्य:

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के गर्वनर
- वित्त सचिव और/ अथवा आर्थिक मामलों के विभाग (डी.ए.ई.) के सचिव
- अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)
- अध्यक्ष, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा)
- सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (डी.एफ.एस.)
- सचिव, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
- मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय आदि

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – आर्थिक विकास

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **<u>कर्नाटक ने एससी/ एसटी उद्यमिता योजना शुरू की: समृद्धि योजना</u>**

- कर्नाटक समाज कल्याण विभाग ने उद्यमिता के माध्यम से एससी/ एसटी युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना शुरू की।
- समृद्धि योजना के लक्ष्य पर सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय है, इस योजना के अंतर्गत उन्हें कौशल विकास और रोजगार के वैकल्पिक साधन प्रदान किए जाएंगे।
- यह योजना पिछड़े समुदायों के युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु निजी उद्यमों के साथ साझेदारी कर रही है, जिससे कि 'औद्योगिक स्वामित्व वाले निजी उद्यम' स्थापित कर उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – सरकारी योजना

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>सितंबर में कोर सेक्टर की विकास दर घटकर पिछले चार महीनों के निचले स्तर पर 4.3% रही।</u>**

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले आठ कोर उद्योगो के सूचकांक के अनुसार सितंबर माह में आठ ढांचागत सेक्टरों की विकास दर घटकर 4.3% हो गई है।
- यह पिछले चार महीनों में निम्नतम विकास दर है क्यों कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी आई है।

संबंधित जानकारी

- आठ कोर उद्योग, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) में शामिल उत्पादों के भार का लगभग 40.27% भाग हैं।
- ये विद्युत, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.), भारत के लिए एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खनिज खनन, विद्युत और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रदान करता है।
- यह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) का स्तर एक सारांशित संख्या है।
- आधार वर्ष को एक बार वर्ष 1993-94 में निश्चित किया गया था, अत: उस वर्ष को 100 का सूचकांक स्तर अभिहस्तांकित किया गया था।
- वर्तमान आधार वर्ष 2011-2012 है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – उद्योग

स्रोत-लिव मिंट

02.11.2018

1. **<u>रेल मंत्रालय ने नयी एप्लीकेशन शुरू की है: यू.टी.एस.ऑनमोबाइल' एप</u>**

- रेल मंत्रालय ने अखिल भारतीय अनारक्षित मोबाइल टिकट सुविधा (यू.टी.एस. ऑन मोबाइल) की शुरूआत की है।
- सीजन टिकटों और प्लेटफार्म टिकट सहित अनारक्षित टिकटों को 'यू.टी.एस.ऑनमोबाइल' ऐप के माध्यम से बुक करने की सुविधा उपलब्ध है।

संबंधित जानकारी

यू.टी.एस.ऑनमोबाइल ऐप

- एप्लीकेशन 'इन-हाउस' भारतीय रेलवे-सी.आर.आई.एस. द्वारा विकसित किया गया है।
- मोबाइल टिकटिंग सुविधा 3C- कैशलेस लेनदेन (डिजिटल भुगतान), संपर्करहित टिकट (प्वाइंट ऑफ सेल पर शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं) और ग्राहक सुविधा एवं अनुभव को बढ़ावा देगी।
- यह पूरे भारतीय रेलवे में अनारक्षित टिकटों की निर्बाध बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है।
- इससे यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए कतारों में इंतजार करने की आवश्यक्ता नहीं होगी और अनारक्षित टिकट- यात्रा, सीजन टिकट और प्लेटफार्म टिकट बुक करने के प्रति उनके अनुभवों को बढ़ाएगा।
- यह एप्लीकेशन पर्यावरण के अनुकूल भी है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>केंद्रीय मंत्रालय ने भारत का पहला ईज ऑफ मोबिलिटी इंडेक्स शुरू किया है:</u>**

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने भारत का पहला ईज ऑफ मोबिलिटी इंडेक्स 2018 शुरू किया है।
- यह रिपोर्ट ओला गतिशीलता संस्थान- ओला के अनुसंधान एवं सामाजिक नवाचार निकाय द्वारा तैयार की गई है।

- यह सूचकांक यात्रियों की वरीयता के साथ समाधानों को संरेखित करने और सूचित निर्णय लेने हेतु पारगमन संस्थाओं और शहरी योजनाकारों की सहायता करने के लिए सूचना का एक स्रोत प्रदान करता है।
- ईज ऑफ मोबिलिटी इंडेक्स, 2018 ने पाया है कि लगभग 80 प्रतिशत नागरिक यह मानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में परिवहन पारिस्थितिक तंत्र में सुधार हुआ है।
- सूचकांक यह भी बताता है कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता यात्रा के सार्वजनिक मोड का प्रयोग करते हैं, जो संकेत देता है कि बड़े पैमाने पर परिवहन के साथ प्रारंभिक और अंतिम मोड की मील कनेक्टिविटी को एकीकृत करने से इनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
- सूचकांक में पाया गया है कि 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन, पारंपरिक वाहनों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – महत्वूपर्ण सूचकांक

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>सिर्फ 5 देशों के पास विश्व के शेष जंगलों का 70% भाग है: अध्ययन</u>**

- इजिप्ट में जैविक विविधता पर सम्मेलन से पहले हाल ही में अध्ययन प्रकाशित किया गया है।
- इस अध्ययन में पाया गया है कि पांच देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, रूस और कनाडा के पास विश्व के शेष जंगलों का विशाल भाग है।
- यह विश्व के शेष अप्रभावित जंगलों का लगभग 70 प्रतिशत भाग है।

संबंधित जानकारी

- वर्ष 2016 में, वैज्ञानिकों ने ग्रह के शेष स्थलीय जंगलों का मानचित्रण किया और वर्ष 2018 में यह जांच की कि विश्व के महासागरों के कौन से हिस्से मानवीय गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से मुक्त हैं।

जंगल क्या है?

- अध्ययन, जंगल को एक मात्र ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित करता है जहां पर प्रचुरता के प्राकृतिक स्तर तक प्रजातियों का मिश्रण उपलब्ध है।
- इसके अतिरिक्त ये पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं का समर्थन करने वाले एकमात्र ऐसे स्थान हैं जो विकासवादी समय से जैव विविधता को बनाए रखे हैं।
- समुद्रों में, जंगल क्षेत्र सबसे अंतिम क्षेत्र होते हैं जिनमें टूना, मार्लिन और शार्क मछलियों जैसे शीर्ष शिकारियों की प्रचुर जनसंख्या निवास करती है।
- इसके अतिरिक्त वे मानव प्रभाव वाले परिदृश्यों में विलुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शरणार्थी भी प्रदान करते हैं।

चिंता

- कई जंगल क्षेत्र वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए महत्वपूर्ण सिंक हैं।
- यदि समुद्रो में समुद्री घास के मैदानों की भांति इन स्थानों को भी निम्नीकृत कर दिया जाएगा तो ये कार्बन सिंक के स्थान पर प्रमुख कार्बन स्रोतों में परिवर्तित हो जाएंगे।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

4. **<u>प्रधानमंत्री ने एम.एस.एम.ई. सेक्टर के लिए प्रमुख समर्थन एवं आउटरीच पहल की शुरूआत की है।</u>**

- प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) हेतु केंद्र सरकार की समर्थन एवं आउटरीच पहल की शुरुआत की है।
- यह कार्यक्रम पूरे देश में 100 स्थानों पर एक साथ शुरू किया गया है।

संबंधित जानकारी

- एम.एस.एम.ई. सेक्टर, भारत की लगभग 70 मिलियन आबादी को रोजगार प्रदान करता है।

- यह विनिर्माण उत्पादन में लगभग 35 प्रतिशत का और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

स्रोत: पी.आई.बी.

5. **<u>पहली बार बौद्धिक संपदा पर भारत-अमेरिका वार्तालाप शुरू हुई है।</u>**

- आई.पी. नीति पर द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने हेतु पहली बार बौद्धिक संपदा पर भारत-अमेरिका वार्तालाप शुरू हुई है।
- यह वार्तालाप, यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवीनता नीति केंद्र (जी.आई.पी.सी.) और अमेरिका-भारत व्यापार परिषद के साथ साझेदारी में फिक्की द्वारा शुरू की गई है।
- इस वार्ता को प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली और वाशिंगटन, डी.सी. में एकांतर रूप से आयोजित किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

बौद्धिक संपदा (आई.पी.)

- यह आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, वाणिज्य में प्रयोग किए जाने वाली डिजाइन, प्रतीक, नाम और चित्रों जैसी मस्तिष्क की रचनाओं को संदर्भित करता है।
- आई.पी. कानून में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे उदाहरणों द्वारा संरक्षित है, जो लोगों को उनके द्वारा खोजी अथवा बनायी गयी चीजों के माध्यम से पहचान बनाने अथवा वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है।

आई.पी. में प्रयोग की जाने वाली शर्तें

पेटेंट

- पेटेंट, सरकार द्वारा आविष्कारक अथवा उनके उत्तराधिकारी को दिए गए अधिकार का एक रूप है, जो मालिक को बनाने, उपयोग करने, बेचने, बेचने की पेशकश करने और सीमित समय के लिए आविष्कार को आयात करने, विनिमय के बदले अपने अविष्कार का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से अन्य को हटाने का अधिकार प्रदान करता है।

कॉपीराइट

- कॉपीराइट, वास्तविक कार्य के निर्माता को एक सीमित समय के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- कॉपीराइट को रचनात्मक, बौद्धिक या कलात्मक रूपों, अथवा "कामों" औद्योगिक डिजाइन अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया जा सकता है।

ट्रेडमार्क

- ट्रेडमार्क एक पहचान चिन्ह, डिज़ाइन अथवा अभिव्यक्ति है जो किसी विशेष व्यापारी के उत्पादों अथवा सेवाओं को अन्य व्यापारियों के समान उत्पादों या सेवाओं से अलग करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>भारत ने प्रवासी पक्षियों के पैराडाइज को बनाए रखने हेतु पांच वर्ष की कार्य योजना का अनावरण किया है।</u>**

- भारत ने रूस में सइबेरिया से लंबी दूरी तय करके सर्दियों के दौरान अस्थायी आवास बनाने हेतु हमारे देश में आने वाले इन प्रवासी प्रजातियों के निवासियों को संरक्षित करने के लिए पांच वर्ष की राष्ट्रीय कार्य योजना प्रस्तावित की है।
- केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कार्य योजना 2018-23 प्रस्तावित की गई है, जो पूरे केंद्रीय एशियाई फ्लाईवे (सी.ए.एफ.) में अपनी सीमा के भीतर भारत में प्रवासी पक्षियों की जनसंख्या को बढ़ाने और संरक्षित करने हेतु राज्यों के मध्य समन्वित कार्य हैं।
- इस कदम से भारत की कई झीलों और अन्य प्राकृतिक आवासों को संरक्षण प्राप्त होगा है और इसे देश में पक्षी विशेषज्ञ पैराडाइज के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

संबंधित जानकारी

मध्य एशियाई फ्लाईवे

- एक फ्लाईवे, एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक प्रवासी प्रजाति अथवा प्रवासी प्रजातियों का समूह अपने वार्षिक चक्र- प्रजनन, मॉलिंग, स्टेजिंग और गैर प्रजनन को पूरा करता है।

- सी.ए.एफ; विश्व के नौ फ्लाईवे में से एक है।
- सी.ए.एफ. के अंतर्गत 30 से अधिक देशों के प्रवासी व्यापक विस्तार हैं, जो विभिन्न जलीय पक्षियों को साइबेरिया में उनके उत्तरी प्रजनन मैदानों को पश्चिम और दक्षिण एशिया, मालदीव और ब्रिटिश हिंद महासागर सीमाओं पर स्थित उनके दक्षिणी गैर-प्रजनन मैदानों से जोड़ते हैं।
- फ्लाईवे में भारत की रणनीतिक भूमिका है क्यों कि यह प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.) द्वारा इस प्रवासी मार्ग का उपयोग करता है जिससे होकर गुजरने वाली 90% से अधिक पक्षी प्रजातियों को एक महत्वपूर्ण विराम स्थान प्रदान करता है।
- एन.ए.पी. के अनुसार, तीन फ्लाईवेज (सी.ए.एफ., पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे जो पूर्वी भारत के हिस्सों को कवर करता है और एशियाई पूर्वी अफ्रीकी फ्लाईवे जो पश्चिमी भारत के हिस्सों को कवर करता है) से प्रवासी पक्षियों की कम से कम 370 प्रजातियां अपने वार्षिक चक्र के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में आती हैं।
- चिल्का झील (ओडिशा), सुंदरबान राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल), ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश), नल सरोवर पक्षी अभयारण्य (गुजरात), कुमाराकोम पक्षी अभयारण्य (केरल और पुलिकट लैगून (आंध्र प्रदेश - तमिलनाडु) कई अन्य क्षेत्र भारत में प्रवासी पक्षियों के पसंदीदा स्थल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – जैवविविधता

स्रोत- टी.ओ.आई

7. **<u>मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी प्रदान की है।</u>**
   - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी प्रदान की है।

संबंधित जानकारी

- यह समझौता भारत और मोरक्को के मध्य द्विपक्षीय सहयोग हेतु एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह अपराध, अनुरेखण, नियंत्रण, दंड अथवा जब्ती अथवा अपराध के साधनों और उपकरणों की जांच और अभियोजनों में भी मदद करता है।
- इसका उद्देश्य अपराध की जांच और अभियोजन में प्रभावकारिता में वृद्धि करना है।
- यह समझौता आवश्यक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करेगा जो पूरे समाज के विकास के लिए पूर्व-आवश्यकता है।
- यह संगठित अपराधियों और आतंकवादियों की कार्यप्रणाली में बेहतर इनपुट और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका बदले में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णयों को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत-पी.आई.बी.

8. **<u>मंत्रिमंडल ने झरसुगुडा हवाई अड्डे का नाम बदलकर "वीर सुरेंद्र सांई हवाई अड्डे" करने को अनुमति प्रदान की है।</u>**
   - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा के झरसुगुडा हवाई अड्डे का नाम बदलकर "वीर सुरेंद्र सांई हवाई अड्डा" करने को मंजूरी प्रदान की है।
   - यह राज्य से जुड़े सम्मानित व्यक्तियों के योगदान के लिए एक उचित श्रद्धांजलि भी होगी।

संबंधित जानकारी

वीर सुरेंद्र सांई

- वीर सुरेंद्र सांई एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरूद्ध लड़ते हुए अपना जीवन का योगदान दिया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

03.11.2018

1. **भारत-जापान सैन्य युद्धाभ्यास "धर्म गार्डियन-2018" मिजोरम में प्रारंभ किया गया है।**

- भारत और जापान की सेनाओं ने मिजोरम के वैरेंग्टे में जंगल युद्ध स्कूल में अपना पहला संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू किया है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य सैन्य संबंधो के लिए सेनाओं का निर्माण और प्रोत्साहन करना और इसके अतिरिक्त दोनों सेनाओं के कौशल और अनुभवों को साझा करना है।
- युद्धाभ्यास 'धर्म गार्डियन-2018' दोनो देशों के मध्य घनिष्ठ रक्षा सहयोग के साथ ही रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु एक अन्य कदम है।

संबंधित जानकारी

- भारतीय और जापानी नौसेनाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले नौसेना युद्धाभ्यास जाइमेक्स और मालाबार हैं।

टॉपिक-जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. **मालाबार पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु एस.एम.आई.एल.ई.**

- केरल पर्यटन ने एक उच्च तकनीक डिजिटल सुविधा शुरू की है जो आगंतुकों को मालाबार क्षेत्र में अनुभवों और सर्विस पैकेजों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है, यह सुविधा उत्तर केरल की ओर पर्यटको को आकर्षित करने हेतु शुरू की गई है।
- इस पैकेज का संक्षिप्त रूप एस.एम.आई.एल.ई.(स्माइल) है, इसका पूरा नाम लघु एवं मध्यम उद्योग लाभान्वित अनुभवात्मक पर्यटन" है।
- एस.एम.आई.एल.ई. की कल्पना बेकल रिसॉर्ट्स विकास निगम (बी.आर.डी.सी.) द्वारा की गई है, यह पर्यटकों को उनके आकर्षक स्थानों से जोड़ता है और अनुभावात्मक सेवा प्रदाता है।
- एस.एम.आई.एल.ई. वी.टी.जी., यात्रियों के लिए मालाबार का अग्रणी व्यापक पैकेज था।

संबंधित जानकारी

- मालाबार, केरल के उत्तरी हिस्से पर पश्चिमी घाटों और अरब सागर के मध्य स्थित है।
- आधुनिक दिनों का मलाबार भरतापुझा नदी के उत्तर में भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है।
- इसमें थ्रिशूर जिले के हिस्से, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कसारागोड जिले शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यटन विकास हेतु सरकार के दृष्टिकोण

स्रोत-द हिंदू

3. **शक्ति: भारत का पहला माइक्रोप्रोसेसर**

- भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर शक्ति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की चंडीगढ़ स्थित माइक्रोचिप निर्माता प्रयोगशाला द्वारा विकसित और बूट किया गया है।
- यह आयातित माइक्रोचिपों पर निर्भरता और साइबर हमलों के खतरों को कम करते हुए इसे संचार और रक्षा क्षेत्रों हेतु आदर्श बनाएगा।
- भारत में निर्मित माइक्रोप्रोसेसर 180 एन.एम. सुविधा में था जब कि अमेरिका में निर्मित माइक्रोप्रोसेसर 20 एन.एम. प्रयोगशाला में था।

संबंधित जानकारी

माइक्रोप्रोसेसर

- माइक्रोप्रोसेसर, एक कंप्यूटर प्रोसेसर होता है जो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के कार्यों को एक एकल एकीकृत परिपथ (आई.सी.) पर निगमित करता है।
- माइक्रोप्रोसेसर एक बहुउद्देश्यीय, घड़ी संचालित, रजिस्टर-आधारित, डिजिटल एकीकृत परिपथ होता है जो इनपुट के रूप में बाइनरी डेटा स्वीकार करता है, अपनी मेमोरी में संग्रहीत निर्देशों के अनुसार इसे संसाधित करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदान करता है।
- माइक्रोप्रोसेसर, बाइनरी संख्या प्रणाली में दर्शायी गई संख्याओं और प्रतीकों पर क्रियान्वित होते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

4. **<u>जलवायु परिवर्तन के कारण "हिमालयी वियाग्रा" पर खतरा है।</u>**

- यह एक मूल्यवान कैटरपिलर कवक है जो सोने की तुलना में अधिक मूल्यवान है और एशिया में इसका उपनाम "हिमालयी वियाग्रा" है।
- शंकु के आकार का यह कवक केवल 9,800 फीट (3,000 मीटर) की ऊंचाई पर पाया जाता है और यह तब बनता है जब परजीवी कवक, एक कैटरपिलर में रहता है और धीरे-धीरे इसे मारता है।
- इसे बढ़ने के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यक्ता होती हैं जहां पर सर्दियों का तापमान हिमांकन बिंदु से नीचे रहे और वहां की मृदा हमेंशा के लिए न जमें।
- इसे एक आश्चर्यजनक दवा के रूप में माना जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इसे खोजना अत्यंत दुर्लभ होता जा रहा है।
- अत: इसके वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कोई लाभ नहीं है, जो लोग चाय बनाने के लिए यर्छागुंबा को पानी में उबालते हैं अथवा इसे सूप में मिलाते हैं, वे मानते हैं कि यह नपुंसकता से लेकर कैंसर तक सारी बीमारियों को ठीक करता है।
- एक रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह विश्व के सबसे अधिक मूल्यवान जैविक उत्पादों में से एक है, जो सैकड़ों, हजारों संग्राहकों को आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है।"

संबंधित जानकारी

- पूरे हिमालयी क्षेत्र में बसने वाले समुदाय बहुत अधिक वित्तीय रूप से निर्भर होने के कारण कैटरपिलर कवक को इकट्ठा करते और बेचते हैं।
- इस कवक की उपलब्धता में होने वाली कमी, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए विनाशकारी होगी और इन समुदायों को अन्य व्यवहार्य आजीविका विकल्पों की आवश्यकता होगी।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – जैवविविधता

स्रोत- डाउन टू अर्थ

5. **<u>क्षुद्रगृह हेतु नासा का ऐतिहासिक डॉन मिशन समाप्ति की ओर अग्रसर है।</u>**

- नासा का अग्रणी डॉन अंतरिक्ष यान जो क्षुद्रग्रह बेल्ट में दो सबसे बड़ी वस्तुओं के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसमें ईंधन की कमी हो गई है।
- डॉन मिशन को वर्ष 2007 में एक यात्रा पर पुरातन ग्रह वेस्टा और बौने ग्रह सेरेस का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसने अपने ओडोमीटर पर 6.9 अरब किलोमीटर की दूरी तय की थी।

संबंधित जानकारी

- वर्ष 2011 में, जब डॉन मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में दूसरी सबसे बड़ी दुनिया वेस्टा पहुंचा तो यह अंतरिक्ष यान, मंगल और बृहस्पति के मध्य इस क्षेत्र में एक पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था।
- वर्ष 2015 में, डॉन ने सेरेस के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया, यह एक बौना ग्रह है जो क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी दुनिया है।
- यह एक बौने ग्रह का दौरा करने वाला और पृथ्वी से दूर दो गंतव्यों के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला मिशन बना।
- इस अंतरिक्ष यान को मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में दो सबसे बड़े पिंडो की यात्रा करने के लिए 11 वर्ष पहले लांच किया गया था।
- वर्तमान में, डॉन बौने ग्रह सेरेस के चारों ओर कक्षा में है, जहां यह दशकों तक रहेगा।

नोट:

नासा ने यह भी घोषणा की है कि इसके एक्सोप्लैनेट-हंटिंग केपलर अंतरिक्ष दूरदर्शी में हाइड्राज़िन ईंधन की कमी हो गई है और यान को संचालन बंद करने का आदेश दिया जाएगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>वैश्विक औषधि सर्वेक्षण भारतीयों को कवर करने के लिए तैयार है।</u>**

- आठ वर्षों में पहली बार जी.डी.एस., वर्ष 2019 के लिए भारत में अल्कोहल, कैनाबिस और मादक द्रव्यों की खपत के रुझानों का सर्वेक्षण करेगा।

- यह सर्वेक्षण 35 देशों में दवा की आदतों की जांच करेगा और इसके निष्कर्षों का अनुवाद 20 भाषाओं में किया जाएगा।
- इस सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार से उन्नत तकनीकें दवाओं के उपयोग को प्रभावित करती है और हानिकारक खुराकों के स्तर को निर्धारित करने में आने वाली जटिलताएं इसको कैसे प्रभावित करती हैं और उन व्यक्तियों को किस प्रकार प्रभावित करती है जो दवा संबंधित हानिकारक प्रतिक्रियाओं को कम करना चाहते हैं।
- यह सर्वेक्षण एम.डी.एम.ए. (3, 4-मेथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन), जिसे 'एक्सटैसी' के नाम से जाना जाता है और एल.एस.डी. (लिसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड) जैसी दवाओं की चिकित्सीय क्षमताओं को समझने हेतु किया जाता है।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में कुछ अध्ययनों ने शराब, अवैध दवाओं और भारत में दवा उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले परिणामों की जांच की है।
- केंद्रीय न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में दवाओं के दुरुपयोग की सीमा, प्रारूप और प्रवृत्तियों पर किए गए सर्वेक्षण में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था।
- उस अध्ययन में शराब के उपयोग का प्रसार 21% था और कैनबिस का वर्तमान उपयोग 3% पर पाया गया था।
- अल्कोहल और कैनाबिस के वर्तमान उपयोगकर्ताओं में क्रमशः 16% और 25% आश्रित थे।

जी.डी.एस. 2019 के संदर्भ में जानकारी-

- जी.डी.एस. 2019 सामाजिक मुद्दों की जांच करेगा, जिसमें यह शामिल होगा कि पुलिस ड्रग्स का उपयोग करने वाले लागों से किस प्रकार व्यवहार करती है और यौन उत्पीड़न की जटिल समस्याओं, सहमति और नशीली दवाओं के प्रति किस प्रकार व्यवहार करती है।
- जी.डी.एस. वार्षिक अज्ञात सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक इन्क्रिप्टेड ऑनलाइन मंच का उपयोग करता है।
- कोई आई.पी. एड्रेस एकत्र नहीं किया जाता है और सर्वेक्षण, सरकारों पर निर्भर नहीं होता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – हेल्थकेयर सेक्टर

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>पूर्वानुमान की तुलना में महासागर तेजी से गर्म हो रहे हैं: आई.पी.सी.सी.</u>**

- अंतर्सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के अनुसार हाल ही में किए गए मूल्यांकन में पाया गया है कि मानव निर्मित कार्बन उत्सर्जन के कारण दुनिया के महासागर तापमान वृद्धि का 90 प्रतिशत भाग अवशोषित कर रहे हैं।
- आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1991 से प्रत्येक दशक में महासागरों का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस (11.7 डिग्री फारेनहाइट) बढ़ जाता है।
- विश्व के महासागर पिछली शताब्दी की अंतिम तिमाही के दौरान किए गए पिछले पुर्वानुमान की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं, जो पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा हैं।
- महासागर, ग्रह की सतह के दो तिहाई से अधिक भाग में फैले हुए हैं और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यह पाया गया कि पिछले 25 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में महासागरों ने वार्षिक रूप से मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिजली की मात्रा के 150 गुना के बराबर ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित की है।

संबंधित जानकारी

- वैज्ञानिक मुख्य रूप से वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दो गैसों: ऑक्सीजन और कार्बन डाइ ऑक्साइड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- दोनों गैसें पानी में घुलनशील हैं लेकिन जिस दर से पानी उन्हें अवशोषित करता है वह दर इसके गर्म होने के साथ कम होती जा रही है।

- प्रत्येक वर्ष के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 को मापकर वैज्ञानिक अधिक यर्थाथता के साथ इसका अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं कि वैश्विक स्तर पर महासागर कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहें हैं।

अंतर्सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल

- अंतर्सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आई.पी.सी.सी.), संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी निकाय है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- यह विश्व को जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृटिकोण और उसके राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु समर्पित है।
- इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम संगठन (डब्लू.एम.ओ.) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- वर्ष 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार, आई.पी.सी.सी. और ए.आई गोरे के मध्य समान रूप से साझा किया गया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

8. **<u>भारत और जापान ने तुर्गा पंप स्टोरेज हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।</u>**

- भारत और जापान ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में तुर्गा पंप स्टोरेज हाइडल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- परियोजना का उद्देश्य बिजली की आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मजबूत करना और पंप भंडारण सुविधाओं का निर्माण करके बिजली की आपूर्ति की स्थिरता में सुधार करना है।
- यह परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास और जीवन स्तर के क्षेत्र में योगदान प्रदान करेगी।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

05.11.2018

1. **<u>चांगशा घोषणा: वैश्विक दक्षिण में 'जीरो हंगर' को लक्षित करने हेतु एक पहल</u>**

- चांगशा घोषणा, चीन के चांगशा में अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग पर एक मंच में प्रस्तावित की गई थी।
- इसमें 20 से अधिक देश, गरीबी और भुखमरी को खत्म करने हेतु कृषि और ग्रामीण विकास पर एक नई घोषणा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- चांगशा घोषणा का उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग की दिशा में प्रयासों को बढ़ाना है, यह एक पहल है जो "वैश्विक दक्षिण" के देशों के मध्य अच्छी प्रथाओं, संसाधनों, और अनुभवों के विनिमय और पारस्परिक साझेदारी के माध्यम से भुखमरी और कुपोषण को खत्म करने के लिए काम करती है।
- यह मंच, नई रिपोर्ट के लांच से मेल खाता है, जो खाद्य एवं कृषि सगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भोजन की कमी की गंभीर चेतावनी जारी करती है।

संबंधित जानकारी

- चीन, देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक्वाकल्चर फसल उत्पादन और पशुधन प्रजनन सहित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में ज्ञान साझा करने हेतु विशेषज्ञों और तकनीशियनों को क्षेत्रबद्ध कर रहा है।
- मंच, कृषि नवाचार में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं और जीरो हंगर के पहले 2030 सतत विकास लक्ष्य (2) तक पहुंचने के प्रयास में ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

2. **<u>ए.आई. बॉट 'सी.एल.ए.आर.ए.एन.' रेडियो आकाशगंगाओं का पता लगा सकता है।</u>**

- 'सी.एल.ए.आर.ए.एन.', माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सॉफ़्टवेयर के ओपन सोर्स संस्करण से "क्लेरन" आगे बढ़ गया है।
- ए.आई. बॉट "सी.एल.ए.आर.ए.एन." फेसबुक पर चेहरों को पहचानने के लिए जाना जाता था (अंतर्राष्ट्रीय रेडियो खगोलविज्ञान अनुसंधान केंद्र)।
- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) प्रोग्राम का उपयोग करेगा जो फेसबुक में चेहरों को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता था वह अब गहरे अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- "सी.एल.ए.आर.ए.एन." नामक ए.आई. बॉट, रेडियो दूरदर्शी द्वारा ली गई तस्वीरों को स्कैन करता है।
- इसका काम रेडियो आकाशगंगाओं का पता लगाना है जो अपने केंद्र पर विशालकाय ब्लैक होल से शक्तिशाली रेडियों जेटों का उत्सर्जन करता हैं।

संबंधित जानकारी

- 'सी.एल.ए.आर.ए.एन.', अंतर्राष्ट्रीय रेडियो खगोलविज्ञान अनुसंधान केंद्र (आई.सी.आर.ए.आर.) के पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के बड़े डाटा विशेषज्ञ डा. चेन वू और खगोलविद् डा. इवी वांग के दिमाग की उपज है।

यह किस प्रकार काम करता है?

- ब्लैक होल, अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं।
- ये विशालकाय ब्लैक होल कभी-कभी जेटों का उत्सर्जन करते हैं जिन्हें रेडियो दूरदर्शी से देखा जा सकता है।
- "'सी.एल.ए.आर.ए.एन.', उन जेटों का पता लगाने में मदद करते हैं जो अपने मेजबान आकाशगंगाओं से काफी दूर स्थित होते हैं, जिससे पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आकाशगंगा कहां स्थित है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

3. **<u>चीन ने विश्व की पहली आयात-थीम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है।</u>**

- चीन ने पड़ोसी देश के साथ 51 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के व्यापारिक घाटे को कम करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में शंघाई में पहली अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है।
- यह विश्व की पहली आयात-थीम वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है जिसमें उद्यम और व्यापार प्रदर्शनियां तथा व्यापार और निवेश हेतु देशों के मंडप शामिल होंगे।
- बारह देश- ब्राजील, कनाडा, इजिप्ट, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और ब्रिटेन मेगा बिजनेस कार्यक्रम में "सम्मानीय अतिथि" होंगे।

संबंधित जानकारी

- इस प्रदर्शनी का आयोजन अमेरिका के साथ चीन के व्यापारिक युद्ध के दौरान किया गया था, जिसने बीजिंग से 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक घाटे को कम करने की मांग करते हुए 250 अरब अमेरिकी डॉलर के चीनी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था।
- भारत ने कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन के अपने प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए प्रदर्शनी में देश के मंडप का निर्माण किया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

4. **<u>होप द्वीप में ग्रेटर फ्लेमिंगो</u>**

- लंबे समय के अंतराल के बाद होप द्वीप के तट पर पांच ग्रेटर फ्लेमिंगो का एक झुंड देखा गया है, जो आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है।
- यह अभयारण्य, सदाबहार पौधों की लगभग 35 प्रजातियों और दुर्लभ पक्षियों की अन्य 120 प्रजातियों का निवास स्थान है।

संबंधित जानकारी

कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य

- कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य और नदीमुख है।
- यह भारत में सदाहार वनों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।
- यह अभयारण्य गोदावरी नदीमुख का हिस्सा है और इसमें व्यापक मात्रा में सदाबहार वन और शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन हैं।
- यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफेद पीठ वाले गिद्ध और दीर्घकालीन हुंडी वाले गिद्धों का निवास स्थान है।

ग्रेटर फ्लेमिंगो

- ग्रेटर फ्लेमिंगो (फीनिकोप्टेरस रोसियस), राजहंस परिवार की सबसे व्यापक और सबसे बड़ी प्रजाति है।
- यह अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व में और दक्षिणी यूरोप में पाई जाती है।
- संरक्षण की स्थिति: नयूनतम चिंता (आई.यू.सी.एन. द्वारा)

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण एवं जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

5. **<u>हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ के मंत्रिपरिषद की 18वीं बैठक</u>**

- आई.ओ.आर.ए. के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, डरबन में आई.ओ.आर.ए. के मंत्रिपरिषद (विदेशी) की 18 वीं बैठक का आयोजन करेगा।
- "आई.ओ.आर.ए. की थीम - शांति, स्थिरता और सतत विकास हेतु उन्नत सहयोग के माध्यम से अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के लोगों को एकजुट करना है।
- आई.ओ.आर.ए. नेल्सन मंडेला 'बी द लीगेसी' इंटर्नशिप कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था जो हिंद महासागर क्षेत्र के युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने हेतु योगदान देने में मदद करता है।

संबंधित जानकारी

हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ

- हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हिंद महासागर की सीमाओं को साझा करने वाले तटीय राज्यों से मिलकर बना हैं।
- आई.ओ.आर.ए. एक क्षेत्रीय मंच है और त्रिपक्षीय प्रकृति का है जो सरकार के प्रतिनिधियों, व्यापारों और अकादमियों के मध्य सहयोग और घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें एक साथ इकठ्ठा करता है।
- यह विशेष रूप से व्यापार सुविधा और निवेश, क्षेत्र के सामाजिक विकास के साथ संवर्धन पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने हेतु खुले क्षेत्रीयवाद के सिद्धांतों पर आधारित है।
- आई.ओ.आर.ए. का समन्वयक सचिवालय इबेन, मॉरीशस में स्थित है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

6. **<u>अपतटीय गश्ती पोत, आई.सी.जी.एस. वाराहा लॉन्च किया गया है।</u>**

- आई.सी.जी.एस. वाराहा, भारतीय तट रक्षक बल के 98 M अपतटीय गश्ती पोतों (ओ.पी.वी.) की श्रृंखला में चौथा पोत है, जिसे एल एंड टी कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था।
- 98M ओ.पी.वी. को लार्सन एंड टर्बो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- इस परियोजना के पहले और दूसरे जहाजों को पहले से ही आई.सी.जी. को दिया जा चुका है और यह वर्तमान में भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर तैनात है और तीसरा, ओ.पी.वी. वर्ष 2019 की शुरुआत में वितरित किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

गश्ती पोत के संदर्भ में जानकारी-

- जहाज में उन्नत प्रौद्योगिकी नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी लगाई जाएगी।
- इसके अतिरिक्त जहाज को एकीकृत ब्रिज प्रणाली (आई.बी.एस.), एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली (आई.पी.एम.एस.), स्वचालित ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ए.पी.एम.एस.) और उच्च क्षमता बाहरी अग्निशमन (ई.एफ.एफ.) प्रणाली से लैस किया जाएगा।

- आई.सी.जी.एस. वाराहा में दो इंजनों वाला एक हेलीकॉप्टर और चार हाई स्पीड नौकाएं होंगी, जिनमें से दो इन्फ्लैटेबल नौकाएं होंगी जो बोर्डिंग ऑपरेशनों, खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्ती के लिए प्रयोग की जाएंगी।
- इन जहाजों को शामिल करने से समुद्री हितों की सुरक्षा अथवा सुरक्षा में आई.सी.जी. की अवरोध की भूमिका को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- यह समुद्र में तेल फैलाव को नियंत्रित करने हेतु प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण को ले जाने में सक्षम होगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत-पी.आई.बी.

7. **<u>एल.पी.जी. सेवाओं में सहयोग हेतु ओ.एम.सी. और सी.एस.सी. एस.पी.वी. के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।</u>**

- एल.पी.जी. सेवाओं में सहयोग हेतु तेल विपणन कंपनियों (आई.ओ.सी.एल., एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल.) और सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यह समझौता ज्ञापन, तकनीकि के उचित उपयोग और भारत के लोगों की उद्यमी भावना का दोहन करने के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में होने वाली समस्याओं का समाधान करने में मदद करेगा।

संबंधित जानकारी

- सामान्य सेवा केंद्र, डिजिटल सेवा पोर्टल को एक्सेस करने के माध्यम से लाभार्थियों को उनके घर के निकट उपर्युक्त ओ.एम.सी. सेवाएं प्रदान करेगा।

सामान्य सेवा केंद्र के संदर्भ में जानकारी-

- सामान्य सेवा केंद्र (सी.एस.सी.), डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की रणनीतिक आधारशिला हैं।
- नागरिकों को विभिन्न जी2सी (सरकार से नागरिक) और अन्य बी2सी (व्यापार से नागरिक) सेवाएं प्रदान करने हेतु सहायता प्राप्त अग्रांत आई.सी.टी. (सूचना एवं संचार तकनीकि) सक्षम केंद्रों के रूप में सी.एस.सी. को परिकल्पित किया गया था।
- सी.एस.सी. केंद्र का संचालन गांव स्तर उद्यमी (वी.एल.ई.) नामक ऑपरेटर द्वारा किया जाता है।
- वी.एल.ई. के पास उसके सी.एस.सी. केंद्र में बुनियादी स्तर का कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वह नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होता है।
- वे डिजिटल विकास, ग्रामीण उद्यमियों और सामाजिक समावेश को उत्प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – सरकारी पहलें

स्रोत-पी.आई.बी.

8. **<u>आगंतुकों की सहायता करने हेतु अरुणाचल में टूरिस्ट पुलिस एप्लीकेशन लांच किया गया है।</u>**

- अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने आपातकाल के दौरान नागरिकों की सहायता करने हेतु अरुणाचल प्रदेश टूरिस्ट पुलिस और अरुणाचल सुरक्षा एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं।
- यह राज्य पुलिस को अधिक कुशल बनाने हेतु प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत किया गया एक प्रयास है।
- यह एप्लीकेशन राज्य में अपराध की दर में महत्वूपर्ण कमी करेगा और राज्य में यात्रा करने हेतु आने वाले पर्यटक, अपने आस-पास टूरिस्ट पुलिस के साथ स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

संबंधित जानकारी

- अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में असम और नागालैंड राज्यों से घिरा हुआ है, पश्चिम में भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और मैकमोहन रेखा द्वारा उत्तर में चीन से अलग होता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

9. **दिल्ली के सिग्नेचर पुल का उद्घाटन किया गया।**

- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 'यमुना' नदी पर बनाए गए प्रतिष्ठित 'सिग्नेचर पुल' का उद्घाटन किया है।
- इस प्रतिष्ठित पुल की लंबाई 675 मीटर है, यह उत्तर और पूर्वोत्तर दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कम करेगा और वजीराबाद पुल के यातायात को साझा करेगा।
- सिग्नेचर पुल, एक कैंटिलीवर स्पार केबल पर बनाया गया पुल है, जो वजीराबाद क्षेत्र में यमुना नदी का विस्तार करता है और वजीराबाद को पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है।
- यह देश का पहला असममित केबल पर बनाया गया पुल है।

टॉपिक- पी.सी.एस. हेतु महत्वूपर्ण

स्रोत- ए.आई.आर.

06.11.2018

1. **एन.जी.टी. ने काफी समय से प्रतीक्षित: भारत न्यूट्रीनो परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।**

- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) की प्रमुख पीठ ने भारत आधारित न्यूट्रीनो वेधशाला (आई.एन.ओ.) परियोजना को पहले प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी के फैसले को बरकरार रखा है, यह मंजूरी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) द्वारा प्रदान की गई थी।
- आई.एन.ओ. को तमिलनाडु में एक चट्टानी पहाड़ के नीचे एक भूमिगत प्रयोगशाला में स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है।
- प्रस्तावित निर्माण-स्थान, केरल की सीमा पर माथिकेट्टन शोला पक्षी अभयारण्य से लगभग 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर पांच कि.मी. क्षेत्र के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी प्रमुख गतिविधि के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

संबंधित जानकारी

भारत स्थित न्यूट्रीनो वेधशाला परियोजना

- सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2017 में भारत स्थित न्यूट्रीनो वेधशाला परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी।
- यह कण भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में स्थापित किए गए न्यूट्रिनो अनुसंधानकर्ता, न्यूट्रिनो कारखानों और प्रयोगों की श्रृंखला में नवीनतम परियोजना है।

इसमें क्या शामिल होता है?

- यह एक भूमिगत परियोजना है और इसमें गुफाओं का समूह शामिल होगा।
- मुख्य गुफा में विशाल न्यूट्रीनो अनुसंधानकर्ता [50 किलो टन चुंबकीय लोहे का कैलोरीमीटर] रखा जाएगा, यह गुफा 130 मीटर लंबी, 26 मीटर चौड़ी और 30 मीटर ऊंची होगी।
- न्यूट्रिनो डबल अनुसंधानकर्ता और डार्क मैटर के लिए प्रयोग करने हेतु दो छोटी गुफाओं का प्रयोग किया जाएगा। इस गुफा के समूह तक पहुँचने हेतु 2 कि.मी. लंबी सुरंग से गुजरना होगा।

न्यूट्रिनो क्या है?

- न्यूट्रीनो, वे सबसे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई है।

इस परियोजना का प्रभारी कौन है?

- टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान, एक प्रधान संस्थान है। इस वेधशाला का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

दक्षिण में आई.एन.ओ. की स्थापना करने के संदर्भ में क्या विशेष है?

- एक परियोजना रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश न्यूट्रिनो अनुसंधानकर्ता 35 डिग्री से अधिक अक्षांश पर स्थित हैं।
- इस प्रकार के अनुसंधानकर्ता को भूमध्य रेखा के निकटतम दक्षिण भारत में लगभग 8 डिग्री अक्षांश तक स्थानांतरित करना संभव है।
- यह पृथ्वी की कोर से गुजरता हुआ पूरे खगोलीय आकाश और सौर न्यूट्रिनो के अध्ययन को कवर

करता हुआ न्यूट्रीनों खगोल विज्ञान की खोजों को स्वीकृति प्रदान करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

2. **<u>आर.बी.आई. ने खराब ऋणों को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।</u>**

- रिजर्व बैंक ने सभी उधारकर्ताओं के विवरण की जानकारी एकत्र करने और वित्तीय अपराधों की जांच करने के क्रम में लंबित पड़े कानूनी मुकदमों की जानकारी एकत्र करने के लिए व्यापक आधार वाली डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पी.सी.आर.) की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की है, उधारकर्ताओं में विलफुल डिफॉल्टर भी शामिल होंगे।
- पी.सी.आर. में बाजार नियामक सेबी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, उत्पाद एवं सेवा कर नेटवर्क, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड जैसी इकाइयों से प्राप्त डेटा भी शामिल किया जाएगा।
- यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वास्तविक समय के आधार पर मौजूदा और भावी उधारकर्ताओं की 360 डिग्री प्रोफ़ाइल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

संबंधित जानकारी

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पी.सी.आर.)

- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एक सूचना भंडार है जो व्यक्तियों और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की संपूर्ण ऋण जानकारी को एकत्र करता है।
- ऋण कोष, बैंकों की बुरे और अच्छे उधारकर्ता के बीच अंतर करने में मदद करता है और इसके आधार पर अच्छे उधारकर्ताओं को आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता है और खराब उधारकर्ताओं को उच्च ब्याज दरें प्रदान करता है।
- यह कदम वाई. एम. देओशथल्ले की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
- पी.सी.आर. सूचना असममितता, ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम करने और ग्राहकों के मध्य ऋण परंपरा को मजबूत करने जैसे मुद्दो का समाधान करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह बैंकों से शुरू होने वाली खराब ऋण की समस्याओं का भी समाधान करेगा, जैसे कि कॉर्पोरेट देनदार मौजूदा ऋण का खुलासा किए बिना बैंकों से उधार नहीं ले सकेंगे।
- पी.सी.आर., वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति को सुधारने में भी मदद करेगा।

पी.सी.आर. क्यों आवश्यक है।

- अब क्रेडिट जानकारी कई तंत्रों पर बिट्स और टुकड़ों के रूप में उपलब्ध है, न कि एक विंडो पर उपलब्ध है।
- बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड अथवा बाजार से डिबेंचरों, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफ.सी.सी.बी.), मसाला बॉन्ड और अंतर-कॉर्पोरेट उधारों से लिए गए ऋण की जानकारी, किसी एक डाटा भंडार पर उपलब्ध नहीं होगी।
- पी.सी.आर. एक ही स्थान पर विभिन्न ऋण उत्पादों पर एक उधारकर्ता के संदर्भ में संपूर्ण प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने में मदद करेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – अर्थव्यवस्था एवं विकास

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>गंगा ग्राम: ग्रामीण स्वच्छता हेतु प्रेरणास्रोत</u>**

- गंगा ग्राम, गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों को आदर्श गांवों में बदलने की अवधारणा है, गांवो को बदलने के साथ खुले में शौच मुक्त, ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज, आधुनिक शमशान, वृक्षारोपण, कार्बनिक और औषधीय पौधों को लगाने पर जोर देना है।
- गंगा ग्राम परियोजना, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना है, यह नमामि गंगे नामक गंगा सफाई अभियान के भाग के रूप में शुरू की गई है। यह परियोजना गंगा के तट पर स्थित गांवों के समग्र स्वच्छता विकास हेतु शुरू की गई है।
- अगस्त में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के

किनारे स्थित सभी 4,470 गांवों को खुला शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया है।

- इन गांवों में से केंद्र और राज्य सरकारों ने 24 गांवों को पायलट परियोजना के अंतर्गत 'गंगा ग्राम' में बदलने के लिए चिन्हित किया है।
- इन्हें 31 दिसंबर, 2018 तक गंगा ग्राम में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- चयनित गांव, स्वच्छता और विकास के एकीकृत प्रयासों के लिए बेंचमार्क स्थापित करेंगे और उन्हें 'गंगा ग्राम' में परिवर्तित किया जाएगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

4. **<u>खरीद प्रबंधक सूचकांक (पी.एम.आई.)</u>**

- खरीद प्रबंधक सूचकांक (पी.एम.आई.) डेटा दर्शाता है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों दोनों में रोजगार में वृद्धि हुई है।
- भारत अक्टूबर सेवाएं पी.एम.आई. 2 के मजबूत क्रम पर पहुंच गईं हैं।

संबंधित जानकारी

खरीद प्रबंधक सूचकांक (पी.एम.आई.)

- खरीद प्रबंधक सूचकांक (पी.एम.आई.), विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए आर्थिक स्वास्थ्य का संकेतक है।
- पी.एम.आई. का उद्देश्य कंपनी के निर्णयकर्ताओं, विश्लेषकों और क्रय प्रबंधकों को वर्तमान व्यावसायिक स्थितियों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना है।
- पी.एम.आई. को आपूर्ति प्रबंधन संस्थान (आई.एस.एम.) द्वारा मासिक रूप से संकलित और जारी किया जाता है।
- पी.एम.आई. पांच प्रमुख सर्वेक्षण क्षेत्रों: नए आदेशों, वस्तुसूची स्तर, उत्पादन, आपूर्तिकर्ता और रोजगार पर आधारित है
- इन सर्वेक्षणों में व्यावसायिक स्थितियों और किसी भी बदलाव के बारे में प्रश्न शामिल होते हैं, प्रश्नों में यह पूंछा जाता है कि वे सुधार अच्छे थे अथवा नहीं करने चाहिए अथवा बुरे थे।
- शीर्षक पी.एम.आई. में 0 से 100 तक की संख्याएं है।
- 50 से ऊपर का पी.एम.आई., पिछले महीने की तुलना में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
- 50 से कम का पी.एम.आई., कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं और 50 का पी.एम.आई. में किसी भी परिवर्तन को नहीं दर्शाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थव्यवस्था

स्रोत-लाइव मिंट

5. **<u>आयुष-स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए-एच.एम.आई.एस.)</u>**

- आयुष-स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए-एच.एम.आई.एस.), स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ई.एच.आर.) हेतु समर्पित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।
- इन प्रणालियों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी हल शामिल करने के द्वारा ए-एच.आई.एम.एस. से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
- यह सॉफ्टवेयर आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है, जिसे पूरे देश में 5 नवंबर को मनाया जाता है।

संबंधित जानकारी

आयुष मंत्रालय

- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी मंत्रालय के संक्षिप्त रूप को आयुष कहते हैं।
- यह भारत का एक सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य आयुर्वेद (भारतीय पारंपरिक चिकित्सा), योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा रिगपा (पारंपरिक तिब्बती दवा) और अन्य स्वदेशी दवा प्रणालियों का विकास, शिक्षा और अनुसंधान करना है।
- इसे मार्च, 1995 में भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी प्रणाली के विभाग (आई.एस.एम. और एच.) के रूप में स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है।

- आयुष मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष धनवंतरी जयंती (धनतेरस) के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2– स्वास्थ्य एवं नीतियां

स्रोत-पी.आई.बी.

6. **<u>दक्षिण कोरियाई प्रथम महिला: किम जंग-सूक</u>**

- किम को अयोध्या में एक पार्क के ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है, यह पार्क भारत में जन्मी कोरियाई रानी हियो-ह्वांग ओक को समर्पित है।
- अयोध्या के साथ संबंध को दक्षिण कोरिया में महत्वपूर्ण माना जाता है क्यों कि इसकी आबादी का 10% से अधिक भाग रानी हियो और राजा किम द्वारा स्थापित किए गए प्रभावशाली किम-हियो वंश से संबंधित है, कई कोरियाई लोग प्रत्येक वर्ष पर्यटक के रूप में इस पार्क में घूमने हेतु भारत आते हैं।

संबंधित जानकारी

- पौराणिक कथा के अनुसार, राजकुमारी सुरिरत्ना, जिन्हें हियो ह्वांग-ओक के नाम से भी जाना जाता है, वे 16 वर्ष की आयु में सन् 42 ईसवीं में अयोध्या से कोरियाई शहर गिमहे में गईं थीं।
- उन्होंने एक स्थानीय राजा से शादी करके करक राजवंश स्थापित किया था।
- कुछ चीनी-भाषा के ग्रंथों का दावा है कि अयोध्या के तत्कालीन राजा को एक सपना आया था जिसमें भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि वे राजा किम सूरो से विवाह करने हेतु अपनी 16 वर्षीय पुत्री को दक्षिण कोरिया भेजें।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>एन.सी.बी.एस.: चावल डोमेस्टीकेशन में छोटे आर.एन.ए. अणु को हटाना महत्वपूर्ण है।</u>**

- यह पहली रिपोर्ट है जो डोमेस्टीकेशन में गैर-कोडित आर.एन.ए. विनियामकों की भूमिका को स्पष्ट करती है।
- राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एन.सी.बी.एस.), बेंगलोर में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, चावल के डोमस्टीकेशन का छोटे आर.एन.ए. अणु (एम.आई.आर. 397) के नुकसान से पता लगाया जा सकता है।
- इन निष्कर्षों का प्रयोग भविष्य में फसलों की गुणवत्ता को सुधारने हेतु किया जा सकता है।

संबंधित जानकारी

- हजारों वर्ष पहले मनुष्य, उन वन्य पौधों की किस्मों को डोमेस्टीकेट करते थे जो फूल, फल, अनाज और दवाएं पैदा करते थे।
- ओरीजा सातिवा की उप-प्रजाति इंडिका चावल को दो जंगली प्रजातियों ओरीजा निवारा और ओरीजा रूफिपोगोन से डोमेस्टीकेट किया जाता है।
- दोनों जंगली प्रजातियों में कमजोर तनें होते हैं और जल निकायों के किनारों के पास प्रोस्टेट होते हैं।
- डोमेस्टीकेशन की प्रक्रिया में इनमें से उपयोगी विशेषताओं: मजबूत तने, बीज टूटने की अनुपस्थिति, प्रति पौधे अधिक अनाज, सुगंध, रंग इत्यादि का चयन किया जाता है।
- दो जंगली प्रजातियों का अध्ययन करने के बाद इनके बीच घरेलू उच्च उपज वाली किस्में और विभिन्न प्रकार के चावल (भूमि रेस) पाए जाते हैं।
- उन्होंने 12 को स्क्रीन्ड किया और 7 को अनुक्रमित किया- टीम ने एक छोटे आर.एन.ए. नियंत्रण लैकासेस की पहचान की और इन्हें एम.आई.आर.397 नाम दिया।
- लैकासेस, एक एंजाइम हैं जो लिगनिन के मोनोमर के बहुलीकरण में शामिल होता है, जो तने की काष्ठमयता में योगदान देता है। यदि पौधा अधिक लैकासेस उत्पन्न करता है तो पौधे में अधिक लिगनिन इकठ्ठा होगी।
- छोटे आर.एन.ए. के रूप में, एक जीन स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है और प्रोटीन बना सकता है; ये उस तरीके को नियंत्रित करते हैं जिसके माध्यम से जीन फीनोटाइप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – जैवविविधता एवं पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>परमाणु पनडुब्बी: आई.एन.एस. अरिहंत</u>**

- परमाणु पनडुब्बी आई.एन.एस. अरिहंत, देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जिसने सफलतापूर्वक अपना पहला शक्ति-संतुलन गश्त पूरा किया है।
- यह पानी के नीचे मौजूद शिकारी के रूप में माना जाता है, इसने अपने पहले लंबी दूरी के मिशन को "लाइव" परमाणु-संहित मिसाइलों के साथ सम्पन्न किया है।
- यह भारत का लंबे समय से प्रतीक्षित परमाणु त्रय है अथवा भूमि, हवा और समुद्र से परमाणु हथियारों से हमला करने की क्षमता है।
- आई.एन.एस. अरिहंत (जिसका मतलब है दुश्मनों का विनाशक), 750 कि.मी. की दूरी की K-15 मिसाइलों से सशस्त्र है, यह आकस्मिक रूप से उस समय आई थी जब एक चीनी पनडुब्बी एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र (आई.ओ.आर.) में गश्त कर रही थी।
- आई.एन.एस. अरिहंत की सफलता उन लोगों के लिए उचित प्रतिक्रिया है जो परमाणु हमले की धमकी देते हैं।

संबंधित जानकारी

आई.एन.एस. अरिहंत

- अरिहंत-वर्ग की पनडुब्बियां उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ए.टी.वी.) परियोजना के अंतर्गत निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं।
- यह भारत द्वारा डिजाइन और निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बियां होंगी।
- पनडुब्बियां, अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम ईंधन के साथ एक दबाव वाले पानी रिएक्टर द्वारा संचालित की जाती हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत- ए.आई.आर.

08.11.2018

1. भारत को फिर से आई.टी.यू. परिषद् का सदस्य चुना गया है

- भारत को वर्ष 2019 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद् (आई.टी.यू.) के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है।
- भारत एशिया-आस्ट्रेलिया क्षेत्र से चयनित होने वाले 13 देशों में तीसरे और वैश्विक रूप से परिषद् में शामिल होने वाले 48 देशों में से आठवें स्थान पर है।
- परिषद् का निर्वाचन दुबई, यू.ए.ई. में जारी आई.टी.यू. प्लेनिपोटेंशियरी सम्मेलन के दौरान हुआ था।

संबंधित जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्रसंघ (यू.एन.) की एक विशेष संस्था है।
- इसे सरकारों (सदस्य देशों) और निजी क्षेत्रों (क्षेत्रीय सदस्यों, सहयोगी एवं शैक्षिक संस्थाओं) के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत पर स्थापित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अपनी स्थापना से एक अंतर्सरकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी संगठन रहा है।
- यह सूचना एवं संचार तकनीक से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑरबिट आवंटित करता है, यह तकनीकी मापदंड तय करता है जो नेटवर्क और तकनीकों के निर्बाध रूप से अंतरसंबंध को सुनिश्चत करता है और विश्वभर में वंचित समुदायों की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तक सुलभ पहुंच के लिए प्रयत्नशील रहता है।

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में वर्तमान में 193 देश और 800 निजी-क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थाएं हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा, स्विटज़रलैंड में है।

विषय - सामान्य अध्ययन 3 – महत्वपूर्ण संस्थाएं

स्त्रोत - इकोनॉमिक टाइम्स

2. संयुक्त राष्ट्र डाक संगठन ने विशेष दिवाली स्टाम्प जारी किए हैं

- संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने दीपावली त्योहार मनाने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम शीट जारी की है।
- स्टाम्प कागज में प्रकाश की जगमगाहट और त्योहार का प्रतीक दीपक दिया गया है।

संबंधित जानकारी

- संयुक्त राज्य डाक सेवा (यू.एस.पी.एस.) ने अक्टूबर 2016 में दीपावली त्योहार मनाने के उपलक्ष्य में अक्टूबर 2016 में एक स्मरणीय स्टाम्प जारी किया था।
- दीपावली भारत सहित दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक बहुलोकप्रिय प्रकाशोत्सव है।

विषय - सामान्य अध्ययन पेपर 3 – महत्वपूर्ण संस्थान

स्त्रोत - द इंडियन एक्सप्रेस

3. गुजरात सरकार ने अहमदाबाद का नाम कर्णावती रखने का सुझाव दिया है

- गुजरात सरकार ने अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती रखने का सुझाव दिया है।

संबंधित जानकारी

- अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र में 11वीं शताब्दी से निवास किया जा रहा है जिसे उस समय अश्वल कहा जाता था।
- अन्हिलवाड़ा (आधुनिक पाटन) के चालुक्य शासक कर्णा ने अश्वल के भील राजा के विरुद्ध एक सफल युद्ध किया और साबरमती नदी के किनारे कर्णावती नामक शहर स्थापित किया।
- 1141 ईस्वीं में सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती के निकट एक किले की स्थापना की और क्षेत्र में चार संतों के नाम पर अहमद नाम से इसका नाम अहमदाबाद रखा।

विषय - सामान्य अध्ययन पेपर 2 – प्रशासन

स्त्रोत - इंडियन एक्सप्रेस

4. अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंध से छूट दी है

- ईरान में चाबहार बंदरगाह को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली है जिसमें संयुक्त समावेशी कार्य योजना (ईरान समझौता) से अमरिकी इंकार के बाद 180 दिनों की अकार्यवाही अवधि दी गयी है।
- यह छूट भारत के लिए कुछ सीमा तक राहत प्रदान करेगी, जोकि भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ मई 2016 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- भारत ईरान में चाबहार से अफगानिस्तान में हाजीगज तक रेलवे लाइन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संबंधित जानकारी

- ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास और अफगानिस्तान के लिए इससे जुड़े रेलवे के निर्माण और गैर-आंवटनयोग्य वस्तुओं की आवाजाही के सम्बद्ध में ईरान स्वतंत्रता और प्रसार-रोधी अधिनियम 2012 (आई.एफ.सी.ए.) के अधीन निश्चित प्रतिबंधों को लागू करने में छूट प्रदान की है।
- आई.एफ.सी.ए. उन नियमों में से एक है जिसके तहत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रतिबंध लगाए थे।
- आई.एफ.सी.ए. ईरान के साथ जहाजरानी, जहाजनिर्माण, ऊर्जा और बीमा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली गैर-अमेरिकी कंपनियों पर भी लागू होगा।

भारत को फ़ायदा

- चाबहार बंदरगाह भूस्थलाकृतिक अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अति बहुप्रतिक्षित संचारमार्ग प्रदान करेगा।

- चाबहार बंदरगाह के विकास में भारतीय भागीदारी से भारत को अफगानिस्तान तक एक वैकल्पिक और विश्वसनीय सुलभ मार्ग प्राप्त होगा।
- चाबहार बंदरगाह में अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए एक क्षेत्रीय परिवहन केन्द्र बनने की संभावना है।
- यह ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बेहतर बनाएगा और भारतीयों को चाबहार में मुक्त व्यापार क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के लिए किफायती ऊर्जा का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगा।

विषय - सामान्य अध्ययन पेपर 3 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्त्रोत - इकोनॉमिक टाइम्स

5. सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए दिशानिर्देश जारी किए

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.) ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए संचालन रणनीति को मंजूरी दे दी है।

रणनीति में मंत्रालय द्वारा तय किए गए उपायों की एक श्रृंखला शामिल होगी जिसमें निम्न शामिल हैं:

(I) अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपाय

- मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए नाफेड मुख्य संस्था होगी।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय निम्नलिखित दो घटकों पर छूट का 50% प्रदान करेगा:
- उत्पादन से संग्रहण तक टमाटर-प्याज-आलू (टॉप) फसलों का परिवहन।
- टॉप फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराये पर लेना;

(II) दीर्घावधि एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं

- एफ.पी.ओ. और उनके संघ की क्षमता निर्माण
- गुणवत्ता उत्पादन
- फसल उपरांत प्रसंस्करण की सुविधा
- कृषि रसद
- विपणन / खपत अंक

ऑपरेशन ग्रीन्स की पृष्ठभूमि

- टमाटर-प्याज-आलू (टॉप) फसलों की पूरे देश भर में आपूर्ति को बिना मूल्य अस्थिरता के सुनिश्चित करने के लिए 2018-19 के बजट घोषणा में ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी।

"ऑपरेशन ग्रीन्स" के उद्देश्य

- टॉप फसल उत्पादक समूहों और उनके एफ.पी.ओ. को मजबूत करने और उन्हें बाजार से जोड़ने लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा टॉप उत्पादकों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ावा देना।
- टॉप समूहों में सु-उत्पादन योजना के द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण और दोहरे उपयोग किस्मों की शुरुआत।
- फार्म गेट आधारभूत संसाधन, सतत कृषि-रसद के विकास और उपभोग केन्द्रों को जोड़ने वाली उचित संग्रहण क्षमता के निर्माण द्वारा फसल की कटाई के बाद हानि में कमी।
- फर्मों को किसानों के साथ जोड़कर टॉप मूल्य श्रृंखला में मूल्य वृद्धि और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में वृद्धि।
- मांग और आपूर्ति पर वास्तविक समय आंकड़ों को संग्रहित करने और मिलाने के लिए बाजार बुद्धिमत्ता नेटवर्क स्थापित करना।

विषय - सामान्य अध्ययन 2 – कृषि नीतियां

स्त्रोत - पी.आई.बी.

6. ओज़ोन - पृथ्वी के सुरक्षा कवच ओज़ोन में सुधार आ रहा है

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विश्व मौसम संगठन के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से समताप मंडल के हिस्से वाली ओज़ोन परत में 1-3 प्रतिशत प्रति दशक की दर से सुधार हुआ है।
- उत्तरी गोलार्ध और मध्य-अक्षांश की ओज़ोन के वर्ष 2030 तक पूरी तरह से भरने और इसके बाद 2050 के दशक तक दक्षिणी गोलार्ध और 2060 तक ध्रुवीय क्षेत्र के भरने का अंदाजा लगाया गया है।

संबंधित जानकारी

- ओज़ोन पर्त विशिष्ट प्रकार के ऑक्सीजन अणु का एक रंगहीन रूप है जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है जिसके कारण त्वचा का कैंसर, आंखों की समस्याओं और फसल क्षति जैसे जोखिम होने का खतरा है।
- क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.) प्रभावी ढंग से ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है।
- सी.एफ.सी. स्प्रे डिब्बे, फ्रिज, फोम इन्सुलेशन और एयर कंडीशनर जैसी वस्तुओं में पाई गयी थी।
- परिणामी रूप में, 1985 में दक्षिण ध्रुव पर ओजोन पर्त में एक छेद की खोज की गई।

यह कितना खराब था?

- 1990 के उत्तरार्ध में यह स्थिति बेहद चिंताजनक थी जब ऊपरी ओजोन पर्त का लगभग 10% भाग नष्ट हो गया था।
- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से यह प्रति दशक लगभग 3% की दर से बढ़ना शुरू हो गया है।

ओज़ोन पर्त की रक्षा के लिए समझौता

- एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.) सहित ओजोन-क्षरणकारी रसायनों को प्रतिबंधित या उपयोग बंद कर दिया।
- इस समझौते में 180 देशों में भाग लिया था।

विषय - सामान्य अध्ययन पेपर 3 – पर्यावरण

स्त्रोत - द हिंदू

7. डबल्यू.एफ.पी. और अलीबाबा ने भूखमरी के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया

- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और चीनी ई-कॉमर्स महानिगम अलीबाबा समूह ने 2030 तक विश्वस्तर पर भूखमरी समाप्त करने के प्रयासों का समर्थन देने के लिए रणनीतिक साझेदारी को मंजूरी दी है।
- समझौते के तहत, अलीबाबा डब्ल्यू.एफ.पी. के संचालन के डिजिटल परिवर्तन को समर्थन देने के लिए अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और संसाधनों को उधार देगा।
- अलीबाबा की क्लाउड कंप्यूटिंग शाखा डिजिटल "वर्ल्ड हंगर मैप" विकसित करने के लिए डब्लू.एफ.पी. के साथ काम करेगी।
- यह मानचित्र 2030 तक संकट को समाप्त करने के लिए वैश्विक भूख और संचालन की निगरानी करेगा।
- शून्य भूखमरी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी -2) में से एक है।

संबंधित जानकारी

विश्व खाद्य कार्यक्रम

- विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और भूखमरी को संबोधित करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है।
- 1963 में एफ.ए.ओ. और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डब्ल्यू.एफ.पी. को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था।
- डब्ल्यू.एफ.पी. का मुख्यालय रोम में है।

डब्ल्यू.एफ.पी. के उद्देश्य

- आपात स्थिति में जीवन को बचाकर रखना और आजीविका की रक्षा करना।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण में सहायता देना और संकटग्रस्त स्थितियों और उसके बाद की आपदाओं में पुर्ननिर्माण करना।
- जोखिम कम करना और लोगों, समुदायों और देशों को अपना स्वयं के भोजन और पोषण की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ बनाए रखना।
- कुपोषण घटाना और भूखमरी के अंतरपीढ़ी चक्र को तोड़ना।

विषय - सामान्य अध्ययन पेपर 2 – महत्वपूर्ण संगठन

स्त्रोत - दि हिन्दू

8. विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर 172 मिलियन डॉलर के परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- केन्द्र और आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के साथ 172.20 मिलियन डॉलर की परियोजना के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गरीब और वंचित किसानों को कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता और जलवायु लोचनीयता बढ़ाने में मदद करेगी।
- **आंध्र प्रदेश एकीकृत सिंचाई और कृषि परिवर्तन परियोजना (ए.पी.आई.आई.ए.टी.पी.)** वर्षाजल कृषि पर अधिकांश आश्रित रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाएगी।

संबंधित जानकारी

आंध्र प्रदेश द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तनशीलता ने आंध्र प्रदेश में कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जहां अधिक संख्या में मुख्यतः दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसान हैं।
- यहां किसानों द्वारा फसल की पैदावार कम है और 55 प्रतिशत से अधिक खेत वर्षाजल पर निर्भर हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट ने राज्य के कृषि प्रदर्शन को प्रभावित किया है।

ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश की कैसे मदद करती हैं?

- यह परियोजना राज्य की रणनीतिक बदलाव का समर्थन करेगी जो आंध्र प्रदेश में कृषि विकास और ग्रामीण विकास के केंद्र में जलवायु लचीलापन को रखती है।
- यह परियोजना कृषि को जलवायु-अनुशील और लाभदायक बनाने के लिए खेत स्तर पर श्रृंखलाबद्ध गतिविधियों को लागू करेगी।
- जलवायु-अनुशील बीज की किस्मों को अपनाकर, जिनकी परिपक्वता अवधि छोटी होती हैं और वे सूखारोधी और तापरोधी और लवणता सहनीय होते हैं, यह परियोजना फ़सलों को जलवायु संबंधित नुकसानों से बचाने में मदद करेगी और फलस्वरूप किसानों की आय बढ़ाएगी।

जी.एच.एस. कम करने में सहायता

- भारत का प्रति व्यक्ति हरित ग्रह गैस उत्सर्जन भी वृद्धि पर है, जबकि 2012 में वर्तमान प्रति व्यक्ति CO_2 का स्तर 44 टन है।
- देश के कुल हरित ग्रह गैस उत्सर्जन में लगभग 18 प्रतिशत के साथ कृषि क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है।
- उन्नत मृदा-जल संरक्षण और जलवायु-अनुशील खेत प्रबंधन में व्यापक रूप से भारत की जी.एच.जी. उत्सर्जन घटाने में मदद करने की संभावना है।

विषय - सामान्य अध्ययन 2 – प्रशासन

स्त्रोत - दि हिन्दू

09.11.2018

1. **उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहभागिता कार्यक्रम**

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत भारत के उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहभागिता कार्यक्रम (ए.एम.एफ.टी.सी.पी.) के सदस्य के रूप में शामिल होने के बारे में जानकारी दी गई है।
- ए.एम.एफ.टी.सी.पी., अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ढांचे के अंतर्गत काम करता है जिससे भारत को वर्ष 2017 से "संघ" का दर्जा प्राप्त है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम.ओ.पी. एंड एन.जी.) द्वारा ए.एम.एफ.टी.सी.पी. में शामिल होने का प्राथमिक लक्ष्य उत्सर्जन को कम करने और परिवहन क्षेत्र में उच्च ईंधन दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्नत मोटर ईंधन/ वैकल्पिक ईंधन के बाजार को पेश करने की सुविधा प्रदान करना है।
- ए.एम.एफ.टी.सी.पी. भी ईंधन विश्लेषण के लिए अवसर प्रदान करता है, परिवहन क्षेत्र में तैनाती के लिए नए/ वैकल्पिक ईंधन की पहचान करता है और ईंधन-केंद्रित क्षेत्रों में उत्सर्जन में कमी के लिए संबद्ध अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की सहायता करता है।

संबंधित जानकारी

- उर्जा संगम, 2015 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक ऊर्जा क्षेत्र में आयात को कम से कम 10% तक कम करना निर्देशित किया है।
- भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय जैव ईंधन-2018 नीति को अधिसूचित किया है जो 2 जी इथेनॉल, जैव-सी.एन.जी., बायोमेथेनॉल, ड्रॉप-इन

ईंधन, डी.एम.ई. इत्यादि जैसे उन्नत जैव ईंधन के क्षेत्र में आर एंड डी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है।

- इन उन्नत ईंधन को फसल अवशेषों, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट गैसों, खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के कचरे से उत्पादित किया जा सकता है।

उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहभागिता कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी-

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष 2018 में ए.एम.एफ.टी.सी.पी. में शामिल हो गई है।
- ए.एम.एफ.टी.सी.पी. के अन्य सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, चिली, इज़राइल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्पेन, कोरिया गणराज्य, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड हैं।
- ए.एम.एफ.टी.सी.पी., स्वच्छक और अधिक ऊर्जा कुशल ईंधन और वाहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच सहभागिता हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।
- ए.एम.एफ.टी.सी.पी. की गतिविधियां, उन्नत मोटर ईंधन की आर एंड डी, तैनाती और प्रसार से संबंधित हैं और उत्पादन, वितरण और अंत उपयोग संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन ईंधन के मुद्दों को व्यवस्थित तरीके से जांचती हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>मंत्रिमंडल ने दुश्मन शेयरों की बिक्री के लिए प्रक्रिया और तंत्र को निर्धारित करने की मंजूरी प्रदान की है।</u>**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुश्मन शेयरों की बिक्री के लिए तंत्र और प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की है।
- दुश्मन संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 ए, भारतीय दुश्मन संपत्ति संरक्षक (सी.ई.पी.आई.)/ गृह मामलों के मंत्रालय के संरक्षक के अंतर्गत दुश्मन शेयरों की बिक्री हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया है।
- निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग को दुश्मन संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 ए की उपधारा 7 के प्रावधानों के अतंर्गत शेयरों की बिक्री हेतु अधिकृत किया गया है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए सरकारी खाते में विनिवेश आय के रूप में बिक्री लाभ जमा किया जाना है।
- सी.ई.पी.आई. प्रमाणित करेगा कि दुश्मन शेयरों की बिक्री, किसी भी फैसले, आज्ञप्ति अथवा किसी अदालत के आदेश, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा किसी समय में लागू किया गया किसी नियम के उल्लंघन में शेयरों की बिक्री नहीं की जा सकती है और इसे सरकार द्वारा निपटाया जा सकता है।

संबंधित जानकारी

- भारत के नियमों की रक्षा, 1962 और भारत के नियमों की रक्षा, 1971 के अंतर्गत भारतीय दुश्मन संपत्ति संरक्षक (सी.ई.पी.आई.) में निहित दुश्मन संपत्ति का निरंतर निगमन प्रदान करता है।
- 1968 के अधिनियम में, "दुश्मन" की परिभाषा निम्नानुसार थी: "दुश्मन" या "दुश्मन विषय" या "दुश्मन फर्म" का अर्थ एक व्यक्ति या देश है जिसके पास एक दुश्मन, दुश्मन विषय या दुश्मन फर्म है, भारतीय रक्षा अधिनियम और नियमों के अंतर्गत कोई भी स्थिति है लेकिन इसमें भारत का नागरिक नहीं शामिल है।
- वर्ष 2017 के संशोधन में, इसे "कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी समेत" प्रतिस्थापित किया गया था, चाहे वह भारत का नागरिक हो या देश का नागरिक हो जो दुश्मन न हो या दुश्मन जिसने..... अपनी राष्ट्रीयता बदल दी हो"।

प्रभाव

- यह निर्णय, दुश्मन शेयरों के विमुद्रीकरण का नेतृत्व करेगा होगा, जो और दुश्मन संपत्ति अधिनियम 1968, लागू होने के बाद दशकों तक निष्क्रिय रहे था।

- 2017 के संशोधन के साथ दुश्मन संपत्ति के निपटारे के लिए एक सक्षम विधायी प्रावधान बनाया गया था।
- अब दुश्मन के शेयरों की बिक्री के लिए प्रक्रिया और तंत्र को मंजूरी प्रदान करने के साथ उनकी बिक्री हेतु एक सक्षम ढांचे को संस्थागत किया गया है।
- यह निर्णय दशकों से निष्क्रिय पड़े चल दुश्मन संपत्ति के मुद्रीकरण का नेतृत्व करेगा।
- इससे होने वाली बिक्री का प्रयोग विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है।

दुश्मन संपत्ति संशोधन 2017

- दुश्मन संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 ए के उपधारा 7 के अनुसा संशोधन किया गया है।
- केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि दुश्मन संपत्ति का निपटान संरक्षक के बजाय किसी अन्य प्राधिकारी या मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>विकलांग युवाओं के लिए वैश्विक आई.टी. चुनौती, 2018</u>**

- "विकलांग युवाओं के लिए वैश्विक आई.टी. चुनौती 2018", सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- भारत, कोरिया सरकार और पुनर्वास अंतर्राष्ट्रीय (आर.आई.) के सहयोग से इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है।
- अक्षमता हेतु वैश्विक आई.टी. चुनौती, एक क्षमता निर्माण परियोजना है जो विकलांग युवाओं की आई.सी.टी. तक पहुंच के माध्यम से बेहतर भविष्य हेतु अपनी सीमाओं और चुनौतियों को दूर करने में मदद करती है।
- यह डिजिटल विभाजन को कम करेगा और समाज में विकलांग युवाओं की भागीदारी का विस्तार करेगा।
- यह विकलांग व्यक्तियों (यूएनसीआरपीडी) के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन का प्रचार करता है - अनुच्छेद 21, सूचना तक पहुंच से संबंधित है।

संबंधित जानकारी

- यहां पर लगभग 1 अरब अर्थात विश्व जनसंख्या के 15 प्रतिशत लोग विकलांग हैं।
- इस आबादी का अधिकांश हिस्सा कम आई.सी.टी. विकास सूचकांक वाले विकासशील देशों में निवास करता है।
- यह प्रारंभ में विकलांग युवाओं के सूचना उपयोगिता कौशल (दृश्य विकलांगता, श्रव्य विकलांगता, लोकोमोटर विकलांगता और विकास संबंधी विकार की श्रेणी में) को बढ़ाने और उनकी सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- यह कार्यक्रम वर्ष 1992 में कोरिया में शुरू हुआ था और वर्ष 2011 से यह एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है।

टॉपिक-जी. एस. पेपर 2 –समाज के कमजोर वर्ग हेतु योजनाएं एवं कार्यक्रम

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **<u>मंत्रिमंडल ने पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने की मंजूरी प्रदान की है।</u>**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन.ओ.सी.) द्वारा पादुर, कर्नाटक में पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एस.पी.आर.) को भरने को मंजूरी प्रदान की है।
- पादुर में एस.पी.आर. सुविधा एक भूमिगत चट्टानी गुफा है जिसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) की कुल क्षमता है जिसमें चार डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे की क्षमता 0.625 एम.एम.टी. हैं।
- भारत सरकार के बजटीय समर्थन को कम करने हेतु पी.पी.पी. मॉडल के अंतर्गत एस.पी.आर. को भरा जा रहा है।

संबंधित जानकारी

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (भारत)

- भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.) ने विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर जैसे तीन स्थानों पर कुल 33 एम.एम.टी. कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत चट्टान गुफाओं का निर्माण और क्रियान्वन किया गया है।
- एस.पी.आर. कार्यक्रम के चरण-1 के अंतर्गत कुल 33 एम.एम.टी. क्षमता, वर्तमान में वित्त वर्ष 2017-18 के उपभोग डेटा के अनुसार भारत की कच्चे तेल की लगभग 95 दिनों की आपूर्ति आवश्यक्ताओं को पूरा करने का अनुमान है।
- ये सभी भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों पर स्थित हैं जो रिफाइनरियों के लिए आसानी से सुलभ हैं।
- ये रणनीतिक भंडार, तेल कंपनियों के साथ कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मौजूदा भंडार के अतिरिक्त हैं और बाहरी आपूर्ति वितरण की प्रतिक्रिया में सेवारत हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – सरकारी नीतियां

स्रोत-पी.आई.बी.

5. **<u>पृथ्वी में एक नहीं, बल्कि तीन चंद्रमा हैं।</u>**

- हंगेरियन वैज्ञानिकों के एक समूह ने दीर्घकालिक खगोलीय अटकलों की पुष्टि की है कि पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि तीन प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं।
- इसमें कहा गया है कि नया चंद्रमा पूरी तरह से एक मिलीमीटर से कम आकार के बहुत छोटे धूल कणों से मिलकर बना हैं और प्रकाश को धुंधला करने के बजाय प्रतिबिंबित करते हैं।
- यही कारण है कि उन्हें पहले स्थान में, जब वे पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की 400,000 किलोमीटर की दूरी के समान दूरी पर स्थित होते हैं तो उन्हें देखना और उनका अध्ययन करना कठिन होता है।

संबंधित जानकारी

- 1961 में, एक पोलिश वैज्ञानिक कॉजीमीर्ज कॉर्डीलेविस्की ने पहली बार इन चंद्रमाओं को देखा था और बाद में उनके नाम पर इन चंद्रमाओं का नाम कॉर्डीलेवेस्की डस्ट क्लाउड (के.डी.सी.) रखा गया था।
- कार्डोलेवेस्की ने अंतरिक्ष में एल 5 के नाम से प्रसिद्ध एक विशेष बिंदु के निकट डस्ट क्लाउड की खोज की जो पृथ्वी-चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण प्रणाली का एक लाग्रेंज बिंदु है।
- लाग्रेंज बिंदु, अंतरिक्ष में साम्यावस्था का वह स्थान हैं जहां पृथ्वी और चंद्रमा जैसे दो बड़े और ठोस खगोलीय पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्र बल को समाप्त कर देता है।
- लाग्रेंज बिंदु के आस-पास कई अन्य छोटी खगोलीय वस्तुएं पायी जाती हैं।
- उदाहरण के लिए, यहां पर सूर्य-पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली और सूर्य-बृहस्पति प्रणाली के लाग्रेंज बिंदुओं के नजदीक कई छोटे ग्रह पाए जाते हैं।
- ऐसे बिंदु पार्किंग उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष वाहनों के लिए भी आदर्श हैं क्यों कि यहां पर ईंधन की खपत अपेक्षाकृत कम होती है।
- ये स्टेशन हस्तांतरण जैसी अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं के लिए महत्वूपर्ण हैं जहां पर अन्य ग्रहों और यहां तक कि सूर्य तक की लंबी यात्राओं पर अंतरिक्ष शटल और स्टेशनों को रोक सकते हैं।
- धरती-चंद्रमा प्रणाली सहित किसी भी दो-निकाय प्रणली में स्थायित्व पहचान के ऐसे पांच बिंदु हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- डाउन टू अर्थ

6. **<u>वाराणसी में मल्टी-मॉडल टर्मिनल</u>**

- प्रधानमंत्री, वाराणसी में गंगा नदी पर एक मल्टी-मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।
- यह मल्टी-मॉडल टर्मिनल, वाराणसी में गंगा नदी पर बनाए जाने वाले तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों में से पहला है।
- केंद्र सरकार के जल मार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नदी पर कुल तीन मल्टी-मॉडल

टर्मिनलों और दो अंतर-मॉडल टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है।

- इस परियोजना का उद्देश्य सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए, विशेषकर माल के परिवहन हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना है।

संबंधित जानकारी

- यह परियोजना वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों के निर्माण की आवश्यकताओं पर जोर देती है।
- यह परियोजना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जल मार्ग विकास परियोजना तकनीकी रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है।
- कुल अनुमानित परियोजना लागत, विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा समान रूप से साझा की जा रही है।
- एम.एम.टी. के संचालन, प्रबंधन और भविष्य के विकास को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल पर एक ऑपरेटर को सौंपने का प्रस्ताव है।
- भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर के नौगम्य जलमार्ग हैं जिनमें नदियां, नहरें, बांध, खाड़ी अन्य शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **<u>आर.बी.आई. ने ढांचागत कंपनियों के लिए ई.सी.बी. मानदंडों में छूट प्रदान की है।</u>**

- रिज़र्व बैंक ने "सरकार के साथ परामर्श से" बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए विदेशी ऋण के मानदंडों में छूट प्रदान की है।
- बुनियादी ढांचा विस्तार में योग्य उधारकर्ताओं द्वारा ई.सी.बी.(बाहरी वाणिज्यिक ऋणों) के लिए बढ़ाए गए न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकताओं को पिछले पांच वर्षों से घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त अनिवार्य हेजिंग के लिए औसत परिपक्वता आवश्यकता को पिछले दस वर्षों से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।
- भारत सरकार के साथ परामर्श करके प्रावधानों की समीक्षा की गई और निर्णय लिए गए हैं।

संबंधित जानकारी

- यह कदम एक तरलता दबाव का अनुसरण करने वाली निधि की उपलब्धता और गैर-बैंक उधारदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों, विशेषकर लंबी अवधि की परिसंपत्तियों के लिए अल्पकालिक वित्त पोषण पर भारी निर्भरता के कारण संपत्ति देयता मुद्दों का समाना करने वाले गैर-बैंक उधारदाताओं से संबंधित चिंताओं के बीच उठाया गया था।
- इसने इन्फ्रा ऋणदाता आई.एल. एंड एफ.एस. द्वारा किए गए डिफॉल्टों के द्वारा क्रेडिट बाजारों को नुकसान पहुंचाया है।
- सरकार उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने में स्पष्ट है जो अर्थव्यवस्था की आवश्यक्ताओं को पूरा करेगी।
- ई.सी.बी. मानदंडों में छूट, आर.बी.आई. द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का अनुसरण करती है, जिसमें मध्यम से लंबी अवधि की निधियों को बढ़ाने के लिए एन.बी.एफ.सी. की मदद करने हेतु ऋण वृद्धि का उपयोग करने के लिए बैंको को दी जाने वाली पिछले हफ्ते की अनुमति शामिल है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

8. **<u>यू.के. इंडिया व्यापार परिषद ने नई रिपोर्ट 'बियॉड द टॉप 200' जारी की है।</u>**

- यू.के. इंडिया व्यापार परिषद की नई रिपोर्ट, 'बियॉड द टॉप 200' है।
- यह बताती है कि किस प्रकार से भारत की नई उच्च शिक्षा नीति, वैश्विक रूप से प्रदान किए गए शीर्ष पाठ्यक्रमों की अधिक उपलब्धता के माध्यम से भारतीय युवाओं को भारत में ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के द्वारा महाशक्ति बनने की ओर भारत की प्रगति को गति प्रदान कर सकती है।
- यह रिपोर्ट, फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन के उपरांत शुरू की गई थी, जो भारतीय उच्च शिक्षा में प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करती है।

- 21 वीं वैश्विक महाशक्ति बनने के पथ पर भारत को अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार करने हेतु बुद्धिमत्ता, समान पहुँच और रोजगार की अवश्यक्ता होगी।

संबंधित जानकारी

- अत: रिपोर्ट सुझाव देती है कि सभी संस्थानों को चाहें वे भारतीय या विदेशी हों, सार्वजनिक या निजी हों और रैंकिंग के निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, यह दोनों पक्षों की रियल ऐडेड वैल्यू को दर्शाता है।
- यह भारत के छात्रों, संस्थानों और नियोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करेगा।
- भारतीय उच्च शिक्षा वातावरण, एस.पी.ए.आर.सी. और जी.आई.ए.एन. जैसी पहलों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जो यू.के. इंडिया उच्च शिक्षा संबंधों को मजबूत करेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –शिक्षा संस्थान

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

10.11.2018

1. **<u>सिमबेक्स 18 – भारतीय और सिंगापुर गणराज्य की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास</u>**

- वार्षिक नौसेना युद्धाभ्यास सिमबेक्स (सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास) का 25 वां संस्करण अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है।
- वर्ष 2018 का संस्करण सिमबेक्स की रजत जयंती के रूप में आयोजित किया गया है।
- यह भारत की 'अधिनियम-पूर्वी' नीति के पूरकीकरण में मदद करेगा और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कई समझौते और उच्च स्तरीय यात्राएं सम्पन्न हुई हैं।

संबंधित जानकारी

- शंग्रिला वार्ता में भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग ने कई समझौतों का करार किया है, जिसमें 'रक्षा और रणनीतिक साझेदारी क्षेत्र के अंतर्गत समझौते भी शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>वैश्विक शीतलन नवाचार शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है।</u>**

- वैश्विक शीतलन नवाचार शिखर सम्मेलन (ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन शिखर सम्मेलन) का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकि मंत्री द्वारा किया गया है।
- यह शिखर सम्मेलन, इस प्रकार का पहला समाधान केंद्रित कार्यक्रम है जिसमें विश्व भर के विशेषज्ञ एकजुट होकर रूम कंडीशनरों की बढ़ती मांग से उत्पन्न होने वाले जलवायु खतरे से निपटने के लिए ठोस साधनों और उपायों की तलाश करेंगे।
- यह कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रॉकी माउंटेन संस्थान, एलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (एईईई), संरक्षण एक्स प्रयोगशाला और सी.ई.पी.टी. विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।
- इस शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार- मिशन नवाचार चुनौती का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ऐसे आवासीय शीतलन (कूलिंग) समाधान के विकास में तेजी लाना है जिसका आज के मानक समाधानों की तुलना में जलवायु पर कम से कम पांच गुना कम प्रभाव पड़ेगा।
- ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार, वैश्विक पहुंच और भागीदारी वाली एक प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य शीतलन प्रौद्योगिकियों के विकास में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल करना है।
- इस प्रतियोगिता का उद्देश्य एक ऐसी शीतलन तकनीकि को विकसित करना है जिसे परिचालन में लाने हेतु बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यक्ता पड़ेगी, इसमें बिना ओजोन क्षय क्षमता के शीतलकों का प्रयोग किया जाएगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>मंत्रिमंडल ने पी.पी.पी. मॉडल के अंतर्गत छह हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी प्रदान की है।</u>**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ए.ए.आई. (भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण) के छह हवाई अड्डों के प्रबंधन के निजीकरण हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है।
- ये हवाई अड्डे अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरू के हैं, इन हवाई अड्डों का सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी मूल्यांकन समिति के माध्यम से कार्यान्वन, प्रबंधन और विकास किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

- हवाई अड्डे प्रबंधन में पी.पी.पी. ने अधिक राजस्व बढ़ाने में सरकार की मदद की है और देश में कहीं पर भी बेहतर वायु संचार हेतु मॉडल का उपयोग किया है।
- यह उम्मीद है कि इस कदम से हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में अधिक विदेशी निवेश किया जाएगा।
- सरकार ने प्रक्रिया की निगरानी करने हेतु सचिवों की सशक्त समिति स्थापित की है।
- पहले से ही पी.पी.पी. मॉडल पर संचालित अन्य हवाईअड्डे दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरू, कोच्चि और हैदराबाद हैं।

अन्य पी.पी.पी. मॉडल परियोजना

- मंत्रिमंडल ने पी.पी.पी. मार्ग के माध्यम से कर्नाटक में पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने की भी मंजूरी प्रदान की है।
- मंत्रिमंडल ने चार बंदरगाहों के संघ के लिए ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सभी सरकारी शेयरों के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, इस संघ में विशाखापत्तनम बंदरगाह ट्रस्ट, पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट और कंदला बंदरगाह ट्रस्ट शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत-लाइव मिंट

4. **<u>नासा की जांच, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का दौरा करने के लिए तैयार है।</u>**

- नासा का राल्फ- एक अंतरिक्ष उपकरण है जो प्लूटो के समान दूरी तक यात्रा कर चुका है -वह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए तैयार है, जो सौर मंडल के प्रारंभिक दिनों से प्राप्त अवशेष हैं।
- पहली बार राल्फ को 2006 मीटर में न्यू होरिजन अंतरिक्ष यान के समीप लॉन्च किया गया था और इससे बृहस्पति और इसके चंद्रमाओं की शानदार तस्वीरें प्राप्त की गई थीं।
- यह दौरा प्लूटो पर जाने के बाद किया गया था, जहां पर राल्फ ने प्रतिष्ठित मामूली ग्रह की पहली हाई डेफिनिशन तस्वीरें लीं थीं।
- वर्ष 2021 में राल्फ, लूसी मिशन के साथ बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की यात्रा करने के लिए तैयार है।
- लूसी अंतरिक्ष यान, एल. राल्फ नामक राल्फ के नियर-ट्विन को ले जाता हैं,जो ब्रहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह पर जांच करेगा
- एल. राल्फ उपकरण सूट, पिंडो के विभिन्न समूहों का अध्ययन करेगा।
- लूसी, किसी अन्य पिछले क्षुद्रग्रह मिशन की तुलना से कहीं अधिक छह ट्रोजन और एक मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रह के चारों ओर उड़ेगा।
- एल. राल्फ, ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के रासायनिक फिंगरप्रिंटों का पता लगाएंगे।

संबंधित जानकारी

- एल. राल्फ, वैज्ञानिकों को सूर्य के प्रतिबिंबित प्रकाश द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की व्याख्या करने की अनुमति देता है जो विभिन्न तत्वों और यौगिकों के फिंगरप्रिंट होते हैं।
- ये आंकड़े इस बात के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं कि कार्बनिक अणु, प्राचीन निकायों में किस प्रकार बनते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के उद्भव को जन्म दे सकती है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

5. **चीन ने पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) समाचार एंकर शुरू किया है।**

- जिन्हुआ समाचार एजेंसी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के राज्य निर्देशित सम्मिलन के मध्य विश्व के पहले दो वास्तविक समाचार एंकर लॉन्च किए हैं।
- ए.आई. कृत्रिम एंकर, दो सगे चीनी समाचार प्रस्तुतकर्ताओं की बनावट पर आधारित हैं।
- कम्प्यूटरीकृत अवतार, अपने तंत्र में दर्ज किए गए शब्दों को पढ़ते हैं और उनके मुंह रिपोर्ट में प्रयुक्त शब्दों के अनुसार चलते हैं।
- "ए.आई. कृत्रिम एंकर", एक चीनी समाचार के लिए और एक अंग्रेजी समाचारों के लिए है। ये दोनों बीजिंग आधारित सर्च इंजन निर्माता और वॉयस-रिकगनीशन तकनीकि सोगो आई.एन.सी. के साथ विकसित किए गए थे।

संबंधित जानकारी

- यह डिजिटल एंकर, मनुष्यों को कुछ निश्चित फायदे प्रदान करते हैं, ये 24 घंटे काम करने में सक्षम हैं और ब्रेकिंग न्यूज को शीघ्र प्रसारित करने में सक्षम हैं।
- "ए.आई. कृत्रिम एंकर, आधिकारिक तौर पर जिन्हुआ रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा बन गया है।
- यह आपको चीनी और अंग्रेजी भाषा में आधिकारिक, समय पर सटीक समाचार और जानकारी प्रदान करने हेतु अन्य एंकरों के साथ मिलकर काम करेगा।

टॉपिक-जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

6. **मंत्रिमंडल ने मोरक्को के साथ प्रत्यर्पण समझौते को मंजूरी प्रदान की है।**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के मध्य प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसकी पुष्टि करने की मंजूरी प्रदान की है।
- यह समझौता उन भगोड़ा अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करेगा जिन पर आर्थिक अपराध, आतंकवाद, एक अनुबंध राज्य में अन्य गंभीर अपराधों का आरोप है और वे अन्य अनुबंध राज्य में पाए गए हैं।
- यह संधि भारत और मोरक्को दोनों के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूती प्रदान करेगी।

संबंधित जानकारी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के मध्य समझौते को भी मंजूरी प्रदान की है।
- भारत और मोरक्को दोनों राष्ट्र गैर-गठबंधन आंदोलन का हिस्सा हैं।
- इटली और क्रोएशिया के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था मादक द्रव्य दवाओं और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित अपराधों तक ही सीमित है।
- भारत, इटली और क्रोएशिया मादक द्रव्य दवाओं और नशीले पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ 1988 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पार्टियां हैं।

मोरक्को के संदर्भ में जानकारी-

- यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर के तट पर एक उत्तरी अफ्रीकी देश है।
- मोरक्को की राजधानी रबत है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत-पी.आई.बी.

7. **नया 'बायोनिक मशरूम' बिजली का उत्पादन कर सकता है।**

- भारतीय मूल के वैज्ञानिकों समेत कई वैज्ञानिकों ने एक बायोनिक युक्ति बनाई है जो एक सामान्य सफेद बटन मशरूम पर साइनोबैक्टेरिया के 3D-प्रिंटिंग समूहों द्वारा हरित ऊर्जा उत्पन्न करती है।
- शोधकर्ताओं ने एक किराने की दुकान से एक साधारण सफेद बटन मशरूम खरीदा और इसे बायोनिक में परिवर्तित किया, इसे सायनोबैक्टीरिया के समूहों के साथ सुपरचार्ज किया जो बिजली उत्पन्न करते है और ग्रैफीन नैनोरिबन को घुमाते है और धारा को एकत्र करते हैं।
- इसे धारा एकत्र कर सकने में सक्षम नैनोस्केल सामग्री का प्रयोग करके साइनोबैक्टीरिया को

एकीकृत करके बनाया जा सकता है जो बिजली का उत्पादन कर सकता है।

संबंधित जानकारी

साइनोबैक्टीरिया

- ये केवल ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम प्रकाशसंश्लेषित प्राकेरियोटिक जीवाणुओं का समूह हैं।
- वे विभिन्न प्रकार की नम मिट्टी और पानी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं अथवा पौधों या लाइकेन बनाने वाले कवकों के साथ संहजीवी संबंधों में पाए जाते हैं।
- साइनोबैक्टीरिया को "नीले-हरे शैवाल" भी कहा जाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>यदि यहां पर कोई परीक्षण नहीं होता है तो कोई दोहरी सजा की वकालत नहीं: सर्वोच्च न्यायालय</u>**

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि मुकदमा शुरू होने से पहले अभियोजन पक्ष के लिए अवैध मंजूरी के आधार पर एक आरोपी को आपराधिक अपराध से बरी किया गया है तो दोहरी सजा की वकालत नहीं होगी।
- 30 अक्टूबर को आयोजित की गई दो न्यायाधीशों की एक पीठ के फैसले में कहा गया था कि यदि "एक आरोपी पर अभी तक परीक्षण नहीं किया गया और तो वह दोषी हो अथवा निर्दोष हो उस पर दोहरी सजा की वकालत के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है।
- यदि अनुमोदन के एक पूर्व आदेश को अवैध पाया जात है तो सक्षम प्राधिकारी के लिए अभियोजन पक्ष के लिए मंजूरी का उचित आदेश जारी करने के लिए कोई वकील संघ नहीं है, न्यायमूर्ति भनुमाथी जिन्होंने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पीठ के फैसले को लिखा था।
- न्यायालयों को अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में त्रुटि, गलती अथवा अनियमितता के आधार पर कार्यवाही रद्द अथवा रोकनी नहीं चाहिए, जब तक कि यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि ऐसी त्रुटि, गलती या अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

संबंधित जानकारी

- यह निर्णय मिजोरम राज्य बनाम डॉ. सी. संगनघिना पर आधारित है।
- इस मुकदमें में, दोहरे खतरे के आधार पर आरोपी डा. सी. संगनघिना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दायर की गई दूसरी चार्जशीट की सुनवाई को अस्वीकार करने के लिए एक विशेष अदालत के निर्णय को कायम रखने हेतु अगस्त 2015 में गोवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ मिजोरम राज्य द्वारा एक अपील दायर की गई थी।

दोहरी सजा के संदर्भ में जानकारी-

- **दोहरी सजा** एक प्रक्रियात्मक वकालत है जो एक वैध रिहाई अथवा दोषसिद्धि का अनुसरण करते हुए एक आरोपी व्यक्ति की समान धाराओं (या समान) और समान तथ्यों पर पुन: दोषी होने से रक्षा करती है।
- संविधान का अनुच्छेद 20 (2) में शासनादेश है कि एक व्यक्ति पर समान अपराध के लिए दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता अथवा उसे समान अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – न्यायालय संबंधी

स्रोत- द हिंदू

12.11.2018

1. **<u>इसरो का संचार उपग्रह जी.एस.ए.टी.-29, जी.एस.एल.वी. एम.के. III द्वारा शीघ्र ही लांच किया जाएगा।</u>**

- जी.एस.ए.टी.-29, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित एक उच्च-प्रवाह क्षमता संचार उपग्रह है।

- यह उपग्रह जी.एस.एल.वी. एम.के. III की दूसरी विकासात्मक उड़ान के माध्यम से स्थापित किया जाएगा।
- इस उड़ान का नाम जी.एस.एल.वी. एम.के. III डी2 है।
- इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम संसाधन केंद्रों (वी.आर.सी.) को उच्च गति की बैंडविड्थ प्रदान करना है।
- के.यू. और के.ए. नाम के दो परिचालन पेलोड, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को संचार सेवाएं प्रदान करेंगे।

संबंधित जानकारी

- इसरो ने मार्च, 2018 को एक अन्य संचार उपग्रह, जी.एस.ए.टी.-6 ए लॉन्च किया था, लेकिन एक दिन बाद वह अंतरिक्ष में गुम हो गया था।
- जी.एस.ए.टी.-29 उपग्रह स्वयं में योजनाबद्ध भारतीय एच.टी.एस. चौरागों में से एक है।
- एच.टी.एस. या उच्च प्रवाह-क्षमता उपग्रहों को अत्यंत विकसित और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।
- इस श्रृंखला का पहला उपग्रह जी.एस.ए.टी.-19 है, जिसे जून, 2017 में श्री हरिकोटा से लांच किया गया था।
- इसके अतिरिक्त इसरो 20-30 छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के एक नए संस्करण एच.वाई.एस.आई.एस को लॉन्च करने के लिए पी.एस.एल.वी. मिशन की तैयारी कर रहा है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत-द हिंदू

2. **<u>ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कोणार्क सूर्य मंदिर में कलाकत्मक पत्थर नक्काशियों को साधारण पत्थरों से बदने जाने के संदर्भ में पूछताछ करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है।</u>**

संबंधित जानकारी

कोणार्क सूर्य मंदिर

- कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा के तट पर कोणार्क में 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है।
- इस मंदिर का निर्माण 1250 ईसवीं के लगभग पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था।
- यह मंदिर हिंदू भगवान "सूर्य" को समर्पित है।
- इस मंदिर का प्रमुख स्तंभ काला रंग का दिखाई देने के कारण इस मंदिर को 1676 के आरंभ में यूरोपीय नौसैनिकों के दस्तावेजों में "काला पगोडा" कहा जाता था।
- यह मंदिर, सूर्य भगवान के रथ का प्रतिनिधित्व करता है और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है।
- कोणार्क सूर्य मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा आदर्श स्मारक टैग प्रदान किया गया था।

अन्य

पूर्वी भारत के अन्य तीन स्मारकों को आदर्श स्मारक टैग प्रदान किया है-

- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हजरदुआरी पैलेस को
- बिहार में वैशाली-कोलुहा को
- असम के सिबसागर (शिवसागर) जिले में रंग घर को
- पुरी में जगन्नाथ मंदिर को "सफेद पगोडा" कहा जाता था।

टॉपिक-जी. एस. पेपर 1 – कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>पहली बार विश्व के सबसे बड़े मस्तिष्क जैसे सुपर कंप्यूटर को चालू किया गया है।</u>**

- मनुष्य के दिमाग की भांति कार्य करने हेतु डिजाइन किए गए विश्व के सबसे बड़े सुपरकंप्यूटर को पहली बार चालू किया गया है।
- नयी बनाई गई मिलियन प्रोसेसर-कोर स्पिकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर (स्पिननेकर) मशीन, प्रति सेकंड 200 मिलियन से अधिक कार्यों को पूरा कर सकने में सक्षम है।

- स्पिननेकर मशीन, यू.के. के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में डिज़ाइन और निर्मित की गई है।
- यह पृथ्वी पर किसी अन्य मशीन की तुलना में वास्तविक समय में अधिक जैविक न्यूरॉन्स का निर्माण कर सकती है।

संबंधित जानकारी

- स्पिननेकर अद्वितीय है, यह पारंपरिक कंप्यूटरों के विपरीत है क्यों कि यह मानक नेटवर्क के माध्यम से बिंदु A से बिंदु B तक बड़ी मात्रा में सूचना प्रेषित कर संवाद नहीं करती है।
- स्पिननेकर का उपयोग पृथक मस्तिष्क नेटवर्क की एक श्रृंखला में उच्च स्तरीय रियल-टाइम प्रोसेसिंग तेज करने हेतु किया गया है।
- इसमें कोर्टेक्स के एक खंड के 80,000 न्यूरॉन मॉडल शामिल है, यह मस्तिष्क की बाहरी परत है जो इंद्रियों से जानकारी प्राप्त और संसाधित करती है।
- इसके अतिरिक्त यह मस्तिष्क के एक भाग-बेसल गैंगलिया को उत्तेजित करती है, यह वह भाग है जो पारकिंसन बिमारी में प्रभावित होता है, इसका अर्थ है कि फार्मस्युटिकल परीक्षण जैसी विज्ञान में स्नायु विज्ञान संबंधी सफलताओं के लिए इसमें काफी संभावानाएं हैं।
- हाल ही में स्पिननेकर की शक्ति को स्पॉनिबोट नामक रोबोट को नियंत्रित करने में उपयोग किया गया है।
- यह रोबोट रियल-टाइम दृश्य सूचना की व्याख्या करने और अन्य को अनदेखा करते हुए निश्चित वस्तुओं का पता लगाने हेतु स्पिननेकर प्रणाली का उपयोग करता है।
- स्नायु वैज्ञानिक अब मनुष्य के मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने हेतु स्पिननेकर का प्रयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क वृहद स्तर पर सिमुलेशनों पर अभूतपूर्व तरीके से कार्य करता है।
- इसके अतिरक्त यह रियल टाइम तंत्रिका सिमुलेटर के रूप में काम करता है जो रोबोटिक्स को मोबाइल रोबोट में बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क डिजाइन करने की अनुमति प्रदान करता है जिससे कि वे लचीलेपन और कम ऊर्जा के साथ चल सकें, बात कर सकें और आगे बढ़ सकें।
- जैविक न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र में मौजूद आधारभूत मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं जो मुख्य रूप से शुद्ध विद्युत-रासायनिक ऊर्जा के 'स्पाइक्स' उत्सर्जित करके संवाद करती हैं।
- न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, मशीन में इन स्पाइक्स की नकल करने के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करता है। इन कंप्यूटर सिस्टमों में वैद्युत परिपथ होते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

4. **फ्रांस में भारतीय युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया था।**

- महान युद्ध (प्रथम विश्व युद्ध) में फ्रांस की स्वतंत्रता में भारतीय सैनिकों के योगदान को दर्शाने हेतु पेरिस में विलर्स गुसलेन में भारतीय युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया था।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए यह इस प्रकार का पहला राष्ट्रीय स्मारक है और अशोक के प्रतीक की विशेषता है।
- यह स्मारक यू.एस.आई. के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बनवाया गया था, जो न्यूवे चैपल में भारतीय स्मारक से दूर है, जिसे राष्ट्रमंडल युद्ध ग्रेव आयोग द्वारा बनवाया गया था।

संबंधित जानकारी

- 11 नवंबर, 1918 को युद्धविराम पर हस्ताक्षर करने के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था।
- भारत ने 5 मिलियन से अधिक सैनिकों का समर्थन दिया, जिनमें से 1.3 मिलियन सैनिक पूरे विश्व में विदेशों में लड़े थे और लगभग 72,000 सैनिक मारे गए थे।

- दिल्ली में इंडिया गेट "अज्ञात सैनिक" को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, इंडिया गेट पर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिको के नाम अंकित हैं।

समृति के रंग

- गेंदे का फूल पूरे भारत में देखा जाने वाला सामान्य फूल है जिसे स्मृति के एक विशिष्ट भारतीय प्रतीक के रूप में खसखस के साथ शामिल किया गया है।
- प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से यूरोप में स्मरण के प्रतीक के रूप में खसखस को अपनाया गया था।
- खसखस को स्मृति के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यों कि यह यूरोप में फ्लैंडर्स मैदानों में व्यापक रूप से उगता है, उन मैदानों में कुछ प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत-पी.आई.बी.

5. **<u>लद्दाख मरम्मत परियोजना को यूनेस्को पुरस्कार प्रदान किया गया है।</u>**

- लद्दाख में एक भव्य घर की आंशिक रूप से नष्ट हुई अवस्था की मरम्मत कर उसे सरंक्षण प्रदान करने के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- लद्दाख परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कारों के अंतर्गत अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में एल.ए.एम.ओ. केंद्र को इसकी प्रणालीगत मरम्मत परियोजना के लिए चुना गया था जिसमें मरम्मत के लिए क्षति होने के बाद बची सामग्री, स्थानीय भवन निर्माण सामग्री और स्वदेशी निर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया था, जब कि इसके वर्तमान उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आधुनिक सुख-सुविधाओं को दक्षतापूर्वक प्रस्तावित किया गया है।
- आंशिक रूप से नष्ट की अवस्था से भव्य घर में बदलने की प्रक्रिया ने लेह पुराने कस्बे के गैर-स्मारक शहरी निर्माण को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत की है।
- लेह पैलेस के नीचे रणनीतिक रूप से स्थित मरम्मतीय ढांचे 17 वीं शताब्दी में ऐतिहासिक शहरी जीवन की निरंतरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- मुंबई में, मुंबई विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित राजाबाई क्लॉक टॉवर और रत्तोनसी मुलजी जेठा की मरम्मत परियोजनाओं दोनों ही औपनिवेशिक युग से संबंधित हैं, इन्हें माननीय उल्लेख प्राप्त है।

संबंधित जानकारी

यूनेस्को एशिया प्रशांत धरोहर पुरस्कार

- यूनेस्को एशिया प्रशांत धरोहर पुरस्कार (वर्ष 2000 से) को एशिया प्रशांत क्षेत्र के भीतर यूनेस्को के रणनीतिक उद्देश्य के साथ प्रदान किया जाता है।
- इसका उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की सुरक्षा को प्रेरित करना है, जिसे निजी क्षेत्र या संस्थागत संगठन के अंतर्गत किसी भी व्यक्तिगत संगठन द्वारा शुरू किया जाता है।

इस पुरस्कार में पांच श्रेणियां शामिल हैं।

- अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस
- अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन
- अवार्ड ऑफ मेरिट
- माननीय उल्लेख
- विरासत संदर्भ में नए डिजाइन हेतु पुरस्कार

टॉपिक- जी. एस. पेपर 1 – कला एवं संस्कृति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

6. **<u>निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट 2018</u>**

- वार्षिक रिपोर्ट, जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में आई.वी.ए.सी. (अंतर्राष्ट्रीय टीका पहुँच केंद्र) द्वारा जारी की जाती है।
- यह 15 देशों में निमोनिया और डायरिया से लड़ने के प्रयासों को दर्शाता है, इन देशों में इन बीमारियों से सबसे अधिक मौतें होती हैं।

- भारत के अतिरिक्त अन्य देश नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डी.आर.सी.), इथोपिया, चाड, अंगोला, सोमालिया, इंडोनेशिया, तंजानिया, चीन, नाइजर, बांग्लादेश, युगांडा और कोट डी' इवोरी हैं।
- यह पाया गया कि पूरे भारत में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में सुधार होने के बावजूद ग्रामीण और गरीब शहरी इलाकों में पांच साल से कम उम्र की लड़कियां अभी भी निरंतर रूप से टीकाकरण से वंचित हैं।
- भारत में, पांच वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में 40 मौतें है, जब कि लड़कों के लिए बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में 39 मौतें है।
- आई.वी.ए.सी. रिपोर्ट यह भी विश्लेषण करती है कि न्यूमोनिया और डायरिया को रोकने और उसका इलाज करने के लिए विशेष रूप से स्तनपान, टीकाकरण, देखभाल और एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुँच, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और जिंक सप्लीमेंट के उपयोग सहित 10 प्रमुख हस्तक्षेपों के उपयोग को देश किस प्रकार से प्रभावी ढंग से वितरित अथावा सुनिश्चित कर रहे हैं।
- इन बीमारियों के कारण बच्चों को मौत से बचाने में मदद करने के लिए उपाय ज्ञात हैं और यह उपाय वर्ष 2030 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों में 25 मृत्यु करने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

टॉपिक-जी. एस. पेपर -2-स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **<u>क्या प्वाइंट कैलिमियर वन्यजीव अभयारण्य, प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित है?</u>**

- हाल ही में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (यू.एस.ई.पी.ए.) ने जांच की है कि प्वाइंट कैलिमियर वन्यजीव अभयारण्य में पानी की गुणवत्ता सामूहिक रूप से पक्षियों के पालन और प्रजनन हेतु असुरक्षित है।
- पी.एच. और पानी की लवणता पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अनुमत सीमा से अधिक हो गई है।
- यह प्रवासी पक्षियों के लिए खतरा पैदा करेगा।
- हालां कि यह एक संरक्षित क्षेत्र है और एक रामसर साइट है, आद्रभूमि के आसपास रासायन कंपनियों और छोटे स्तर के झींगा फार्मों ने अभयारण्य की जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के प्रति खतरा पैदा करना शुरू कर दिया है।

संबंधित जानकारी

प्वाइंट कैलिमियर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य

- यह वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में स्थित है।
- इस अभ्यारण्य में रूके हुए पानी के आसपास रेतीले तट, खारे दलदल और कांटेदार झाड़ियों के जंगल हैं।
- यह अभयारण्य 1967 में भारत की एक स्थानिक स्तनधारी लुप्तप्राय प्रजाति, काले हिरण के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था।
- यह पानी के पक्षियों के बड़े समूहों, विशेष रूप ग्रेटर फ्लैमिंगो के लिए प्रसिद्ध है।
- यह आई.यू.सी.एन. श्रेणी IV (आवास/ प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र) और एक रामसर आद्रभूमि भी है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण एवं जैव विविधता

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>ए.डी.बी. ने देश में कुशल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ई.ई.एस.एल. को $ 13 मिलियन का अनुदान दिया है।</u>**

- एशियाई विकास बैंक और ऊर्जा दक्षता सेवाओं ने ऊर्जा दक्षता परिक्रामी निधि (एनर्जी एफिशिएंट रिवॉल्विंग फंड) की स्थापना के लिए 13 मिलियन अमरीकी डालर देने हेतु वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ई.ई.आर.एफ. का उद्देश्य भारत में ऊर्जा दक्षता बाजार में निवेश का विस्तार करना और उसे सतत बनाए रखना, बाजार विविधीकरण का निर्माण करना और मौजूदा प्रौद्योगिकियों को उचित अनुपात में बढ़ाना है।
- ए.डी.बी. निधिकरण, नई प्रौद्योगिकियों और अपने आत्मनिर्भर व्यापार मॉडल की खोज करने के दौरान नगरपालिकाओं के साथ प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल.ई.डी.) स्ट्रीट-लाइट जैसे स्थापित ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए ई.ई.एस.एल. वित्त ऊर्जा सेवा उपयोगिताओं की सहायता कर रही है।
- यह उस परियोजना के समग्र उद्देश्यों का समर्थन करेगी जो सरकार के राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के लक्ष्यों से संबंधित है।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के लिए बाजार का विस्तार करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

संबंधित जानकारी

ई.ई.एस.एल. के संदर्भ में जानकारी-

- ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत है।
- यह ऊर्जा दक्षता की मुख्य दिशा में काम कर रहा है और देश में दुनिया के सबसे बड़ी ऊर्जा दक्षता संविभाग को कार्यान्वित कर रहा है।
- ई.ई.एस.एल. ने ब्रिटेन, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने परिचालन शुरू कर दिए हैं।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility)

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जी.ई.एफ.) की स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हमारे ग्रह की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी।
- जी.ई.एफ., राष्ट्रीय सतत विकास पहलों का समर्थन करते समय वैश्विक पर्यावरण मुद्दों का पता लगाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सिविल सोसाइटी संगठनों (सी.एस.ओ.) और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में 183 देशों को एकजुट करता है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मेलनों के लिए जी.ई.एफ. वित्तीय तंत्र के रूप में भी कार्य करता है:

- जैव विविधता पर सी.बी.डी. सम्मेलन।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.)।
- मरूस्थलीकरण सेनिपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.सी.डी.)।
- निरंतर कार्बनिक प्रदूषक (पी.ओ.पी.) पर स्टॉकहोम सम्मेलन।
- पारे पर मिनमाता सम्मेलन।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – महत्वूपर्ण संस्थान

स्रोत- पी.आई.बी.

13.11.2018

1. **समुद्र शक्ति- 2018**

- समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग का विस्तार करना, अंतरकार्यकारिता को बढ़ाना और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का विनिमय करना है।
- वर्ष 2018 का संस्करण इंडोनेशिया में सुराबाया बंदरगाह पर आयोजित किया गया है।

संबंधित जानकारी

- 18 मई को भारत के प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' में परिवर्तित कर दिया गया था और इस साझेदारी में रक्षा सहयोग एक महत्वूपूर्ण स्तंभ रहा है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>आई.ओ.एन.एस. की 10वीं वर्षगांठ</u>**

- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आई.ओ.एन.एस.) की 10वीं वर्षगांठ स्मरणीय गतिविधियां कोच्चि में आयोजित की गई थी।
- आई.ओ.एन.एस. की 10वीं वर्षगांठ संगोष्ठी की थीम "सागर" (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) है।

संबंधित जानकारी

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी

- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी को सामान्यत: आई.ओ.एन.एस. के नाम से जाना जाता है, यह वर्ष 2008 में भारत द्वारा शुरू की गई हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राष्ट्रों के मध्य आयोजित की जाने वाली द्विवार्षिक बैठकों की एक श्रृंखला है।
- यह समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए और सदस्य राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

भूमिका

- आई.ओ.एन.एस., हिंद महासागर क्षेत्र के लिए निर्माण की गई एक सुरक्षा है जो पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी के समान है।
- यह सदस्य राष्ट्रों की नौसेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के मध्य एक स्वैच्छिक पहल है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>मधुमेह के दुर्लभ प्रकार का अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया गया है।</u>**

- देश भर में मोनोजेनिक मधुमेह के मामलों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय मोनोजेनिक मधुमेह अध्ययन समूह का गठन किया गया है।
- यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.), मद्रास मधुमेह अनुसंधान संस्थान (एम.डी.आर.एफ.) और डॉ. मोहन के डायबिटीज स्पेशलिटीज सेंटर (डी.एम.डी.एस.सी.) द्वारा समर्थन प्राप्त है, यह अध्ययन समूह के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र होगा।
- एम.डी.आर.एफ. के साथ राष्ट्रीय मोनोजेनिक मधुमेह अध्ययन समूह का प्रधान केंद्र के रूप में गठन किया गया है।

संबंधित जानकारी

- मोनोजेनिक मधुमेह, विकारों का एक समूह है जहां एक जीन का परिवर्तन मधुमेह का कारण बनता है।
- तीन सबसे सामान्य रूप - मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग (एम.ओ.डी.वाई.), निओनैटल डायबिटीज मेलिटस (एन.डी.एम.) और जन्मजात हाइपोग्लाईसीमिया (अल्पशर्करारक्तता) हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **<u>भारतीय सेना ने तीन प्रमुख तोप प्रणालियों को प्रतिष्ठापित किया है।</u>**

- भारतीय सेना द्वारा स्वीडिश निर्मित बोफोर्स होवित्जर्स को शामिल करने के बाद यह पहला प्रमुख प्रतिष्ठापन है।
- भारतीय सेना को तीन प्रमुख तोप प्रणालियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें M777 A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स, K-9 वज्र स्व-चालित प्रॉपेल्ड तोप और "समग्र गन टोइंग वाहन" शामिल हैं।

संबंधित जानकारी

- 155 मि.मी., 39 कैलिबर अल्ट्रा-लाइट होवित्जर्स को अमेरिका से सरकार से सरकार विदेश सैन्य बिक्री के अतंर्गत प्राप्त किया गया है और यह भारत में महिंद्रा डिफेंस के साथ साझेदारी में बी.ए.ई. प्रणाली द्वारा संकलित की जाएंगी।
- एम 777 तोपें, 24-40 कि.मी. सीमा के भीतर किसी भी लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होंगी।
- सीमा युद्धों में तोपखाने का एक बड़ा महत्व है, विशेषत: पहाड़ी क्षेत्रों की सीमाओं पर होने वाले युद्धों में तोपखानों का बहुत महत्व है, पहाड़ी क्षेत्रों पर हम पाकिस्तान और चीन दोनों देशों से सीमाएं साझा करते हैं।

- प्रथम 10 K9 वज्र 155 मि.मी./52 कैलिबर तोपें दक्षिण कोरिया के हनवा टेकविन से आधे गिरे राज्यों में आयात की गई हैं और भारत में एल. एंड टी. द्वारा संकलित की गई हैं।
- शेष 90 तोपें, दक्षिण कोरिया से आने वाली कुछ प्रमुख असेंबलीज के साथ भारत में बड़े पैमाने पर निर्मित की जाएंगी।
- 6×6 फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर, अशोक लेलैंड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हैं और तोपखाने टोइंग वाहनों के पुराने बेड़े के लिए बहु-प्रतीक्षित प्रतिस्थापन प्रदान करेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. **<u>बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान: नई मसौदा नीति ने पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को कम किया है।</u>**

- केंद्र द्वारा बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान (बी.एन.पी.) के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.जेड.) की मसौदा पुन: अधिसूचना ने ई.एस.जेड. क्षेत्र को पहले के 268.96 वर्ग कि.मी. से घटाकर 168.84 वर्ग कि.मी. कर दिया है।
- नए मसौदे में कहा गया है कि ई.एस.जेड. के अंतर्गत पहले के 147 गांवों की अपेक्षा अब केवल 77 गांव रखे जाएंगे।

संबंधित जानकारी

- बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान बैंगलोर, कर्नाटक के निकट स्थित है।
- बन्नेरघाटा जैविक उद्यान, जिसे बी.बी.पी. के नाम से जाना जाता है, वह बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान का अभिन्न अंग है और वर्ष 2002 के दौरान एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान के रूप में उभरा है।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अथवा पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्र भारत सरकार के पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आस-पास के क्षेत्र हैं।
- ई.एस.जेड. घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करकें संरक्षित क्षेत्रों में किसी प्रकार के "शॉक अब्जार्वर" का निर्माण करना है।
- वे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से निम्न सुरक्षा वाले क्षेत्रों में एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>पलाऊ, प्रवाल भित्तियों को बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है।</u>**

- पलाऊ का पश्चिमी प्रशांत राष्ट्र कई प्रकार के सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, यह कदम अपनी प्रवाल भित्तियों को रसायनों से होने वाले गंभीर नुकसानों से बचाने हेतु लिया गया है।
- सनस्क्रीन से निकलने वाले रसायन जो तैराकों द्वारा पानी में धुलने से अथवा सीवर प्रणाली के माध्यम से महासागर में प्रवेश करते हैं, वे इन प्रवाल भित्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं।
- वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के बाद पलाऊ सरकार ने यह कदम उठाया था, रिपोर्ट में कहा गया था कि जेलीफिश झील में सनस्क्रीन उत्पाद "व्यापक" रूप से पाए गए हैं, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल देश का एक स्थल है।

संबंधित जानकारी

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि पानी में सनस्क्रीन की कम सांद्रता भी युवा प्रवाल के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- अध्ययनों से यह भी पता चला है कि सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायन क्षेत्रीय प्रवाल विरंजन का कारण बन सकते हैं और अपनी हार्मोन प्रणाली में हस्तक्षेप किए बिना मछली के प्रजनन को बाधित कर सकते हैं।
- वर्ष 2015 के अध्ययन में पाया गया है कि सनस्क्रीन में ऑक्सीबेन्जोन, प्रवाल वृद्धि को रोकता है और प्रवाल के भीतर रहने वाले शैवालों के लिए विषाक्त होता है।

प्रवाल भित्ति

- एक प्रवाल भित्ति, पानी के नीचे स्थित पारिस्थितिक तंत्र है जिसकी विशेषता भित्ति निर्मित प्रवाल हैं।
- भित्तियां, कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा आयोजित प्रवाल जंतुओं की कॉलोनियों से बनती हैं।
- अधिकांश प्रवाल भित्तियां, जिनके जंतु गुच्छे, समूहों में रहते हैं।
- इन्हें प्राय: "समुद्र के वर्षावन" कहा जाता है, छिछली प्रवाल भित्तियां पृथ्वी के कुछ सबसे विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करती हैं।
- वे विश्व के महासागर क्षेत्र के 0.1% से कम भाग पर हैं, लगभग फ्रांस का आधा क्षेत्र है जो सभी समुद्री प्रजातियों के कम से कम 25% को निवास प्रदान करते हैं।
- वे सामान्यत: उष्णकटिबंधीय पानी में छिछली गहराई में पाए जाते हैं, लेकिन गहरे पानी और ठंडे पानी की प्रवाल भित्तियां अन्य क्षेत्रों में छोटे पैमानों पर पायी जाती हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>भारत, वैश्विक आर.टी.आई. रेटिंग में नीचे आ गया है।</u>**

- इस वैश्विक आर.टी.आई. की स्थापना एक्सेस इन्फो यूरोप के साथ कनाडा आधारित गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी (सी.एल.डी.) के द्वारा की गई है।
- भारत अपने दूसरे स्थान (2011) से खिसककर वर्ष 2016, 2017 और 2018 में क्रमश: चौथे, पांचवे और छठवें स्थान पर आ गया है।
- रेटिंग एजेंसियों के अनुसार भारत ने कुल 150 अंकों में से 128 अंक प्राप्त किए हैं।
- यहां पर 61 संकेतकों में से नौ संकेतक श्रेणियां हैं जिनके अंतर्गत भारत के अंक कम हो गए हैं।
- भारत का स्थान, अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों की तुलना में कम है, जिन्होंने भारत के बाद आर.टी.आई. को अपनाया था।
- सी.एल.डी. के अनुसार, वैश्विक आर.टी.आई. रेटिंग, किसी दिए गए देश में सूचना के अधिकार की गारंटी प्रदान करने हेतु कानूनी ढांचे की क्षमता का आकलन करने हेतु एक प्रणाली है।
- हालां कि यह केवल कानूनी ढांचे को मापने तक ही सीमित है और यह कार्यान्वयन की गुणवत्ता का आकलन नहीं करती है।

संबंधित जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.), नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है और यह भूतपूर्व सूचना अधिनियम, 2002 की स्वतंत्रता को प्रतिस्थापित करता है।
- अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, भारत का कोई भी नागरिक "सार्वजनिक प्राधिकरण" (सरकार का एक निकाय अथवा "राज्य का माध्यम") से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसका शीघ्रता से अथवा तीस दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार और सक्रिय रूप से जानकारी की निश्चित श्रेणियों के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता होती है जिससे कि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के अनुरोध हेतु न्यूनतम साधनों की आवश्यकता पड़े।
- भारत में सूचना प्रकटीकरण को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 और विभिन्न अन्य विशेष कानूनों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, जिससे नए आर.टी.आई. अधिनियम ने राहत प्रदान की है।
- सूचना का अधिकार, भारत के नागरिकों के एक मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध करता है।
- आर.टी.आई. बहुत उपयोगी साबित हुआ है लेकिन व्हिस्टलब्लोवर अधिनियम द्वारा इसे प्रभावहीन किया गया है।
- इसे जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया जाएगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. **<u>ओडिशा में लुप्तप्राय अश्वनाल केकड़ों को संरक्षित किया गया है।</u>**

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग पिछले दो वर्षों से इन लुप्तप्राय अश्वनाल केकड़ों को समुद्र में विलुप्त होने से बचा रहा है।
- यह ओडिशा के बालासोर में स्थित फकीर मोहन विश्वविद्यालय में जनवरी, 2017 में शुरू किए गए अश्वनाल परियोजना के समुद्री पशुपालन के अंतर्गत किया जा रहा है।
- इस परियोजना में ओडिशा तट के किनारे अश्वनाल केकड़ों की घटती हुई आबादी को बहाल करने हेतु पुनर्विक्रय, उनके भंडारण में वृद्धि करने और समुद्री पशुपालन हेतु नई एक्वाकल्चर तकनीक शुरू की गई है।

संबंधित जानकारी

- अश्वनल केकड़े, तटों पर भारी संख्या में पाए जाते थे, इनकी प्रजातियों की उपस्थिति अब बलरामगाड़ी, चांदीपुर तट, बालासोर जिले के खांडिया नदीघर, केंद्रपारा जिले में ईकाकाकुला, मदाली और हुकिटोला तट तक ही सीमित हो गई है।
- फार्मास्युटिकल, नैदानिक और खाद्य उद्योगों में इस प्रजाति के औषधीय मूल्यों के कारण इस प्रजाति को बचाने हेतु कई सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियां और मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब जैसे देश ओडिशा की मदद कर रहे हैं।

जनसंख्या में कमी के कारण

- विभिन्न व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अश्वनाल केकड़ों के अविचारपूर्ण शोषण के परिणामस्वरूप पिछले दशकों में इस जीव की जनसंख्या वैश्विक गिरावट आई है।
- इनकी जनसंख्या में कमी के प्रमुख कारणों में से "प्रजनन आधारों के पर्यावरणीय पतन और विनाश भी हैं।
- केकड़े के आर्थिक महत्व के संदर्भ में स्थानीय मछुआरों को जानकारी न होने और तट के किनारे अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियां भी इनकी आबादी में कमी के प्रमुख कारणों में से एक है।

अश्वनाल केकड़े के संदर्भ में जानकारी

- अश्वनाल केकड़ा एक 'जीवित जीवाश्म' रूप है जो इस प्रजाति के लिए लगभग एकसमान है जो 230 मिलियन वर्ष पहले त्रैसिक काल के दौरान मौजूद थी।
- इस प्राचीन प्रजातियों की एक अनूठी और दिलचस्प विशेषता यह है कि इसका रक्त नीला तांबा आधारित है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – जैवविविधता

स्रोत- डाउन टू अर्थ

14.11.2018

1. **<u>एच.आर.डी. मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संकाय के लिए एल.ई.ए.पी. और ए.आर.पी.आई.टी. शुरू की है।</u>**

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में दो नई पहलों- लीडरशिप फॉर अकादमिशियन प्रोग्राम (एल.ई.ए.पी.) और वार्षिक शैक्षणिक रिफ्रेशर कार्यक्रम (ए.आर.पी.आई.टी.) की शुरुआत की है।
- ये पहलें, शिक्षण की गुणवत्ता को बदलने और नेताओं में सुधार करने के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करती हैं।

संबंधित जानकारी

लीडरशिप फॉर अकामिदिशियन प्रोग्राम (एल.ई.ए.पी.)

- लीडरशिप फॉर अकामिदिशियन प्रोग्राम (एल.ई.ए.पी.) सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में दूसरे स्तर के शैक्षणिक पदाधिकारियों के लिए तीन सप्ताह का प्रमुख नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे स्तर के अकादमिक प्रमुखों तैयार करना है जो संभावित रूप से भविष्य में नेतृत्व की भूमिका निभाने की संभावना रखते हैं।
- यह कार्यक्रम उच्च अकादमिक प्रमाण-पत्र, आवश्यक नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल के साथ

वरिष्ठ संकाय प्रदान करेगा जिसमें समस्या सुलझाने के कौशल शामिल हैं।

- एल.ई.ए.पी. कार्यक्रम का कार्यान्वयन 15 एन.आई.आर.एफ. शीर्ष रैंक वाले भारतीय संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा।

वार्षिक शैक्षणिक रिफ्रेशर कार्यक्रम (ए.आर.पी.आई.टी.)

- वार्षिक शैक्षणिक रिफ्रेशर कार्यक्रम (ए.आर.पी.आई.टी.), एम.ओ.ओ.सी. मंच स्वयं का उपयोग करके 15 लाख उच्च शिक्षा संकायों के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास की एक प्रमुख और अनूठी पहल है।
- राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एन.आर.सी.), ए.आर.पी.आई.टी. की कार्यान्वयन संस्था है जिनका कार्य अनुशासन में रहकर नवीनतम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना और संशोधित पाठ्यक्रम के विनिमय हेतु नए और विकासात्मक बदलाव, संज्ञानात्मक सुधारों और तरीकों को पेश करना है।
- प्रशिक्षण सामग्री, स्वयं के माध्यम से अपलोड और उपलब्ध कराया जाएगा।

स्वयं लर्निंग पोर्टल

- एस.डब्ल्यू.ए.वाई.ए.एम. (स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स), माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एक मंच है।
- इस प्रयास का उद्देश्य सबसे वंचितों को शामिल करते हुए सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण-अधिगम संसाधनों को उपलब्ध कराना है।
- स्वयं, उन छात्रों के लिए डिजिटल अंतरों को दूर करना चाहता है जिन्होंने अब तक डिजिटल क्रांति से परिचित नहीं है और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा को जोड़ने में सक्षम नहीं हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – शैक्षणिक

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>इंद्रा- 2018</u>**

- इंद्रा, भारत और रूस के मध्य एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है।
- यह संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के संरक्षण के अंतर्गत बबीना में हो रहे विद्रोह का मुकाबला कर रहा है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य संयुक्त नीतियों का अभ्यास करना और संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण के अंतर्गत शांति व्यवस्था /प्रवर्तन पर्यावरण में दोनों सेनाओं की अंतरकार्यकारिता को बढ़ाना है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>नासा अंतरिक्ष में ऑर्गन्स-ऑन-चिप भेजने के लिए तैयार है।</u>**

- नासा मानव कोशिकाएं रखने वाली छोटी युक्तियों को ऊतक चिप अथवा ऑर्गन्स-ऑन-चिप के नाम प्रचलित 3D मैट्रिक्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आई.एस.एस.) में भेजने की योजना बना रहा है।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एन.आई.एच.) में सी.ए.एस.आई.एस. और नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसलेशन साइंसेज (एन.सी.ए.टी.एस.) के सहयोग से जांच करने की योजना बना रही है।
- यह इसका परीक्षण करने में मदद करेगा कि वे तनाव, दवाओं और अनुवांशिक परिवर्तनों के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं।
- यह चिप लचीली प्लास्टिक से बने होते हैं और उनके भीतर रखी कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करने हेतु पोर्ट और चैनल होते हैं।
- "अंतरिक्ष में ऊतक चिप", मानव स्वास्थ्य एवं बीमारी पर माइक्रो गुरूत्वाकर्षण की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने और उस समझ को पृथ्वी पर स्थित बेहतर मानव स्वास्थ्य में बदलने हेतु एक पहल प्रतीत होती है।

संबंधित जानकारी

- अंतरिक्ष में ऊतक चिप के पहले चरण में पांच जांचे शामिल हैं।

- प्रतिरोधक तंत्र की आयु की जांच को स्पेस एक्स. सी.आर.एस.-16 उड़ान पर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
- अन्य चार को स्पेस एक्स. सी.आर.एस.-17 अथवा बाद की उड़ानों पर शुरू करना निर्धारित हैं, इनमें लंग होस्ट डिफेंस, रक्त-मस्तिष्क बाधा, पेशीय बीमारियां और गुर्दे के कार्यों पर जांचें शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **<u>ट्विटर इंडिया ने #पावरऑफ 18 लांच किया है।</u>**

- ट्विटर, #पावरऑफ 18 नामक एक सामाजिक पहल शुरू कर रहा है।
- इस अभियान के शुरू होने को #पॉवरऑफ 18 हैशटैग द्वारा एक्टिव इमोजी द्वारा चिह्नित किया जाता है।
- इस पहल का उद्देश्य निकट भविष्य में आने वाले चुनाव सत्र 2019 में सार्वजनिक बहस में योगदान दने हेतु और नागरिक कार्यकारिणी में भागीदारी हेतु भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करना था।

संबंधित जानकारी

ट्विटर

- ट्विटर एक अमेरिकी ऑनलाइन समाचार और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर उपयोगकर्ता "ट्वीट्स" के नाम से प्रचलित संदेशों को पोस्ट करते हैं और उन पर संवाद करते हैं।
- ट्विटर, मार्च 2006 में जैक डोरसे, नोह ग्लास, बिज़ स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

5. **<u>इसरो ने 2023 शुक्र मिशन के लिए विदेशी प्रयोगों को आमंत्रित किया है।</u>**

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अवसर की घोषणा (ए.ओ.) जारी करके शुक्र पर अपने मध्य 2023 नियोजित मिशन की ओर पहला कदम बढ़ाया है।
- ए.ओ., अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय को मिशन पर ले जाने वाले अपने वैज्ञानिक पेलोडों का प्रस्ताव देने हेतु जारी किया गया है।
- शुक्र का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष-आधारित प्रयोगों के लिए यह ए.ओ. विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए खुले हैं।
- ए.ओ. का विशिष्ट उद्देश्य उन महत्वपूर्ण विज्ञान प्रयोगों की पहचान करना है जो इसरो के शुक्र मिशन पर भारत से पूर्व-चयनित प्रस्तावों के समूह से समग्र विज्ञान को मजबूत/ पूर्ण करता हैं।"

संबंधित जानकारी

शुक्रयान-1

- शुक्रयान-1 (शुक्र कला) वीनस की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा शुक्र हेतु प्रस्तावित एक कक्षा है।
- इसरो द्वारा लांच किए जाने वाले प्रस्तावित उपग्रह की पेलोड क्षमता लगभग 500W बिजली के साथ 100 किलोग्राम होने की संभावना है।
- वर्ष 2016-17 में रेडियो प्रच्छादन प्रयोग में वीनस ऑर्बिटर मिशन से प्राप्त सिग्नलों का प्रयोग करते हुए शुक्र के वातावरण का अध्ययन करने हेतु इसरो ने जाक्सा के साथ मिलकर काम किया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – अंतरिक्ष कार्यक्रम

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>डब्ल्यू.ई.एफ. ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की तीसरी वार्षिक बैठक दुबई में शुरू हुई है।</u>**

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) की ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की तीसरी वार्षिक बैठक दुबई, यू.ए.ई. में सम्पन्न हुई है।
- वार्षिक बैठक की थीम **वैश्वीकरण 0: चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तुकला को आकार देना** था।

- इसका उद्देश्य तकनीकी व्यवधानों की विशाल लहर के लिए की जाने वाली तैयारियों का पता लगाना है जो चौथी औद्योगिक क्रांति के साथ आएंगी।

संबंधित जानकारी

ग्लेबल फ्यूचर काउंसिल

- ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल, 38 विशिष्ट परिषदों का एक नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक परिषद साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, शासन, नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और जल, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वाणिज्य और निवेश जैसे भविष्य के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इस बैठक का परिणाम, स्विट्जरलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में होने वाली विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2019 के साथ ही मंच की वर्तमान में चल रही वैश्विक पहलों के लिए एजेंडे को निर्धारित करेगा।

विश्व आर्थिक मंच

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) की स्थापना वर्ष 1971 में स्विटजरलैंडड के कोलोगनी-जिनेवा में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी।
- इस संगठन का आदर्श वाक्य: दुनिया की स्थिति में सुधार करने हेतु प्रतिबद्धता है।
- इस संगठन के अध्यक्ष बोर्जब्रेंडे हैं।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट (जी.सी.आर.)
- यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट
- वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट
- सक्षम व्यापार रिपोर्ट
- वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
- मानव पूंजी सूचकांक
- वैश्विक लिंगांतर सूचकांक

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- ए.आई.आर.

7. **<u>बैंगनी जीवाणु 'बैटरियां' मल को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करेगा।</u>**

- शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि बैंगनी फोटोट्रॉफिक जीवाणु जो प्रकाश से ऊर्जा संग्रहित करता है, जब उसे विद्युत प्रवाह के साथ आपूर्ति किया जाता है तो वह विद्युत उत्पादन हेतु हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते समय किसी भी प्रकार के कार्बनिक अपशिष्ट से लगभग 100 प्रतिशत कार्बन को पुन: प्राप्त कर सकता है।
- ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन, इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन प्रदान करने हेतु CO2 और H2O के स्थान पर कार्बनिक अणु और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करता है।
- इसका अर्थ है कि वे वैकल्पिक फोटोट्रॉफिक जीवाणु और शैवाल की अपेक्षा से तेज़ी से बढ़ते हैं और मेटॉबॉलिज्म के उत्पादों के रूप में हाइड्रोजन गैस, प्रोटीन अथवा बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर के एक प्रकार को उत्पन्न कर सकते हैं।

संबंधित जानकारी

अधिकतम जैव ईंधन, न्यूनतम कार्बन पदचिह्न

- अपने नवीनतम अध्ययन में, समूह ने बैंगनी फोटोट्रॉफिक जीवणुओं की प्रजातियों के मिश्रण के द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन को अधिकतम करने के लिए इष्टतम स्थितियों का विश्लेषण किया है।
- उन्होंने जीवाणु के मेटाबॉलिक व्यवहार पर नकारात्मक धारा- वृद्धि माध्यम में धातु इलेक्ट्रोड द्वारा आपूर्ति किए गए इलेक्टॉनों के प्रभाव का भी परीक्षण किया है।
- उनकी पहली प्रमुख खोज यह थी कि हाइड्रोजन उत्पादन की उच्चतम दर को पोषित करने वाला पोषक मिश्रण भी CO2 के उत्पादन को कम करता है।
- "यह दर्शाता है कि कम कार्बन पदचिन्हों के साथ सामान्यत: अपशिष्ट जल- मैलिक अम्ल और सोडियम ग्लूटामेट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक्स से मूल्यवान जैव ईंधन को पुन: प्राप्त करने हेतु बैंगनी जीवाणु का उपयोग किया जा सकता है।

- बैंगनी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 को ग्रहण करने हेतु एक नकारात्मक इलेक्ट्रोड अथवा "कैथोड" से इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करने में सक्षम हैं।
- बैंगनी जीवाणु द्वारा उत्पादित अतिरिक्त CO2 को ग्रहण करना न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बल्कि ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु कार्बनिक अपशिष्ट से बायोगैस की रीफाइनिंग करने में भी उपयोगी हो सकता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- साइंस डेली

8. **यू.पी. मंत्रिमंडल ने फैजाबाद को अयोध्या के रूप में नामित करने के नामकरण को मंजूरी प्रदान की है।**

- उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद और इलाहाबाद डिवीजनों का नाम बदल कर क्रमश: अयोध्या और प्रयागराज करने को मंजूरी प्रदान की है।
- इससे पहले सरकार ने एक अन्य ऐतिहासिक स्थल मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था।

संबंधित जानकारी

- सरकार ने इन "तथ्यों" के आधार पर नामकरण को उचित करार दिया है कि अयोध्या, पौराणिक "इक्ष्वाकु वंश" की राजधानी रही है और भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान है।
- अयोध्या समय के अनुसार कई राज्यों और राजवंशों की राजधानी रही है।
- दूरदराज के देशों में भी इस भूमि को अयोध्या के नाम से ही जाना जाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

9. **एमनेस्टी ने म्यांमार के आंग सान सू क्यी से अपने सर्वोच्च सम्मान को वापस लिया।**

- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आंग सान सू क्यी से अपने सर्वोच्च सम्मान को वापस ले लिया है, यह पुरस्कार इनसे रोंहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के प्रति म्यांमार के नेताओं की "उदासीनता" की वास्तविकता हेतु लिया गया है।
- यह पुरस्कार वर्ष 2009 में सू क्यी को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके शांतिपूर्ण और अहिंसक संघर्ष को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रदान किया गया था।
- म्यांमार की सेना जुंता के खिलाफ खड़े होने के प्रयासों हेतु सू क्यी को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता था।
- उन्हें 15 से अधिक वर्षों तक घर में नजरबंद किया गया था।
- उन्हें वर्ष 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –पुरस्कार एवं सम्मान

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

10. **चक्रवाती तूफान 'गाजा'**

- गाजा, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है और इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ने और आगे बढ़ने पर गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है।
- इस तूफान में 100 कि.मी. प्रति घंटे की गति से हवा के साथ भारी बारिश होगी।
- मौसम भविष्यवाणी ने अपनी चेतावनी में कहा कि यह तूफान तमिलनाडु के कई जिलों को और पुदुचेरी के कराइकाल जिले को भारी नुकसान पहुँचा सकता है।

टॉपिक जी.एस. पेपर 1- भारतीय भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

15.11.2018

1. **प्रधानमंत्री ने 2 बिलियन बैंकरहित व्यक्तियों को फिनटेक वेव में शामिल करने हेतु मंच 'ए.पी.आई.एक्स.' लॉन्च किया है।**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक फिनटेक मंच ए.पी.आई.एक्स.- एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज लॉन्च किया है।
- इस मंच का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों से कंपनियों को जोड़ना और पूरे विश्व में बिना बैंक खातों वाले दो बिलियन व्यक्तियों हेतु एक बैंकिंग समाधान बनना है।

- आसियान वित्तीय नवाचार नेटवर्क (ए.एफ.आई.एन.) ने सितंबर, 2018 में ए.पी.आई. एक्सचेंज(ए.पी.आई.एक्स.) को लांच करने की घोषणा की थी।
- इस वैश्विक संघ का नेतृत्व आई.टी. परामर्श फर्म वर्चूसा कर रही हैं, ए.पी.आई.एक्स. को विकसित और संचालित करने हेतु वर्चूसा समेत डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदाता फिडॉर और परसीपिएन्ट को चुना गया है।
- ए.पी.आई.एक्स. को वित्तीय संस्थानों (एफ.आई.) के लिए ऑनलाइन वैश्विक फिनटेक बाजार और सैंडबॉक्स मंच के रूप में बताया जाता है।
- इसे विश्व का पहला सीमा पार, ओपन-आर्किटेक्चर मंच कहा जाता है जो सक्षम करेगा:
- एफ.आई और फिनटेक कंपनियों को एक विश्व स्तर पर सुव्यवस्थित बाजार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने हेतु सक्षम बनाएगा।
- वित्तीय उद्योग प्रतिभागियों के मध्य एक सैंडबॉक्स में सहयोगी प्ररीक्षण करने में सक्षम बनाएगा।
- एशिया-प्रशांत में डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन करने हेतु ए.पी.आई. को अपनाने में सक्षम बनाएगा।

संबंधित जानकारी

ए.एफ.आई.एन. (आसियान वित्तीय नवाचार नेटवर्क)

- ए.एफ.आई.एन., आई.एफ.सी. की एक पहल है जो विश्व बैंक समूह, आसियान बैंकर संघ (ए.बी.ए.) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एम.ए.एस.) का सदस्य है।
- इसका उद्देश्य विनियमित वित्तीय संस्थानों और वित्तीय प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के मध्य परीक्षण और सहयोग का समर्थन करना है।
- "ए.एफ.आई.एन. " की प्राथमिकता एशिया प्रशांत क्षेत्र के भीतर उभरते हुए बाजारों में वित्तीय सेवा नवाचारों और समावेशों का समर्थन करना, वित्तीय संस्थानों और फिनटेक फर्मों के लिए सहयोग और नवाचार हेतु एक मंच प्रदान करना है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – वित्तीय समावेशन

स्रोत- एन.डी.टी.वी.

2. **<u>कृषि मंत्रालय ने एन.सी.डी.सी. की नई योजना की शुरूआत की है।</u>**

- "युवा सहकार- सहकारी उद्यम समर्थन एवं नवीनता" योजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा शुरू की गई है।
- सहकारी व्यापार उद्यमों की ओर आकर्षित करने हेतु युवाओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक युवा-अनुकूल योजना है।
- यह योजना एन.सी.डी.सी. द्वारा बनाए गए 1000 करोड़ रुपये के सहकारी स्टार्ट-अप और नवाचार निधि (सी.एस.आई.एफ.) से जुड़ी होगी।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, महिलाओं अथवा एस.सी. अथवा एस.टी. अथवा पी.डब्ल्यू.डी. सदस्यों वाले आकंक्षी जिलों और सहकारी समितियों को परियोजना के लिए वित्त पोषण, परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तक प्रदान किया जाएगा।
- सामान्य श्रेणी के लिए वित्त पोषण, परियोजना लागत का 70% तक सीमित होगा।
- सभी प्रकार की सहकारी समितियां संचालन में कम से कम एक वर्ष के लिए पात्र हैं।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)

- एन.सी.डी.सी. एक सांविधिक निगम है जिसे 13 मार्च, 1963 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था।
- एन.सी.डी.सी. के उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक उत्पाद, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और इससे संबद्ध अथवा इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात हेतु योजनाएं और संवर्धन कार्यक्रमों को आयोजित करना है।
- सहकारी समितियों की दुनिया में सबसे पसंदीदा वित्तीय संस्थान होने के कारण एन.सी.डी.सी. ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सहकार 22 की शुरूआत कर दी है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – सरकारी योजना

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>नीति अयोग और यूनिसेफ ने यूनिसेफ-अटल टिंकरिंग लैब हैकथॉन की शुरूआत की है।</u>**

- नीति आयोग और यूनिसेफ ने स्कूली बच्चों के लिए 72 घंटे के टिंकरिंग हैकथॉन का आयोजन किया है।
- नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.) और यूनिसेफ ने सतत विकास के प्रति योगदान देने हेतु भारत के युवा बच्चों को एक खुला मंच प्रदान करने के लिए एक साथ आए हैं।
- यूनिसेफ- अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला युवा चैंपियंस पुरस्कार, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे राष्ट्र में शुरू किए गए अटल टिंकरिंग मैराथन चैलेंज के विजेताओं को प्रदान किए गए थे।

संबंधित जानकारी

- ए.आई.एम.-अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला (ए.टी.एल.) ने छह अलग-अलग विषयगत क्षेत्रों- स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, स्मार्ट गतिशीलता और कृषि प्रौद्योगिकी में अटल टिंकरिंग मैराथन नामक एक छह महीने लंबा राष्ट्रव्यापी चैलेंज शुरू किया था।
- इसका उद्देश्य समुदाय की समस्याओं का अवलोकन करना और अभिनव समाधान विकसित करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना था।

अटल इनोवेशन मिशन

- स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोगिता (एस.ई.टी.यू.) के साथ अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.), नवाचार और उद्यमशीलता की परंपरा को संवर्धित करने हेतु भारत सरकार का प्रयास है।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय नवाचार केंद्र, बड़ी चुनौतियों, स्टार्ट-अप व्यवसाय और अन्य स्व-रोज़गार गतिविधियों के संवर्धन हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना है।

अटल इनोवेशन मिशन में दो मुख्य कार्य होंगे:

- **उद्यमिता संवर्धन**- स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोगिता के माध्यम से नवप्रवर्तनकों को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन और परामर्श देना।
- **नवाचार संवर्धन**: एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां नवीन विचार उत्पन्न होते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **<u>डी.आई.पी.पी., वैश्विक डिजिटल सामग्री बाजार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।</u>**

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वैश्विक डिजिटल सामग्री बाजार 2018 पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
- इस सम्मेलन में संगीत, फिल्म, प्रसारण और प्रकाशन के साथ ही सामूहिक प्रबंधन, उभरते हुए मॉडलों और बाजार एवं नीति निर्माताओं हेतु आश्रयों पर सत्र शामिल होंगे।
- देश में फिल्म, संगीत और मीडिया के क्षेत्र में मजबूत रचनात्मक उद्योग के कारण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा भारत को सम्मेलन के मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है।
- जी.डी.सी.एम. 2018 विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों से व्यवसायियों, पूरे विश्व के डिजिटल उद्योग और संयुक्त राष्ट्र के मिशनों से लोकतांत्रिक समुदायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी की निगरानी करेगा।
- इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य रूप से ध्यान एशिया प्रशांत क्षेत्र पर रहेगा।

संबंधित जानकारी

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
- यह विभाग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु संवर्धन और विकासात्मक उपायों के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है।
- यह देश में एफ.डी.आई. प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने हेतु जिम्मेदार है।
- इसके अतिरिक्त डी.आई.पी.पी. पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और उत्पादों के भौगोलिक संकेतों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु जिम्मेदार

है और उनके संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित पहलों की देखरेख करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. **<u>भारत, ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर शीर्ष स्थान पर आकर अमेरिका से आगे निकल जाएगा: आई.ई.ए.</u>**

- भारत, वर्ष 2030 के पहले ऊर्जा क्षेत्र से कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में अमेरिका से आगे निकल जाएगा।
- पेरिस आधारित आई.ई.ए. ने रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2040 तक भारत के ऊर्जा क्षेत्र से कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 80 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है क्यों कि एयर कंडीशनिंग द्वारा संचालित क्षेत्रों के कारण बिजली का उपयोग वर्तमान का लगभग तीन गुना हो जाएगा।
- चीन कार्बन डाइ ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक बनेगा।
- आई.ई.ए. के अनुसार, इस अवधि के दौरान भारत के दो तिहाई घरों में एयर कंडीशन होने का अनुमान है, जिससे वर्तमान की तुलना में उत्सर्जन में 15 गुना वृद्धि हो जाएगी।
- शीतलन के लिए भारत की बिजली आपूर्ति की मांग को इस अवधि की मांग से 700 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा, ऐसा माना जा रहा है कि देश की एयर कंडीशनिंग दक्षता में कोई बड़ा सुधार नहीं किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, बिजली की मांग और उत्सर्जन में गंभीर बढ़ोत्तरी के बाद भी भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत, विश्व के अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम है।

संबंधित जानकारी

- भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया संयुक्त रूप से वर्ष 2040 तक दोगुनी से अधिक मांग होने के कारण कोयले द्वारा बनाई जाने वाली बिजली के वृद्धि केंद्र हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, एक पेरिस आधारित स्वायत्त अंतरसरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1973 के तेल संकट के परिणामस्वरूप वर्ष 1974 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) की ढांचागत संरचना में की गई थी।
- आई.ई.ए. को प्रारंभ में तेल की आपूर्ति में भौतिक व्यवधानों के प्रति प्रतिक्रिया देने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों के संदर्भ में आंकड़ों पर एक सूचना स्रोत के रूप में कार्य करने हेतु समर्पित किया जाता था।
- प्रभावी ऊर्जा नीति के "3 ई": ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एजेंसी के शासनादेश का प्रसार किया गया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – ऊर्जा क्षेत्र

स्रोत-लाइवमिंट

6. **<u>सरकार, नेता जी द्वारा तिरंगा फहराने की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी करेगी।</u>**

- सरकार ने पोर्ट ब्लेयर में नेता जी सुभाषचंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराने के अवसर की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है।
- इस सिक्के पर सेलुलर जेल की पृष्ठभूमि पर तिरंगे को सलाम करते हुए 'नेताजी सुभाषचंद्र बोस' का चित्र छापा जाएगा।
- इस सिक्के पर देवनागरी लिपि और अंग्रेजी भाषा दोनों में 'प्रथम ध्वजारोहण दिवस' अभिलेखित किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

- वर्ष 1943 में, नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में जिमखाना मैदान (वर्तमान में नेताजी स्टेडियम) में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था।

- इसके अतिरिक्त उन्होंने द्वीपों (प्रथम भारतीय सीमाओं) के ब्रिटिश शासन से मुक्त होने की घोषणा की थी।
- उस समय वह द्वीप जापान द्वारा ब्रिटिश शासन से मुक्त किया गया था जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया गया था।
- बोस ने अंडमान द्वीप को शहीद और निकोबार द्वीप को स्वराज के रूप में नामित किया था।
- उन्होंने आई.एन.ए. के जनरल ए.डी. लोगानाथन को द्वीप समूह के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था।
- अब आजाद हिंद सरकार, निर्वासन में एक सरकार नहीं थी बल्कि उसकी अपनी जमीन, अपनी मुद्रा, नागरिक कोड और टिकटें थीं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एरिट्रिया के खिलाफ प्रतिबंध हटा दिए हैं।</u>**

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नौ वर्ष बाद एरिट्रिया के खिलाफ प्रतिबंध हटाने हेतु सर्वसम्मति से मतदान किया था।
- यह लक्षित प्रतिबंध दिसंबर, 2009 से प्रभावी रूप से लागू था।
- एरिट्रिया पर सोमालिया स्थित इस्लामवादी विद्रोही समूह अल-शबाब को सामग्री समर्थन प्रदान करने के साथ ही जिबूती के साथ एक अलग सीमा विवाद होने के कारण उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे।
- सोमालिया और जिबूती दोनों 2009 के संकल्प के मुखर समर्थक थे।

संबंधित जानकारी

एरिट्रिया

- एरिट्रिया- आधिकारिक रूप से एरिट्रिया राज्य, अफ्रीका के हॉर्न का एक देश है, जिसकी राजधानी असमारा है।
- यह पश्चिम में सूडान, दक्षिण में इथोपिया और दक्षिण-पूर्व में जिबूती के साथ सीमा साझा करता है।
- एरिट्रिया के उत्तर-पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों की लाल सागर के साथ एक विस्तृत तट रेखा है।

यू.एन.एस.सी. (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद)

- यू.एन.एस.सी., संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव हेतु जिम्मेदार है।
- इसमें 15 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट है। इन 15 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं।
- पांच स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्तियां होती हैं।
- 10 अस्थायी सदस्यों को एक क्षेत्रीय आधार पर दो वर्षों की अवधि हेतु सेवा करने के लिए चुना जाता है।
- यह ऐसा एक मात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जो सदस्य राज्यों को बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने के अधिकार रखता है।
- इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा को महासचिव की नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश हेतु सुझाव भी देती है।
- यू.एन.एस.सी., महासभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव भी करती है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
- संयुक्त राष्ट्र महासभा
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
- संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- बी.बी.सी. न्यूज

8. **<u>किलोग्राम की परिभाषा को बदलने की तैयारी की जा रही है।</u>**

- किलोग्राम की परिभाषा को पुन: परिभाषित करने की आवश्यक्ता है अथवा नहीं है, इस पर वोट देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वजन एवं माप महासम्मेलन की वर्सेल्स, फ्रांस में बैठक आयोजित की गई थी।
- 1879 के बाद से, किलोग्राम को "ले ग्रैंड K", प्लैटिनम और इरीडियम को बेलन का भार जो

2 पाउंड से थोड़ा अधिक होता है, के वजन के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे पेरिस में एक बंद मेहराब में रखा गया है।

- विभिन्न देशों में उनका "मूल किलोग्राम" होता है जो राष्ट्रीय मानकों के रूप में कार्य करता है और वर्ष 1875 में 17 देशों द्वारा स्थापित ली ग्रांड K द्वारा जांचा जाता है।
- हालां कि वैज्ञानिकों का कहना है कि समय के साथ प्रणाली को बदलने की आवश्यक्ता है, मूल तत्व में परमाणु खो जाते हैं और जिससे उनके भार में कमी आ जाती है क्यों कि यह "क्षति और पर्यावरणीय कारकों के प्रति अतिसंवेदनशील" होते हैं।
- वैज्ञानिक प्लांक नियतांक के आधार पर किलोग्राम की गणना को पेश कर रहे हैं, जिसे किबल तुला नामक एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, जिसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रायन किबल द्वारा लंदन की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में विकसित किया गया था।
- इस परिवर्तन के गणना, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, जलवायु परिवर्तन अध्ययन और अन्य विषयों में अनुप्रयोग होंगे जिनमें बहुत सटीक माप की आवश्यकता होती है।

संबंधित जानकारी

- वैज्ञानिकों का कहना है कि एक नियतांक का प्रयोग करते हुए किलोग्राम की पुन: दी गई परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि यह भविष्य में अधिक यर्थाथ भार मापन के लिए विश्वसनीय और सक्षम रहेगी।
- किलोग्राम का मूल्य नहीं बदलेगा।
- किलोग्राम 1875 की अंतिम इकाई है जिसे अभी तक नहीं बदली गई है।
- अन्य आधारभूत इकाईयों जैसे: लंबाई के लिए मीटर, ताप के लिए कैल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और ज्योति तीव्रता के लिए कैण्डिला जैसी अन्य आधारभूत इकाईयों के लिए मानकों को सुधारा गया है।
- उदाहरण के लिए, मीटर को उस लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रकाश एक धातु बार की तुलना में एक सेकंड के 1/29,79,458 वें समय में निर्वात में तय करता है।

वजन एवं माप महासम्मेलन

- वजन एवं माप महासम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय भार एवं माप ब्यूरो का सर्वोच्च प्राधिकार है।
- अंतर्राष्ट्रीय वजन एवं माप ब्यूरो एक ऐसा संगठन है जो फ्रांस में पेरिस के पास सेवर्स में स्थित है।
- यह 1875 में मीटर सम्मेलन की शर्तों के अंतर्गत स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसके माध्यम से सदस्य राज्य, माप विज्ञान और माप मानकों से संबंधित मामलों पर एक साथ कार्य करते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- डाउन टू अर्थ

16.11.2018

1. **<u>नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है।</u>**

- नीति आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु 'हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद' का गठन किया है।
- हिमालय की विशिष्टता और सतत विकास के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने वर्ष 2017 में पांच कार्य समूहों को गठन किया था।
- इस परिषद का गठन पांच कार्यसमूहों की रिपोर्टों के आधार पर पहचाने गए कार्य बिंदुओं के कार्यान्वन और समीक्षा हेतु किया गया है, जो कार्यवाही हेतु योजना तैयार करने के लिए विषयगत क्षेत्रों के साथ स्थापित किए गए हैं।

पांच विषयगत क्षेत्र हैं:

- जल सुरक्षा के लिए हिमालय में बसंत के पुन:उत्थान और वस्तुसूची
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन
- खेती को परिवर्तन दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करना

- हिमालय में कौशल और उद्यमिता (E&S) परिदृश्य को सुदृढ़ करना
- सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा/ सूचना

संबंधित जानकारी

- हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य डॉ वी. के. सरस्ववत होंगे और इस परिषद में हिमालयी राज्य के मुख्य सचिवों के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेष आमंत्रितगण भी शामिल होंगे।
- हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद, हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास हेतु प्रधान एजेंसी होगी।
- इस परिषद में 12 राज्य शामिल हैं, जिनके नाम- जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के दो जिले जिनके नाम दिमा हसाओ और करबी अंगलॉग और पश्चिम बंगाल का कालीम्पोंग जिला हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **दिल्ली पुलिस ने ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है: 'एन.आई.पी.यू.एन.'**

- दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों को सेवा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक ई-लर्निंग पोर्टल 'एन.आई.पी.यू.एन.' लॉन्च किया है।
- ई-लर्निंग पोर्टल का उद्देश्य विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करना है।
- यह कानून पर ऑनलाइन संसाधन और जानकारी, स्थायी आदेश, जांच सूची, केस फाइलों के लिए फॉर्म, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसलों को प्रदान करके विभिन्न मुकदमों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों की मदद करेगा।

संबंधित जानकारी

- सहयोगी शिक्षा और साझेदारी (सी.एल.ए.पी.) परियोजना के अंतर्गत कई पाठ्यक्रमों को स्वयं से विकसित किया गया है जब कि अन्य पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), फिक्की, एन.एच.आर.सी., एन.सी.पी.सी.आर. और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया गया हैं।
- प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट का उद्देश्य दिल्ली पुलिस के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय और प्रशिक्षुओं के मध्य सूचना साझा करने में सहायता करना है।
- यह वेबसाइट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, सैंपल प्रश्न पत्र, मैनुअल, कानून आदि प्रदान करती है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

3. **भारत डाक ने ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है।**

- डाक विभाग को भारत डाक के रूप में भी जाना जाता है, भारत डाक ने अपने पार्सल बिजनेस नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अपनी ई-कॉमर्स साइट लॉन्च की है।
- डी.ओ.पी., ऑनलाइन वाणिज्य के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ाने की योजना बना रहा है।

संबंधित जानकारी

- भारत की डाक सेवा ने इस वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक नामक एक स्वतंत्र बैंकिंग सेवा को भी सूत्रबद्ध किया है।

भारत डाक

- डाक विभाग (डी.ओ.पी.) को भारत डाक के रूप में जाना जाता है, यह भारत में डाक विभाग के अंतर्गत एक सरकार-संचालित डाक प्रणाली है।
- यह भारत सरकार के संचार मंत्रालय का हिस्सा है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण संस्थान

स्रोत-पी.आई.बी.

4. **'सुपर-अर्थ' सूर्य के निकटतम एकल तारे के चारो-ओर चक्कर लगाती पायी गई है।**

- खगोलविदों ने पृथ्वी के तीन गुना से अधिक भारी बर्फ से ढके हुए ग्रह की खोज की है, जो

सूर्य के निकटतम अकेले तारे के चारो-ओर चक्कर लगा रहा है।

- संभावित रूप से इस पथरीले ग्रह को बर्नार्ड स्टार बी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक 'सुपर-अर्थ' है और यह प्रत्येक 233 दिनों में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है।
- यह ग्रह 'स्नोलाइन' नामक तारे से सुदूर क्षेत्र में स्थित है।
- यह ग्रह रहने योग्य नहीं है क्यों कि यहां पर पानी और गैस ठोस रूप में स्थित है, अत: यहां जीवन संभव नहीं है।
- इस ग्रह की सतह का तापमान लगभग -170 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है।

संबंधित जानकारी

- बर्नार्ड स्टार, खगोलविदों और एक्सोप्लानेट वैज्ञानिकों के मध्य एक कुख्यात पिंड है, क्यों कि यह उन पहले तारों में से एक था जहां पहले ग्रह होने का दावा किया गया लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआ।
- बर्नार्ड स्टार बी, "प्रॉक्सिमा सेंटौरी बी" के बाद हमारे सूर्य के सबसे निकट ज्ञात दूसरा एक्सोप्लैनेट है।
- अल्फा सेंटौरी ट्रिपल सिस्टम के बाद बर्नार्ड स्टार, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित अगला तारा है।
- यह एक प्रकार का धुंधला और कम द्रव्यमान का तारा है जिसे लाल बौना भी कहा जाता है।
- लाल बौने को एक्सप्लानेट उम्मीदवारों को देखने के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, जो ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित हैं।
- शोधकर्ताओं ने अवलोकन के दौरान त्रिज्या वेग विधि का उपयोग किया था जिसके कारण बर्नार्ड स्टार बी की खोज हुई थी।
- यह तकनीक एक तारे में झोंको का पता लगाती है जो एक कक्षीय ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उतपन्न होते हैं।
- ये झोंके तारे से आने वाले प्रकाश को प्रभावित करते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

5. **<u>आदि महोत्सव</u>**

- "आदी महोत्सव", एक राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव है जिसे आदिवासी मंत्रालय और टी.आर.आई.एफ.ई.डी. के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- यह महोत्सव आदिवासी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य की भावना को पोषण और संवर्धन देने हेतु मनाया जाता है।
- इस त्यौहार की थीम: "आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव" थी।
- इस महोत्सव में आदिवासी कला और शिल्प के उत्पाद, आदिवासी दवा और चिकित्सक, आदिवासी व्यंजन और आदिवासी लोक अभिनय का प्रदर्शन और उत्पादों की बिक्री भी शामिल की जाएगी।

संबंधित जानकारी

(टी.आर.आई.एफ.ई.डी.) - भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड

- यह आदिवासी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।
- इसे बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय (जिसे अब बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) द्वारा स्थापित किया गया था।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य लघु वन उत्पादन (एम.एफ.पी.) और आदिवासियों द्वारा इकठ्ठा अथवा काटे जाने वाले अधिशेष कृषि उत्पादन (एस.ए.पी.) के व्यापार को संस्थागत बनाना है क्यों कि वे अपने जीवनयापन के लिए इन प्राकृतिक उत्पादों पर पूर्णतय: निर्भर हैं।
- टी.आर.आई.एफ.ई.डी., गेहूं और चावल की खरीद के लिए एफ.सी.आई. हेतु एक एजेंसी के रूप में काम करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –कमजोर वर्ग हेतु कल्याणकारी योजनाएं

स्रोत-पी.आई.बी.

6. **<u>भारत ने मृत्युदंड के उपयोग पर यू.एन.जी.ए. मसौदा संकल्प के खिलाफ मतदान किया है।</u>**

- भारत ने मृत्युदंड के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदे संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है और कहा है कि यह देश के सांविधिक कानून के खिलाफ है जहां "दुर्लभ से भी दुर्लभ" मुकदमों में निष्पादन किया जाता है।
- मसौदा संकल्प को महासभा की तीसरी समिति (सामाजिक, मानवतावादी, सांस्कृतिक) में स्वीकार किया गया था।
- भारत, इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में से एक था, जो मृत्युदंड का सामना करने वाले लागों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सम्मान करने हेतु सभी राज्यों की विधानसभा बैठक बुलाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे भेदभावपूर्ण कानून अथवा भेदभाव के परिणामस्वरूप अथवा कानून के मनमाने आदेश के आधार पर लागू नहीं किया गया है।

संबंधित जानकारी

- भारत में मृत्युदंड को दुर्लभ से भी दुर्लभ मामलों में प्रयोग किया जाता है, जिस मुकदमें में किया गया अपराध इतना जघन्य हो कि जिससे समाज की आत्मा कांप जाए, वहां मृत्युदंड प्रयोग किया जाता है।
- भारतीय कानून सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिसमें एक स्वतंत्र न्यायालय द्वारा निष्पक्ष परीक्षण, निर्दोषता की संभावनाएं, रक्षा के लिए न्यूनतम गारंटी और उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा करने का अधिकार शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

- संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- यह एक मात्र ऐसा संगठन है जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के समान प्रतिनिधि, मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि अंग होते हैं।
- इसकी शक्तियों में संयुक्त राष्ट्र के बजट की निगरानी करना, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करना, संयुक्त राष्ट्र के अन्य हिस्सों से रिपोर्ट प्राप्त करना और महासभा संकल्प के रूप में सिफारिशें करना शामिल है।
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में इसकी संरचना, कार्य, शक्तियां, मतदान और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण संस्थान

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **<u>हिमाचल ने युवाओं के लिए 'स्टार्टअप वैन' की शुरूआत की है।</u>**

- हिमाचल प्रदेश ने युवाओं के लिए 'स्टार्टअप वैन' की शुरूआत है जिसका उद्देश्य नौकरी तलाशने वाले युवाओं को नौकरी प्रदाताओं में बदलना है। स्टार्टअप और नवाचार परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार युवाओं को उद्यमिता विकसित करने हेतु हर प्रकार की संभव सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना का मूल उद्देश्य स्व-रोजगार और रोजगार उत्पन्न करना, उद्यमियों के कौशल का उन्नयन करना और व्यवसायिक मार्गदर्शन के अंतर्गत अपनी इकाइयों को स्थापित करने हेतु उन्हें समर्थन प्रदान करना है।
- इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के संभावित क्षेत्रों में व्यावहारिक परियोजनाओं का चयन करने, स्टार्टअप स्थापित करने और उसे व्यवसायिक तरीके से चलाने हेतु प्रशिक्षित करने में उनकी मदद करना भी है।
- इस योजना के अंतर्गत ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संचालित नवाचार क्षेत्र, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, शिल्प, कला, जल और स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ तकनीक, कृषि, बागवानी और इससे संबंधित क्षेत्र, खाद्य

प्रसंस्करण, खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य, मोबाइल, आई.टी. और जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

संबंधित जानकारी

- इस योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण करने, नेटवर्किंग विकसित करने, आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने और जागरूकता पैदा करने के क्रम में राज्य के कई संस्थानों में इनक्यूबेशन सेंटरों का निर्माण करने का प्रावधान है।
- इक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए मंडी आई.आई.टी., हमीरपुर एन.आई.टी., पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, नौनी बागवानी विश्वविद्यालय, बीर प्रौद्योगिकी उद्यान, एच.पी. विश्वविद्यालय, पालमपुर सी.एस.आई.आर. और जे.पी.यू.आई.टी. वकनाघाट का चयन किया गया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण योजनाएं

स्रोत- टी.ओ.आई.

8. **<u>नीति आयोग ने शहरी आधारभूत ढांचे पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है।</u>**

- "शहरी आधारभूत ढांचे: सार्वजनिक और निजी साझेदारी और नगर निगम वित्त नवाचारों के प्रति नए दृष्टिकोण" पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया है।
- इस सम्मेलन का आयोजन एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग और एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है।
- इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शहरी आधारभूत ढांचे में मुख्य मुद्दों, दृष्टिकोणों और आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा करना है।
- इसका लक्ष्य समग्र मुद्दों की समीक्षा करना, दक्षिण एशिया में शहरी वित्त और पी.पी.पी. की स्थिरता का मूल्यांकन करना है, विशेषकर तब जब भारत अपने ज्ञान के आधार को अधिक व्यापक बना रहा और अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों में व्यस्त हो।

संबंधित जानकारी

शहरी आधारभूत ढांचे पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन इस प्रकार का पहला सम्मेलन है, जिसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र से सरकार, उद्योग, अनुसंधान संगठन, अकादमियों, प्रबुद्ध मंडल और नागरिक समाज के नेतृत्वकर्ता शामिल हैं।
- इस सम्मेलन का लक्ष्य समग्र मुद्दों की समीक्षा करना, दक्षिण एशिया में शहरी वित्त और पी.पी.पी. की स्थिरता का मूल्यांकन करना है, विशेषकर तब जब भारत अपने ज्ञान के आधार को अधिक व्यापक बना रहा और अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों में व्यस्त हो।
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) एक ऐसा विकल्प रहा है जो सरकारों को परियोजना के जीवन चक्र से जुड़े जोखिमों को बेहतर रूप से साझा करने में सक्षम बनाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

9. **<u>पर्वतीय गोरिल्ला समाप्त होने की कगार से वापस आ गए हैं।</u>**

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई.यू.सी.एन.) ने एक बयान जारी किया है कि यह प्रजातियां "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" खतरे के स्तर से "लुप्तप्राय" तक स्थानान्तरित हुई हैं।
- वर्ष 2008 में पर्वतीय गोरिल्ला की जनसंख्या लगभग 680 होने का अनुमान लगाया गया था लेकिन वर्ष 2018 के अनुमानों से पता चलता है कि इनकी जनसंख्या बढ़कर एक हजार से अधिक हो गई है, जो इस उप-प्रजाति के लिए अभी तक दर्ज आंकड़ों में उच्चतम है।
- समन्वित और विकसित सर्वेक्षण विधि के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की पुष्टि की गई है।

संबंधित जानकारी

गोरिल्ला

- गोरिल्ला, कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा और युगांडा में पाए जाते हैं, ये देश अफ्रीका के बहुत ही असुरक्षित क्षेत्रों में स्थित हैं।
- जिन तीन देशों में गोरिल्ला पाए जाते हैं उन देशों की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान सीमाओं के प्रवर्तन को बढ़ा दिया है, जहां शिकार, जमाव और पक्की सड़कों अवैध हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –वन्यजीव एवं जैवविविधता

स्रोत- डाउन टू अर्थ

17.11.2018

1. **शिलॉग: नोंगक्रम नृत्य महोत्सव**

- नोंगक्रम नृत्य महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके दौरान अच्छी फसल, शांति और समुदाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है, यह महोत्सव खासी पहाड़ियों के निवासियों द्वारा अत्यधिक जोश और उत्साह से मनाया जाता था।
- यह अद्वितीय नृत्य, स्वदेशी खासी जनजाति की उप-जनजाति हिमाखिरिम के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- इस महोत्सव के दौरान इस जनजाति के लोग चांदी अथवा सोने का मुकुट पहनते हैं जो खासी समाज की प्रतिष्ठा और गौरव को दर्शाता है।
- पुरुषों द्वारा किए गए नृत्य को "का शाद मस्तीह" के नाम से जाना जाता है।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में मेघालय में इंडिया इंटरनेशल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया गया था।
- यह महोत्सव मेघालय सरकार के वानिकी एवं पर्यावरण विभाग, जैव संसाधन संस्थान और भारतीय सांस्कृतिक परिषद के साथ सहयोग में सतत विकास द्वारा आयोजित किया गया था।
- यह कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हिमालयी चेरी ब्लॉसम में अद्वितीय शरद ऋतु के फूल आने का उत्सव मनाता है।
- इसके प्रतिनिधियों के माध्यम से जापान सरकार की भागीदारी के साथ इस त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाया गया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- एन.डी.टी.वी.

2. **दक्षिण-पश्चिम तट के लिए यातायात पृथक्करण योजना**

- नौवहन महानिदेशालय ने यातायात पृथक्करण योजना (टी.एस.एस.) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
- भारतीय तट से दूर टक्कर की पिछली घटनाओं, पिछले वर्षों के लिए व्यापारियों के जहाजों के यातायात प्रारूप, वर्तमान यातायात प्रवाह के साथ तालमेल में अनुकूलतम समुद्री मार्गों पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है, इसमें केरल तट से दूर स्थित क्षेत्रों में यातायात का सरलीकरण भी शामिल है।
- भारतीय जलमार्गों में होने वाली टक्कर की घटनाओं का कम करने के लिए इस प्रस्ताव में नौपरिवहन की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और यातायात की विपरीत धाराओं के अलगाव से संबधित पहलुओं पर भी विचार किया गया है।

संबंधित जानकारी

- प्रस्तावित टी.एस.एस. लेन वर्तमान में विचाराधीन हैं और यह कर्नाटक में मैंगलोर के पश्चिम में लगभग 90 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित होगी।
- यह लेन भारत के दक्षिणी सिरे की दक्षिण-पूर्व दिशा में बढ़ रही है और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के दक्षिण में लगभग 40 नॉटिकल मील की दूरी पर समाप्त होती है।
- तट से औसत दूरी लगभग 50 नॉटिकल मील है।
- यह योजना मछली पकड़ने वाले जहाजों के सुरक्षित संचालन हेतु अधिक समुद्री क्षेत्र प्रदान करेगी और यह मछली उद्योग के लिए फायदेमंद रहेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –सरकारी योजना

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>आंध्र सरकार ने अमरावती कला-प्रेरित राज्य प्रतीक घोषित किया है।</u>**

- आंध्र प्रदेश सरकार ने आधिकारिक प्रयोग के लिए अपना नया प्रतीक निर्धारित किया है।
- राज्य प्रतीक, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से प्रेरित है, राज्य प्रतीक में "धम्मा चक्का"- "कानून का पहिया" है, जो त्रिरत्नों के वृत्त से अलंकृत है जिसमें एकांतर क्रम में सुफ़ने की पत्तियां और कीमती पत्थर जड़े हुए हैं।
- "धम्मा चक्का के केंद्र में पूर्ण कलासा सुशोभित है।
- प्रतीक के निचले भाग में राष्ट्रीय प्रतीक रखा गया है, जिसे कभी भी 24 मि.मी. से कम ऊँचाई के आकार का नहीं किया जाना चाहिए।

संबंधित जानकारी

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2014 में आंध्र पदेश को तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश राज्य में विभाजित किया गया था, यह अधिनियम तेलंगाना अधिनियम के नाम से लोकप्रिय है।
- इस अधिनियम ने दोनों राज्यों की सीमाओं को परिभाषित किया और हैदराबाद को नए राज्य तेलंगाना की स्थायी राजधानी और नए आंध्र प्रदेश राज्य की अस्थायी राजधानी घोषित किया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गर्वनैंस

स्रोत- ए.आई.आर

4. **<u>अरुणाचल प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत दो पूर्वोत्तर सर्किटों का उद्घाटन किया गया है।</u>**

- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पी.टी.एस.ओ. झील में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है।
- ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर सर्किट- भालुकपोंग-बोमडिला - तवांग परियोजना और नाफरा-सेप्पा-पप्पू, पासा, पक्के घाटी- सांगदूपोता- नई सगाली-ज़ीरो- योम्चा परियोजना का विकास कर रही हैं।

संबंधित जानकारी

स्वदेश दर्शन योजना

- यह योजना वर्ष 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य देश में थीम-आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना है।
- पर्यटक सर्किटों को एकीकृत तरीके से उच्च पर्यटक मूल्य, प्रतिस्पर्धा और स्थायित्व के सिद्धांतों पर विकसित किया जाएगा।
- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास करने हेतु तेरह विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है जिनके नाम: उत्तर-पूर्व भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालयी सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, मरूस्थालीय सर्किट, जनजातीय सर्किट, पारिस्थिकीय सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और विरासत सर्किट हैं।
- यह योजना, सार्वजनिक वित्त पोषण के लिए शुरू किए गए परियोजना घटकों के लिए 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है।
- यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) पहलों का भी लाभ उठाती है।

प्रसाद बनाम स्वदेश दर्शन योजना

- तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत पहचाने गए तीर्थ स्थलों के विकास और सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- जब कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पहचाने गए 'आध्यात्मिक सर्किट' में उन विशेष विषयगत सर्किटों के विकास पर जोर दिया जा रहा है जिनमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों के विभिनन धार्मिक/आध्यात्मिक गंतव्य शामिल हैं।
- प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास हेतु 13 स्थलों की पहचान की गई है, जिनके नाम: अमृतसर, अजमेर, द्वारका, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, अमरावती, कांचीपुरम, वेल्लंकन्नी, केदारनाथ, कामख्या और पटना हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –सरकारी योजना

स्रोत-पी.आई.बी.

5. **<u>विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक जयपुर में आयोजित की गई है।</u>**

- विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय क्षेत्रीय बैठक जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई है।
- इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से डब्लू.सी.ओ. के उप सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जा रही है।
- क्षमता निर्माण और सीमा शुल्क में सुधार के लिए आवश्यक कदमों सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु यह बैठक आयोजित की गई है।
- इसके अतिरिक्त प्रतिभागी अन्य मुद्दों के मध्य संशोधित क्योटो प्रोटोकॉल, डिजिटल सीमा शुल्कों, ई-कॉमर्स पर भी चर्चा और विचार-विमर्श करेंगे।

संबंधित जानकारी

विश्व सीमा शुल्क संगठन

- विश्व सीमा शुल्क संगठन, एक अंतरसरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी।
- यह एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सीमा शुल्क मामलों में कार्यनिर्वाह क्षमता रखता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क समुदाय की आवाज़ माना जाता है।
- डब्लू.सी.ओ. के सदस्य 182 देशों में सीमा शुल्क नियंत्रण हेतु जिम्मेदार हैं जो सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के 98 प्रतिशत हिससे का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- डब्लू.सी.ओ. का प्राथमिक उद्देश्य सदस्य सीमा शुल्क प्रशासन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है जिससे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों, विशिष्ट राजस्व संग्रह, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार सुविधा, सामुदायिक सुरक्षा और व्यापार आंकड़ों के संग्रह में सफलतापूर्वक योगदान देने में मदद मिलती है।
- यह अपने सदस्यों और रणनीतिक पर्यावरण की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है और इसके उपकरणों एवं सर्वोत्तम अभ्यास दृष्टिकोणों को पूरे विश्व में सुदृढ़ सीमा शुल्क प्रशासन के आधार के रूप में माना जाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

6. **<u>केरल सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गौ समृद्धि योजना की शुरूआत की है।</u>**

- केरल सरकार ने डेयरी किसानों के लिए "गौ समृद्धि योजना" की शुरूआत की है।
- सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त योजना, कम प्रीमियम दरों पर डेयरी किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करेगी।
- सामान्य श्रेणी से संबंधित किसानों को प्रीमियम पर 50% सब्सिडी मिलेगी जब कि अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी के लोगों को प्रीमियम पर 70% सब्सिडी मिलेगी।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –कमजोर समाज हेतु योजनाएं

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

7. **<u>13वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन</u>**

- सिंगापुर में 13वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है जिसके दौरान समूह के नेताओं ने समुद्री सहयोग सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है।
- भारत, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में वर्ष 2005 में इसकी स्थापना के बाद से भाग ले रहा है।

संबंधित जानकारी

ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन

- ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला एक अद्वितीय मंच है।
- ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।
- वर्ष 2005 में स्थापित ई.ए.एस. ने प्रमुख नेताओं को एशिया- प्रशांत क्षेत्र में सामान्य हितों और चिंताओं पर उच्चतम स्तर पर खुले और

पारदर्शी तरीके से चर्चा करने की स्वीकृति प्रदान की थी।

- ई.ए.एस. की सदस्यता में दस आसियान सदस्य राज्य (ब्रुनेई दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी.डी.आर., मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम), ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और अमेरिका शामिल हैं।
- ई.ए.एस., आसियान की एक पहल है और आसियान की केंद्रीयता के आधार पर आधारित है।
- ईस्ट एशिया समूह की अवधारणा को पहली बार वर्ष 1991 में तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा प्रोत्साहित की गई थी।
- ई.ए.एस. के ढांचे के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग के छह प्राथमिक क्षेत्र हैं।
- ये क्षेत्र- पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान कनेक्टिविटी हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण समिति

स्रोत-द हिंदू

8. **<u>तमिलनाडु में जल एवं स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार और ए.डी.बी. ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।</u>**

- एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) और भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य के कम से कम 10 शहरों में जलवायु-अनुकूल जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी ढांचे को विकसित करने के लिए $ 500 मिलियन के बहु-किश्त वित्तपोषण की पहली किश्त के रूप में $169 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- तमिलनाडु को पानी और स्वच्छता के प्रति सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने और उच्च प्रदर्शन वाले औद्योगिक गलियारे में विश्व स्तरीय शहरों को विकसित करने के लिए ए.डी.बी. कार्यक्रम समर्थन करने हेतु राज्य के विजन तमिलनाडु 2023 का भाग बन गया है।
- ए.डी.बी. का समर्थन, नवाचार और जलवायु-अनुकूल निवेश और गहन संस्थागत समर्थन के माध्यम से जटिल शहरी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा।
- भारत का पहला सौर संचालित सीवेज उपचार संयंत्र भी इसी परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली को पेश करने से गैर-राजस्व जल को कम करने और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

संबंधित जानकारी

- तमिलनाडु, भारत के बड़े राज्यों का सबसे शहरीकृत राज्य है, लेकिन यहां पर शहरी सेवा का स्तर निम्न है, तमिलनाडु में आधे से कम घरों में पाइप के पानी की पहुँच है।
- इस राज्य में केवल 42% परिवार सीवेज नेटवर्क द्वारा कवर किए गए हैं, जिसमें से 43% सीवेज सीधे जलमार्गों में जाता है।
- यह कार्यक्रम रहने योग्य शहरों के विकास हेतु व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में संस्थागत क्षमता, जन जागरूकता और शहरी शासन को बढ़ावा देगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

19.11.2018

1. **<u>भुवन गंगा भू-पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन</u>**

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नई दिल्ली में विश्व जी.आई.एस. दिवस 2018 पर विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया था।
- जी.आई.एस. दिवस की थीम: 'भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से नमामि गंगे कार्यक्रम का जी- शासन' थी।
- एन.एम.सी.जी. ने जून 2015 में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इन्होंने भुवन गंगा भू-पार्टल और भुवन गंगा मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है।

भुवन गंगा पोर्टल

- भुवन गंगा भू-पोर्टल जल गुणवत्ता की निगरानी, जलविद्युत निगरानी, भू-आकृति निगरानी, जैव

संसाधन निगरानी करने और व्यापक भू-स्थानिक डेटाबेस के लिए उपलब्ध है।

- भुवन गंगा मोबाइल एप्लिकेशन, एक यूजर फ्रैंडली एप्लीकेशन है जो गंगा नदी की जल गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रदूषण स्रोतों पर जानकारी इकट्ठा करने और रिपोर्ट करने में उपयोगकर्ता/जनता को सक्षम बनाता है।
- मोबाइल एप्लिकेशन में शहरी सीवेज, अर्ध शहरी/ ग्रामीण सीवेज, प्राकृतिक नालियों/ नालों, औद्योगिक अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट निपटान अथवा किसी भी अन्य प्रदूषण स्रोत के संदर्भ में जानकारी इकठ्ठा करने का प्रावधान है।

संबंधित जानकारी

- अपनी असीमित क्षमता के कारण गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभावी न्यूनीकरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जी.आई.एस. मानचित्रण, एन.एम.सी.जी. के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है।
- डिजिटल उन्नयन मॉडल तैयार करने हेतु उच्च रिज़ॉल्यूशन में गंगा घाटी का मानचित्रण करने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) तकनीकि का प्रयोग करके गंगा कायाकल्प कार्य को सुविधाजनक बनाने हेतु एन.एम.सी.जी. ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर काम किया है।
- यह तकनीक एक क्षेत्र की संपूर्ण स्थलाकृति की पहचान करने में सक्षम बनाती है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करना और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सुधार करना आसान हो जाता है।
- इस तकनीक के माध्यम से गंभीर प्रदूषण हॉटस्पॉटों को भी आसानी से पहचाना जाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – महत्वूपर्ण पोर्टल

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>केरल ने एक नया ओपेन ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम 'के.ओ.ओ.एल.' प्रस्तावित किया है।</u>**

- केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (के.आई.टी.ई.) ने अपने ऑनलाइन ओपन शिक्षण प्रशिक्षण मंच 'के.ओ.ओ.एल.' को प्रस्तावित किया है।
- इस मंच का उपयोग शिक्षकों, छात्रों और आम जनता को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है।
- के.ओ.ओ.एल. को एक एम.ओ.ओ.सी. (वृहद ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम) मॉडल में डिजाइन किया गया है, जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।

संबंधित जानकारी

के.ओ.ओ.एल.

- यह, शिक्षा के क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बनने के लिए केरल राज्य द्वारा लिया गया बड़ा कदम है।
- इसे शिक्षा विभाग के संसाधन पोर्टल 'समग्र' के विस्तारित रूप में विकसित किया जा रहा है।
- गतिविधियों का अभ्यास करने के लिए एनिमेटेड शिक्षण सहायक, वीडियो ट्यूटोरियल और जांचसूची के रूप में इसमें शिक्षार्थियों के लिए विशेषताओं की एक श्रृंखला शामिल है।
- यह राज्य का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस

3. **<u>फिच ने 'बी.बी.बी.-' पर भारत की रेटिंग की पुष्टि की है: आउटलुक स्टेबल</u>**

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पुष्टि की है कि भारत का 'दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग' (आई.डी.आर.) स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बी.बी.बी.-' पर है।
- फिच रेटिंग, दुनिया की तीन बड़ी क्रेडिट एजेंसियों में से एक है। अन्य दो क्रडिट एजेंसियां मूडीज और स्टैंर्ड एंड पुअर हैं।
- फिच ने वर्ष 2006 में स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बी.बी.+' से 'बी.बी.बी.-' तक भारत की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया था।
- फिच का कहना है कि वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी मौद्रिक के सख्त होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार में स्थानांतिरत होने के लिए कमजोर है।

संबंधित जानकारी

- अप्रैल में न्यूनतम सार्वजनिक वित्त और बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे और महत्वपूर्ण सुधारों के माध्यम से मौजूदा सरकार की विफलता का हवाला देते हुए भारत के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को घटा दिया गया था।
- निवेश ग्रेड के लिए रेटिंग की सीमा ए.ए.ए. (श्रेष्ठ) से बी.- अथवा बी. 3 (बहुत खराब) के मध्य है।

निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग क्या है?

- निवेश ग्रेड निवेश, वित्तीय साधन होते हैं जिनकी रेटिंग एस एंड पी. की शब्दावली के अंतर्गत ए.ए.ए.+ से बी.बी.बी. तक होती है।
- यह बी.बी.बी.- को बाजार भागीदारों द्वारा किए गए विचार के अनुसार न्यूनतम निवेश ग्रेड मानते हैं।
- बी.बी.बी. से नीचे के ग्रेड को अव्यवहार्य ग्रेड निवेश मानते हैं और इसके नीचे की रेटिंग डिफॉल्ट में बांड की अंतिम श्रेणी है।
- जिन बॉन्ड को निवेश ग्रेड बांड के रूप में नहीं रेट किया जाता है उन्हें हाइ यील्ड बांड अथवा जंक बॉन्ड के रूप में जाना जाता है।

निवेश ग्रेड रेटिंग क्यों आवश्यक है?

- वित्तीय सिद्धांत जोखिम को कम करने और अधिकतम संभावित रिटर्न निकालने के लिए निम्नलिखित विविधीकरण का सुझाव देता है।
- इस रणनीति का अनुसरण करते हुए कई बड़े वित्तीय संस्थानों में दुनिया भर में इक्विटी और बॉन्ड में निवेश किया है।
- इन एफ.आई. के अंतर्गत कुछ ऐसे पेंशन फंड, ट्रस्ट और एंडॉवमेंट्स हैं जिन्हें केवल निवेश ग्रेड उपकरणों में निवेश करने का आदेश है।
- अंत: किसी भी देश का बांड जिसकी निवेश-ग्रेड रेटिंग समाप्त होती है उसे बाजार में बेचा जाएगा।

इसके प्रभाव क्या हैं?

- यदि कोई देश अपनी निवेश ग्रेड रेटिंग खो देता है तो उसे भविष्य के ऋणों के लिए बहुत अधिक लागत देनी पड़ेगी क्यों कि उसकी विश्वसनीयता को उच्च नहीं माना जाएगा और उसे बाजार में कम संख्या में ऋण प्रदाता मिलेंगे।
- आत्मविश्वास की कमी के परिणामस्वरूप इक्विटी बाजारों से धन का बहिर्वाह भी हो जाएगा क्यों कि अर्थव्यवस्था में विश्वास कम हो जाएगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

4. **<u>आर.बी.आई. अधिनियम की धारा 7</u>**

- आर.बी.आई. अधिनियम की धारा 7, केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) के बीच मतभेदों के समय से सुर्खियों में आई है।
- आर.बी.आई. अधिनियम में दिए गए प्रावधान सरकार को आर.बी.आई. को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- सरकार ने धारा 7 को लागू कर दिया जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया है।
- इस खंड के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के लिए तरलता, कमजोर बैंकों की पूंजी आवश्यकता और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को ऋण प्रदान करने के मुद्दों पर हाल के सप्ताहों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को कई पत्र भेजे हैं।

संबंधित जानकारी

धारा 7 क्या है?

- भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार से स्वतंत्र एक इकाई है। इस प्रकार यह अपने निर्णय स्वयं लेती है। अत: कुछ मामलों में इसे सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ता है।
- आर.बी.आई. अधिनियम में धारा 7 में यह प्रावधान निहित है जो कहते हैं: (a) सार्वजनिक हितों के लिए आवश्यक समझें जाने वाले मुद्दों पर केंद्र सरकार को समय-समय पर बैंक के गवर्नर के साथ परामर्श करने के बाद बैंक को निर्देशित करना चाहिए। (b) इस प्रकार के किसी भी निर्देश के अधीन, बैंक के मामलों और व्यापार के महाप्रबंधन और निर्देश को केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा जाएगा

जो सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और उन सभी कार्यों और चीजों को कर सकता है जिनका प्रयोग बैंक द्वारा किया जाता है। (c) केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए अधिनियम में गर्वनर और उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस मामले में नामित किए गए डिप्टी गवर्नर के पास भी महाप्रबंधक की शक्तियां और मामलों के निर्देश और बैंको के व्यापार होते हैं, वह सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और वे सभी कार्य और चीजें कर सकता है जिनका अभ्यास अथवा कार्यान्वन बैंक द्वारा किया जाता है।

नोट: यह अनुभाग सरकार को सार्वजनिक हित के संदर्भ में केंद्रीय बैंक को दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जो अन्यथा की स्थिति में सरकार से आदेश नहीं लेता है।

सरकार ने धारा 7 क्यों लागू की है?

- सरकार का मानना था कि तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पी.सी.ए.) ढांचे के अंतर्गत बैंकों के लिए ऋण नियमों को आसान बनाने से एम.एस.एम.ई. पर दबाव कम हो सकता है।
- नियामक उसी समस्या के साथ खड़ा था और वह सरकार कह रहा था कि आपके इस कदम से हम प्रगति में पीछे चले जाएंगे और हमारे सारे सुधारात्मक प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे।
- सितंबर में आई.एल. और एफ.एस. डिफ़ॉल्ट के बाद क्रेडिट बाजारों के सख्त होने के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों ने अधिक तरलता के लिए सरकार की पैरवी की।
- लेकिन आर.बी.आई. ने अपनी स्थिति बनाए रखी क्यों कि बैंकिंग प्रणाली में ऋण लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और बाजार सिर्फ एक विकसित स्थिति में जोखिम को कम कर रहा था।

टॉपिक-जी. एस. पेपर 3- भारतीय अर्थव्यवस्था

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

5. **<u>छात्रों द्वारा भारत का पहला सूक्ष्म उपग्रह "एक्ससीड सैट 1" हैदराबाद से लांच किया गया है।</u>**

- हैदराबाद आधारित स्टार्टअप एक्सीड स्पेस के संरक्षण के अंतर्गत विकसित भारत का पहला निजी उपग्रह "एक्ससीड सैट1" है।
- एक्ससीड सैट 1 को 19 नवंबर को वैंडेनबर्ग वायु सेना स्टेशन, कैलिफ़ोर्निया में स्पेसएक्स लॉन्चपैड से लॉन्च किया गया था।

संबंधित जानकारी

एक्ससीड

- एक्ससीड वाणिज्यिक, सरकारी और अकादमिक ग्राहकों के लिए उन्नत छोटे उपग्रह और वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान बनाता है।
- एक्ससीड सैट1 को बहुत उच्च आवृत्ति (वी.एच.एफ.) और अति उच्च आवृत्ति (यू.एच.एफ.) सिग्नल पर संचालित किया जाता है और यह यू.एच.एफ. सिग्नलों को ऊपर ले जाता है और वी.एच.एफ. सिग्नलों को वापस भेजता है, इस प्रकार निजी रेडियो ऑपरेटरों के लिए आसान संचार उपलब्ध कराता है।
- चार वर्ष पूर्व हैमसैट द्वारा संचालन बंद करने के बाद एक्ससीड सैट 1 से निजी रेडियों ऑपरेटरों को अधिक बढ़ावा प्रदान करने की उम्मीद है। हैमसैट को कई हैम ऑपरेटरों के योगदान द्वारा बनाया गया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – अर्थशास्त्र

स्रोत- ई.टी.

6. **<u>बाघ स्थानांतरण जारी रह सकता है: एन.टी.सी.ए.</u>**

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) ने बड़ी असफलताओं के बावजूद ओडिशा के सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य में चल रही इस प्रकार की पहली अंतर-राज्य बाघ स्थानान्तरण परियोजना के जारी रहने की उम्मीद जतायी है।
- ओडिशा ने सतकोसिया में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से तीन जोड़े बाघ लाने की योजना बनाई थी।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- यह पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सक्षम प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण एवं वानिकी मंत्री की अध्यक्षता में की जाती है।
- प्राधिकरण में आठ विशेषज्ञ अथवा व्यवसायी शामिल होते हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण और जनजातियों लोगों के कल्याण के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव होता है, इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में संसद के तीन सदस्य होते हैं जिनमें से दो सदस्य संसद द्वारा और एक सदस्य विधान परिषद द्वारा चुना जाता है।
- वन के महानिरीक्षक, टाइगर परियोजना के प्रभारी अपने पदानुसार कार्यकारी सचिव होंगे।

एन.टी.सी.ए. के मुख्य उद्देश्य

- टाइगर परियोजना को सांविधिक अधिकार प्रदान करना जिससे कि उसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी हो।
- अपनी संघीय संरचना के अंतर्गत राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के आधार पर बाघ अभ्यारण्य के प्रबंधन में केंद्र-राज्य के उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना।

एन.टी.सी.ए. की शक्तियां और कार्य

- इस अधिनियम की धारा 38V की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी प्रदान करना।
- यह सतत पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और आकलन करता है और बाघ अभ्यारण्य के भीतर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे पारिस्थितिक रूप से अस्थिर भूमि के उपयोग को अस्वीकृत करता है।
- यह बाघ संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु महत्वूपर्ण समर्थन को सुनिश्चित करता है जिसमें वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और कानूनी समर्थन शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – वन्यजीव एवं जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>मथुरा में भारत का पहला हाथियों का अस्पताल खोला गया है।</u>**

- हाथियों के लिए भारत का पहला विशिष्ट अस्पताल मथुरा, उत्तर प्रदेश मे खाला गया है।
- इस अद्वितीय चिकित्सा केंद्र में वायरलेस डिजिटल एक्स-रे, लेजर उपचार, दांत का एक्स-रे, थर्मल इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, हाइड्रोथेरेपी और अस्पताल में अलग कमरे की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- यह असपताल, हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र (वन्यजीवन एस.ओ.एस.) के नजदीक स्थित है। इस अस्पताल को घायल, बीमार अथवा बूढ़े हाथियों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह अस्पताल हाथियों को उठाने के लिए चिकित्सा सुविधाओं से लैस है।

संबंधित जानकारी

वन्यजीवन एस.ओ.एस.

- वन्यजीवन एस.ओ.एस. (डब्ल्यू.एस.ओ.एस.), भारत में एक संरक्षण गैर-लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य भारत की प्राकृतिक विरासत, जंगलों और वन्यजीवन की रक्षा और संरक्षण करना है।
- डब्ल्यू.एस.ओ.एस. का प्राथमिक उद्देश्य देश में संकटग्रस्त वन्यजीवन को बचाना और पुनर्वास करना और भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना है।
- यह वर्तमान में दक्षिण एशिया में सबसे बड़े वन्यजीव संगठनों में से एक है।
- डब्ल्यू.एस.ओ.एस. को आलसी भालुओं और अभी हाल ही में हाथियों के संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है।
- वन्यजीव एस.ओ.एस. भारत में कई राज्यों में तेंदुए, मैकाक, हाथी, मून भालू, सांप इत्यादि जैसी प्रजातियों के संदर्भ में मानव-वन्यजीव संघर्ष के शमन पर केंद्रित सक्रिय परियोजनाओं को भी चलाता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण एवं वन्यजीव

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>चीन द्वारा निर्मित 'कृत्रिम सूर्य'</u>**

- चीन का "कृत्रिम सूर्य" 10 मेगावाट की ऊष्मीय क्षमता के साथ 180 मिलियन ºF के तापमान तक पहुंच गया था।

- इस तापमान पर यह जलते हुए तारे के मूल भाग से छह गुना अधिक गर्म होता है, जो लगभग 27 मिलियन फॉरेनहाइट (15 मिलियन सेंटीग्रेड) तक जाता है।
- परमाणु संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकमाक (ई.ए.एस.टी.) युक्ति का निर्माण किया गया है, यही समान प्रक्रिया तारों को शक्ति प्रदान करती है।
- यह प्रयोग प्लाज्मा भौतिकी संस्थान द्वारा किया गया है।

संबंधित जानकारी

परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन

- परमाणु विखंडन तब होता है जब एक बड़े, कुछ हद तक अस्थिर समस्थानिक (वे अणु जिनमें प्रोटानों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रानों की संख्या भिन्न होती है) परमाणुओं पर उच्च गति वाले कणों, सामान्यत: न्यूट्रॉनों से बमबारी की जाती है।
- इन न्यूट्रॉनों को त्वरित किया जाता है और फिर इन्हें विखंडित अथवा छोटे कणों में विभाजित करने हेतु अस्थायी समस्थानिकों पर इनकी बमबारी करायी जाती है।
- इस प्रक्रिया के दौरान एक न्यूट्रॉन त्वरित किया जाता है और लक्षित नाभिक पर हमला करता है, जो आज के समय में अधिकतर परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग किया जा रहा है वह यूरेनियम -235 है।
- यह लक्षित नाभिक को विभाजित करता है और इसे दो छोटे समस्थानिकों (विखंडन उत्पादों), तीन उच्च गति वाले न्यूट्रॉनों और बड़ी मात्रा में ऊर्जा में तोड़ देता है।
- इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा को परमाणु रिएक्टरों में पानी गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है और अंततः इससे बिजली उत्पन्न की जाती है।
- उत्सर्जित होने वाले उच्च गति के न्यूट्रॉन प्रक्षेप्य में परिवर्तित हो जाते हैं जो अन्य विखंडन अभिक्रिया अथवा श्रृंखला अभिक्रिया शुरू करते हैं।

परमाणु संलयन

- परमाणु संलयन "भारी नाभिक का निर्माण करने हेतु छोटे परमाणु नाभिकों का संघ जो परिणामस्वरूप विशालमात्रा में ऊर्जा के उत्सर्जन करने को संदर्भित करता है।
- एक संलयन अभिक्रिया होने के लिए अत्यधिक उच्च दाब और 270 मिलियन फॉरेनहाइट से अधिक के तापमान पर दो परमाणु नाभिकों को मिलना चाहिए।
- संलयन अभिक्रिया तक होती है जब दो कम द्रव्यमान वाले समस्थानिक सामान्यत: हाइड्रोजन के समस्थानिक अत्यधिक ताप और दाब की शर्तों के अंतर्गत एकत्र होते हैं।
- संलयन ही सूर्य को शक्ति प्रदान करता है।
- ट्राइटियम और ड्यूटीरियम के परमाणु (हाइड्रोजन के समस्थानिक क्रमशः हाइड्रोजन-3 और हाइड्रोजन-2 हैं), एक न्यूट्रॉन और हीलियम समस्थानिक उत्पन्न करने हेतु अत्यधिक दाब और ताप के अंतर्गत मिलते हैं।
- इसके साथ ही विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – विज्ञानएवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

20.11.2018

1. **<u>एन.एस.ई. गो बिड: एन.एस.ई. द्वारा लांच किया गया मोबाइल ऐप है।</u>**

- भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने खुदरा निवेशकों के लिए 'सरकारी प्रतिभूतियों' को खरीदने के लिए अपना नया मोबाइल ऐप और वेब-आधारित मंच 'एन.एस.ई. गो बिड' लॉन्च करने की घोषणा की है।
- एन.एस.ई. के व्यापारिक सदस्यों के साथ सभी पंजीकृत निवेशकों के लिए 'एन.एस.ई. गो बिड' ऐप उपलब्ध होगा और यह नए खुदरा निवेशकों

को एकत्र करने की सुविधा भी व्यापारिक सदस्यों को प्रदान करेगा।

- यह खुदरा निवेशकों को 'एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यू.पी.आई.)' और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा सीधे अपने बैंक खाते से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करेगा।
- 'एन.एस.ई. गो बिड मंच' आर्डर संग्रहण, भुगतान और रिफंड के कार्य का प्रबंधन करेगा जिन्हें वर्तमान में व्यापारिक सदस्यों द्वारा प्रबंधित करने की आवश्यक्ता होती है।
- इस ऐप के माध्यम से खुदरा निवेशक ट्रेजरी बिलों (टी- बिल) में 91 दिनों, 182 दिन और 364 दिनों के लिए और विभिन्न सरकारी बांडों में एक वर्ष से 40 वर्षों की अवधि तक निवेश कर सकते हैं।

संबंधित जानकारी

भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज

- भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई में स्थित भारत का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है।
- एन.एस.ई. की स्थापना वर्ष 1992 में देश के पहले लाभकारी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में की गई थी।
- एन.एस.ई. आधुनिक, पूर्णतया स्वचालित स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली प्रदान करने वाला देश का पहला एक्सचेंज था, जो पूरे देश के निवेशकों को आसान ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण पोर्टल

स्रोत- द हिंदू

2. **<u>ग्रोथ-इंडिया दूरदर्शी का पहला विज्ञान अवलोकन</u>**

- ग्रोथ-इंडिया दूरदर्शी, हनले, लद्दाख में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है।
- इसने अपना पहला विज्ञान अवलोकन किया है जो नोवा विस्फोट का अनुवर्ती अध्ययन है।
- ग्रोथ-इंडिया दूरदर्शी, आने वाले यात्रियों को देखने वाली वेधशालाओं के वैश्विक रिले का हिस्सा है।
- इसके तीन लक्ष्य हैं:

1. जब भी एल.आई.जी.ओ. समूह अपनी बाइनरी न्यूट्रॉन तारे विलय का पता लगाता है तो प्रकाशीय क्षेत्र में विस्फोटों की खोज करना
2. नजदीकी युवा सुपरनोवा विस्फोटों का अध्ययन करना
3. नजदीकी क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करना

संबंधित जानकारी

नोवा

- नोवा एक विस्फोटक घटना है जिसमें सफेद बौने तारें की सतह पर होने वाले प्रचंड विस्फोट शामिल है, जो तारे की चमक में अस्थायी वृद्धि करते हैं।
- इस आवर्ती नोवा का नाम एम.31एन. -2008 है जिस पर कई बार विस्फोट होते देखा गया है।

नोवा बनाम सुपरनोवा

- नोवा और सुपरनोवा, ब्रह्मांड की दो विशेषताएं हैं।
- नोवा को "एक सप्ताह से वर्षों की अवधि के दौरान एक सितारा अचानक से बहुत अधिक चमकीला हो जाता है और फिर पुन: अपनी वास्तविक चमक को प्राप्त कर लेने के रूप में परिभाषित करते हैं।
- सुपरनोवा, "एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसमें तारे के भीतर अधिकांश सामग्रियों के विस्फोट शामिल होते हैं, जो परिणामस्वरूप एक बेहद चमकीले, अल्पकालिक वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं"।
- नोवा और सुपरनोवा के बीच बड़ा अंतर यह है कि सुपरनोवा में विस्फोटों के साथ बहुत सी वस्तुओं के द्रव्यमान निकलकर बाहर चले जाते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>श्रीलंकाई फ्रॉगमाउथ: एक दुर्लभ पक्षी को केरल के चिन्नार अभ्यारण्य में देखा गया था।</u>**

- हाल ही में एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति 'श्रीलंकाई फ्रॉगमाउथ' को केरल के चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया था।

- पहली बार जब पश्चिमी घाटों के पूर्वी छोर पर इस पक्षी को देखा गया था तब से इस पक्षी ने पक्षी विज्ञानियों के मध्य अत्यंत रूचि उत्पन्न कर दी है।

श्रीलंकाई फ्रॉगमाउथ

- यह सामान्यत: पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर पाया जाता है।
- यह यूरोप और शीतोष्ण एशिया में पाए जाने वाले नटैजा, सांध्यकालीन और रात्रिचर पक्षी प्रजाति का संबंधी है।
- इसका पसंदीदा आवास कुछ छोटे पेड़ों अथवा झाड़ियों के साथ एक शुष्क और खुला क्षेत्र है।
- इस प्रजाति की मुख्य विशेषता यह है कि अप्रैल-मई में संभोग के मौसम के बाद यह साल में केवल एक अंडा देती है।
- नर पक्षी घोंसले को नष्ट करके नवजात पक्षी के साथ उड़ जाता है।
- श्रीलंका में इनका एक अद्वितीय आवास है और माना जाता है कि ये पक्षी प्रजाति कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में पायी जाती हैं।
- आई.यू.सी.एन. स्टेटस- कम चिंतनीय

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –वन्यजीवन एवं जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

4. **<u>भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति 2018 रिपोर्ट</u>**

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने देश की पहली स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति 2018 की रिपोर्ट जारी की है।
- यह रिपोर्ट 'आई.एन.सी. 42' द्वारा तैयार की गई है जो एक भारतीय सूचना मंच है जिसे भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के प्रसार हेतु जाना जाता है।
- यह रिपोर्ट एक विश्लेषण है जो प्रशासन, निवेश, विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य मूल पहलुओं के संदर्भ में रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्तमान में 49,000 से अधिक स्टार्टअप, 1500 से अधिक निवेशक, 250 से अधिक इनक्यूबेटर और 26 यूनिकॉर्न्स हैं।
- अपने आकार, पहुंच और प्रभाव के संदर्भ में भारत दुनिया के तीन सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है।

संबंधित जानकारी

आई.एन.सी.42

- आई.एन.सी. (इंक) 42, एक अग्रणी भारतीय मीडिया एवं सूचना मंच है, जो भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के संपूर्ण कवरेज के लिए जाना जाता है।
- आई.एन.सी. 42, समर्थित समाचार और विश्लेषण के माध्यम से स्टार्टअप अर्थव्यवस्था की गहन समझ प्रदान करने के द्वारा भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाने, कनेक्ट और विकसित करने के मिशन के साथ कार्य करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – महत्वूपर्ण रिपोर्ट

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

5. **<u>2018 एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (ए.पी.ई.सी.) शिखर सम्मेलन</u>**

- हाल ही में 2018 एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन पापुआ न्यू गिनी में किया गया है।

संबंधित जानकारी

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग

- ए.पी.ई.सी., 21 प्रशांत महासागरीय सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर-सरकारी मंच है जो पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
- इसका उद्देश्य संतुलित, समावेशी, सतत, नवाचार और सुरक्षित विकास और क्षेत्रीय आर्थिक समाकलन की गति को बढ़ाने के द्वारा क्षेत्र के लोगों को अधिक समृद्ध बनाना है।

कार्य

- यह एशिया-प्रशांत के सभी निवासियों की प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में भाग लेने में मदद करने हेतु काम करता है।

- ए.पी.ई.सी. सदस्य, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और वन एवं समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु पहलों को भी लागू करते हैं।
- ए.पी.ई.सी. सदस्यों में दुनिया की लगभग 40% आबादी, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 54% हिस्सा और विश्व व्यापार का लगभग 44% हिस्सा शामिल है।

नोट:

- भारत ने ए.पी.ई.सी. में सदस्यता प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया है और भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी से प्रारंभिक समर्थन मिला है।
- अधिकारियों ने विभिन्न कारणों से और यह मानते हुए भारत को शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की कि भारत, प्रशांत महासागर पर सीमा साझा नहीं करता बल्कि वर्तमान में शामिल सभी देश सीमा साझा करते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

6. **<u>विश्व शौचालय दिवस</u>**

- 19 नवंबर, 2018 को पूरे विश्व में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है।
- वर्ष 2018 की थीम: "वेन नेचर कॉल्स" थी।

संबंधित जानकारी

- विश्व शौचालय दिवस (डब्ल्यू.टी.डी.), वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों को प्रेरित करने हेतु 19 नवंबर को मनाया जाने वाला एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन दिवस है।
- विश्व शौचालय दिवस, वर्ष 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा स्थापित किया गया था।
- सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छता को प्राप्त करना और खुले में शौच को समाप्त करना है।
- विश्व शौचालय दिवस, इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस दिशा में कार्य करने के लिए लोगों को सूचित करने, व्यस्त करने और प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है।

भारत में विश्व शौचालय दिवस कार्यक्रम

- सरकार ने सुरक्षा कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीवर बहाव अथवा ओवरफ्लो के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले क्षेत्रीय स्टॉफ के द्वारा सीवर और सेप्टिक टंकियों की सफाई करने के लिए मानक कार्यान्वन प्रक्रियाएं (एस.ओ.पी.) जारी की हैं।
- मंत्रालय द्वारा एक शौचालय निगरानी उपकरण डैशबोर्ड लांच किया गया है जो शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के लिए प्रशासनिक और निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करेगा।
- यह उपकरण उनके क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रदान करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई करने में उनकी मदद करेगा।
- इन मामलों के अध्ययन पर राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता कार्यशाला में 'भारत के शहरी परिदृश्य में बदलाव: स्वच्छता पर सफलता की कहानियां' नामक किताब का विमोचन किया गया है।
- स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान शहरी क्षेत्रों में की गई गतिविधियों को दर्शाने हेतु एक कॉफी टेबल किताब और 'स्वच्छ शहरी भारत' एवं 'सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों पर सलाहकार' नामक दस्तावेजों को जारी किया गया है।
- विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन-2018 का आयोजन मुंबई में विश्व शौचालय संगठन और इकोसन सर्विसेज फाउंडेशन द्वारा किया गया था।
- स्वच्छ भारत विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी।
- उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद जिले के वाजिदपुर गांव में "शौचालय संसद" का आयोजन किया गया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

7. **<u>सरकार, कर्नाटक में कैंसर के रोगियों की देखभाल में सहायता कर रही है।</u>**

- आशा किरण, नामक गतिशील इकाई को किदवई मेमोरियल अर्बुदविज्ञान संस्थान, बैंगलोर पहुँचाने हेतु सी-डैक से भेजा गया है।

- कैंसर स्क्रीनिंग के लिए यह एक पूर्ण, आत्मनिर्भर गतशील चिकित्सा इकाई है, जिसमें सभी आधारिक निदान और अल्ट्रासाउंड स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, इसे पूर्णतया प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) द्वारा डिजाइन और सुसज्जित किया गया हैं।
- सी-डैक ने स्नोमेड सी.टी.-डाईकॉम के साथ संगततापूर्ण ढंग से अपना स्वयं का सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिससे कि रोगियों की डिजिटल मेडिकल इमेज और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्डों को 4जी कनेक्टीविटी का प्रयोग करके प्रेषित किया जा सकता है।

संबंधित जानकारी

प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)

- प्रगत संगणन विकास केंद्र, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इलेक्टॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नैंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

8. **<u>दक्षिण भारत में तितलियों के प्रवासन हेतु मानचित्रण परियोजना</u>**

- यह देश में इस प्रकार की पहली ऐसी पहल है जिसमें द फर्न्स नेचुरलिस्ट्स सोसाइटी (एफ.एन.एस.), वायनाड, त्रावनकोर प्राकृतिक इतिहास समाज (टी.एन.एच.एस.) और मालाबार प्राकृतिक इतिहास समाज (एम.एन.एच.एस.) दक्षिण भारत में तितलियों के प्रवासी रास्ते का मानचित्रण करने हेतु नागरिक विज्ञान परियोजना शुरू करने के लिए संयुक्त हुए हैं।
- सामान्यत: तितलियों का प्रवासन पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत के साथ अक्टूबर-नवंबर के दौरान मैदानों से घाटों की ओर होता है और दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन से ठीक पहले अप्रैल-मई के दौरान तितलियों का प्रवासन घाटों से मैदनों की ओर होता है।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में परंबिकुलम बाघ अभ्यारण्य (केरल), भारत के संरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है जहां पर विभिन्न प्रकार की तितलियों पायी जाती हैं।
- हाली ही में अभ्यारण्य में आयोजित एक सर्वेक्षण में तितलियों की 221 प्रजातियों को देखा गया, जिनमें से 11 प्रजातियां क्षेत्र के लिए स्थानिक प्रजातियां थी।

प्रमुख प्रजातियां

- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि मिल्कवीड तितलियों की चार प्रजातियों- दखन डार्क ब्लू बाघ, ओरिएंटल ब्लू बाघ, डबल ब्रांडेड ब्लैक कौआ और भारतीय सामान्य कौआ मुख्य रूप से प्रवासन में शामिल हैं।
- प्रवासन, दक्षिण भारत के मैदानी इलाकों से पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में होता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –वन्यजीवन एवं जैव विविधता

स्रोत-द हिंदू

9. **<u>9वां सी.जी.डी. बोली-प्रक्रिया चरण</u>**

- प्रधानमंत्री, 9वें सी.जी.डी. बोली-प्रक्रिया चरण के अंतर्गत 65 भौगोलिक क्षेत्रों (जी.ए.) में शहर गैस वितरण (सी.जी.डी.) परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
- यह 9वें चरण तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करने वाली देश की आबादी के लगभग आधे हिस्से के लिए सुविधाजनक, पर्यावरण-अनुकूल और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की घोषणा करेगा।

संबंधित जानकारी

सी.जी.डी. नेटवर्क

- सी.जी.डी. नेटवर्क का ध्यान देश के नागरिकों के लिए खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन (अर्थात पी.एन.जी.) और परिवहन ईंधन (अर्थात सी.एन.जी.) की उपलब्धता में वृद्धि करने पर केंद्रित हैं।
- सी.जी.डी. नेटवर्क का विस्तार प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करके औद्योगिक

और वाणिज्यिक इकाइयों को भी लाभान्वित करेगा।

प्राकृतिक गैस क्यों?

- प्राकृतिक गैस, कोयले और अन्य तरल ईंधन की तुलना में पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित और सस्ता ईंधन है।
- प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.), पेट्रोल की तुलना में 60 प्रतिशत और डीजल की तुलना में 45 प्रतिशत सस्ती है।
- समान प्रकार प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.), एल.पी.जी. के बाजार मूल्य की तुलना में 40 प्रतिशत सस्ती है।

अन्य

- भारत ने दिसंबर 2015 में सी.ओ.पी. 21 पेरिस सम्मेलन में वचन लिया था कि वह वर्ष 2030 तक, वर्ष 2005 के स्तर के कार्बन उत्सर्जन में 33 प्रतिशत तक कमी लाएगा।
- प्राकृतिक गैस, एक घरेलू रसोई ईंधन के रूप में और परिवहन क्षेत्र के साथ ही औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाईयों लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

10. **<u>फ्यूगो ज्वालामुखी इस वर्ष 5वीं बार फटा है।</u>**

फ्यूगो ज्वालामुखी

- यह ग्वाटेमाला में चिमलटिनेंगो, एस्कुएंतला और सैकटेपेक्यूज़ विभागों की सीमाओं पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
- यह हाल ही में जून 2018 में फटा था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर -1- भौतिक भूगोल

स्रोत- बी.बी.सी.

21.11.2018

1. **<u>आंध्र प्रदेश ने 'भूधार' पोर्टल लॉन्च किया है।</u>**

- आंध्र प्रदेश ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो आधार संख्या की तरह अद्वितीय पहचान संख्या के साथ लोगों के लिए भूमि रिकार्डों को उपलब्ध कराता है।
- "भूधार" एक 11 अंको का अद्वितीय पहचान कोड है जो राज्य में प्रत्येक कृषि भूमि स्वामित्व और ग्रामीण एवं शहरी संपत्तियों को अभिहस्तांकित किया गया है।
- दो प्रकार के भूधार कार्ड: ई-भूधार और एम-भूधार कार्ड उपलब्ध हैं।
- भूधार अद्वितीय पहचान कोड, राज्य में प्रत्येक कृषि भूमि स्वामित्व और ग्रामीण एवं शहरी संपत्तियों को अभिहस्तांकित किया गया है।
- एक कृषि भूमि स्वामित्व अथवा ग्रामीण अथवा शहरी संपत्ति के वैध मौलिक डेटा के आधार पर अस्थायी भूधार अभिहस्तांकित किया जाएगा, जो 99 से शुरू होगा जो यह दर्शाएगा कि यह अस्थायी भूधार है।
- अस्थायी भूधार संख्या, विवाद अथवा मुकदमेबाजी अथवा पुर्नपंजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली भूमि को जारी की जाती है।

संबंधित जानकारी

- उपग्रह मानचित्रण के माध्यम से अपनी भूमि का विवरण देखने में लागो को सक्षम बनाने हेतु शीघ्र ही भू-संदर्भित सुविधा पेश की जाएगी।
- भुसेवा पोर्टल, किसी विशिष्ट भूमि अथवा संपत्ति के सारे हस्तांतरणों से संबंधित जानकारी एकल स्रोत में प्रदान करेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण पोर्टल

स्रोत- द हिंदू

2. **<u>वज्र प्रहार: भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास</u>**

- वज्र प्रहार नामक भारत, अमेरिका संयुक्त विशिष्ट सैन्य युद्धाभ्यास 2018, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है।
- यह युद्धाभ्यास आतंकवाद के हमलों से निपटने के लिए दोनों देशों के विशेष बलों के मध्य आयोजित किया गया है और इसे इकाई एवं उप-इकाई स्तर पर भी आयोजित किया गया है।

संबंधित जानकारी

- इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के दलों को बंधक बचाव, व्यवधान निर्माण, मरूस्थलीय उत्तरजीविता, चिकित्सा सहायता और युद्ध के मैदान जैसे पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के

अंत में वे अपने सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को प्रमाणित करने हेतु तीन दिवसीय मैदानी अभ्यास करेंगे।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- द हिंदू

3. **इग्ला-एस. मिसाइल प्रणाली**

- भारतीय सेना ने रूस की इग्ला-एस. मिसाइल प्रणाली को मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणालियों (एम.ए.एन.पी.ए.डी.एस.) हेतु अपने कई बिलियन डॉलर के अनुबंध के विकल्प के रूप में चुना है।
- यह रूसी एम.ए.एन.पी.ए.डी.एस. (मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली) तकनीक का नवीनतम संस्करण है।
- यह भारत को पहले आपूर्ति की गई एस.ए.-18 मिसाइलों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती हैं।
- इसे प्राकृतिक (पृष्ठभूमि) अव्यवस्थाओं और प्रत्युपायों की उपस्थिति में सामरिक विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन (यू.ए.वी.), क्रूज मिसाइल, आमने-सामने अथवा पीछे की ओर जैसे छोटी दूरी के दृश्य हवाई लक्ष्यों के विरूद्ध उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह मिसाइल रूस के रोसोबोरॉनएक्सपोर्ट कार्पोरेशन द्वारा विकसित की गई है।

संबंधित जानकारी

मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली

- मानव-पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, कंधे द्वारा सतह से हवा में मार की जाने वाली मिसाइल हैं।
- ये सामान्यत: निर्देशित हथियार होते हैं और कम उड़ान वाले विमानों विशेष रूप से हेलीकॉप्टरों के लिए खतरनाक होते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **कम्बाला (एक पारंपरिक कीचड़-मार्ग भैंस दौड़ प्रतियोगिता)**

- दक्षिणा कन्नड़ और उडुपी (कर्नाटक) के तटीय जिलें, कम्बाला जिला समिति के तत्वाधान में आयोजित की जाने वाली कम्बाला (पारंपरिक कीचड़-मार्ग भैंस दौड़ प्रतियोगिता) के लिए तैयार हैं।
- कम्बाला, पारंपरिक रूप से एक साधारण खेल है जो क्षेत्र के ग्रामीण लोगों का मनोरंजन करता है।
- कम्बाला का दौड़ का मैदान एक कीचड़युक्त धान का मैदान है।
- इस खेल का जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी माना जाता है।

संबंधित जानकारी

- कर्नाटक सरकार ने पशु (कर्नाटक संशोधन) अध्यादेश, 2017 में क्रूरता की रोकथाम की घोषणा की थी।
- राष्ट्रपति ने कर्नाटक में कम्बाला को वैध ग्रामीण खेल बनाने हेतु पशु (कर्नाटक संशोधन) विधेयक में क्रूरता की रोकथाम को अपनी सहमति प्रदान की है।
- इस विधेयक में कम्बाला और बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता को पशु (पी.सी.ए.) अधिनियम, 1960 में क्रूरता की रोकथाम के दायरे से बाहर रखने की उम्मीद है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

5. **सरकार ने एयरसेवा 2.0 का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है।**

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई दिल्ली में एयरसेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उन्नत संस्करण लांच किया है।
- वेब पोर्टल के एक उन्नत संस्करण में बड़े सुधार किए गए हैं जिसमें सोशल मीडिया पर सुरक्षित साइन-अप और लॉग-इन, यात्रियों के समर्थन के लिए चैटबॉट, सोशल मीडिया शिकायतों सहित बेहतर शिकायत प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं।
- यह यात्रियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा।

- यह हैशटैग(#) एयरसेवा का उपयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायतों को पंजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करेगा।
- यह देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों से चल रही उड़ानों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा जिसमें वास्तविक समय में फ्लाइट की स्थिति और फ्लाइट सारिणी का विवरण शामिल है।
- यह सभी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करेगा जिसमें विकलांगों अथवा अकेले अवयस्कों को सहायता प्रदान करना शामिल है, यह सुविधाएं और सेवाएं पूरे भारत के हवाईअड्डों पर उपलब्ध हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

6. **<u>हाथी गलियारों के लिए पारिस्थिकी-संवेदनशील क्षेत्र</u>**

- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से देश में सभी हाथी गलियारों को पारिस्थिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने पर विचार करने के लिए कहा है।
- यह कदम हाथी गलियारों और हाथी अभ्यारण्यों के कानूनी संरक्षण हेतु उठाया गया हैं जिससे संरक्षित क्षेत्रों की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं।

संबंधित जानकारी

पारिस्थिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.ए.)

- पारिस्थिकी-संवेदनशील क्षेत्र, भारत सरकार के पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- ई.एस.जेड. घोषित करने का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करने के द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में कुछ प्रकार के "शॉक अब्जार्वर" बनाना है।
- वे उच्च संरक्षित क्षेत्रों से निम्न संरक्षित क्षेत्रों की ओर संक्रमण क्षेत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं।

ई.एस.ए. घोषित करने के लिए मानदंड

- एम.ओ.ई.एफ. ने ई.एस.ए. घोषित करने के लिए मानकों और मानदंडो को निर्धारित करने वाले दिशानिर्देशों के एक व्यापक सेट को मंजूरी प्रदान की है।
- एम.ओ.ई.एफ. द्वारा गठित एक समिति ने इसे संयुक्त रखा है।
- दिशानिर्देश इस आधार पर मानदंड निर्धारित करते हैं कि किन क्षेत्रों को ई.एस.ए. के रूप में घोषित किया जा सकता है। इनमें प्रजाति आधारित (स्थानिक, दुर्लभ इत्यादि), पारिस्थितिक तंत्र-आधारित (पवित्र पेड़, सीमावर्ती वन आदि) और भू-आकृति विज्ञान विशेषता आधारित (निर्वासित द्वीप, नदियों की उद्गम आदि) शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरणीय मुद्दा

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट</u>**

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 'वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2019' जारी की है।
- यह रिपोर्ट, गुणवत्ता शिक्षा से लाभ प्राप्त करने हेतु प्रवासी और शरणार्थी बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने में देशों की उपलब्धियों और कमियों को दर्शाती है।
- रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2000 से आज पूरे विश्व में विद्यालय जाने वाले बच्चों की आयु के प्रवासी और शरणार्थियों की संख्या में 26% की वृद्धि हुई है और वे आधी मिलियन कक्षाएं भर सकते हैं।
- यह पाया गया है कि भारत के ग्रामीण परिवारों में साक्षरता स्तर, मौसमी प्रवासन के साथ घट जाता हैं।

- यह रिपोर्ट कहती है कि 80% मौसमी प्रवासी बच्चें शिक्षा के अभाव में रहते हैं और लगभग 40% प्रवासियों को काम नहीं मिलता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण क्षेत्र, अल्पकालिक प्रवासियों को बहुतायत में अवशोषित करता है।
- यह रिपोर्ट मौसमी प्रवासन में शामिल बच्चों से संबंधित मुद्दों को निपटाने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदमों को स्वीकृति प्रदान करती है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –सामाजिक न्याय

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग ग्रांड चैलेंज का अनावरण किया है।</u>**

- प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग ग्रांड चैलेंज का अनावरण किया है।
- इस चुनौती का उद्देश्य वर्तमान तकनीकियों का उपयोग करते हुए जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करने हेतु भारत की युवा क्षमताओं, स्टार्टअप और अन्य निजी उद्यमों का लाभ उठाना है।
- यह भारत को दुनिया में व्यापार करने हेतु सबसे सुगम स्थानों में से एक बनाने हेतु सरकार के संकल्प का परिणाम है।
- इस चुनौती का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गहन डेटा विश्लेषण, ब्लॉकचेन और अन्य अग्रणी तकनीक पर नवाचार विचारों को आकर्षित करना है।
- इस ग्रांड चैलेंज के लिए स्टार्ट अप इंडिया पोर्टल पर मंच प्रदान किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में, भारत ने विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में 190 देशों के मध्य 77वां स्थान प्राप्त किया है, इस वर्ष भारत ने वर्ष 2017 में प्राप्त 100वें स्थान की तुलना में 23 स्थानों की रिकॉर्ड छलांग लगाई है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

9. **<u>वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में तीन अन्य आक्रामक विदेशी पौधे पाए गए हैं।</u>**

- केरल वन अनुसंधान संस्थान से ज्ञात हुआ है कि कई पौधों ने नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व में अपने आक्रामक प्रकृति को दर्शाना शुरू कर दिया है, जिसमें वायनाड वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है।
- यहां पर देश में एशियाई हाथियों और बाघों का प्रमुख आवास है।
- आक्रामक प्रजातियों में शामिल हैं-

1. लेमन बेसिल अथवा टी बुश (ओसिममग्रेटिस्सीमम)

- लेमन बेसिल एक सुगंधित बारहमासी जड़ी बूटी है।
- यह मुख्य रूप से अफ्रीका और मेडागास्कर में पायी जाती है।

1. लाल-फूल रैग पत्ती (क्रॉसोसेफालमक्रिपिडाइअऑइस)

- लाल-फूल रैग पत्ती, एक रसीली जड़ी बूटी है।
- इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पायी जाने वाली सबसे आक्रामक खरपतवारों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1. नीली नागार्जुनी अथवा लाल मिर्च नागर्जुनी (स्टार्चीटारफेटासायनेंसिस)

- "लाल मिर्च नागर्जुनी एक बारहमासी सदाबहार जड़ी बूटी है।
- यह मुख्यत: दक्षिण और मध्य अमेरिका और कैरीबियाई में पायी जाती है।

संबंधित जानकारी

आक्रामक प्रजातियां

- एक आक्रामक प्रजाति, ऐसी प्रजाति होती हैं जो एक विशिष्ट स्थान (एक प्रख्यात प्रजातियां) की मूल निवासी नहीं होती हैं और यह पर्यावरण, मानव अर्थव्यवस्था अथवा मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखती है।

लक्षण

- आक्रामक प्रजातियों में सामान्यत: उच्च यौन प्रजनन क्षमता होती है।
- अलैंगिक पुनर्उत्पादन करने की क्षमता होती है।
- फैलाव और आवास दक्षता होती है।

- पर्यावरणीय विषमता और गड़बड़ी के प्रति एक उच्च सहनशीलता होती है।
- देशीय प्रजातियों की तुलना में पर्यावरणीय तनाव (प्ररूपी नमनीयता) के प्रति एक उच्च अनुकूलन क्षमता होती है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

10. **<u>भारत, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग पर दो स्थान खिसककर 53 वें स्थान पर आ गया है।</u>**

- आई.एम.डी. बिजनेस स्कूल स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किए जाने वाले वैश्विक वार्षिक प्रतिभा रैंकिंग में भारत दो स्थान नीचे खिसककर 53 वें स्थान पर आ गया है।
- स्विट्जरलैंड ने लगातार पांचवें वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, स्विटजरलैंड के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड शीर्ष पांच स्थानों पर हैं।
- सिंगापुर ने सूची में 13वां वैश्विक स्थान प्राप्त कर एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यह वैश्विक रैंकिंग, प्रतिभा को विकसित करने, आकर्षित करने और बनाए रखने के क्षेत्र में 63 देशों को स्थान प्रदान करती है।
- चीन को शिक्षा पर सार्वजनिक व्ययों के स्तर के साथ विदेशी कामगारों को आकर्षित करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण सूची में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है जो अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के औसत से भी कम है।
- रैंकिंग, तीन कारकों: निवेश और विकास, अपील और तत्परता पर आधारित होती है।
- इन कारकों में वे संकेतक भी शामिल होते हैं जो स्थानीय प्रतिभा को विकसित करने में निवेश किए गए संसाधनों को प्राप्त करते हैं, किस सीमा तक कोई देश प्रतिभा को आकर्षित करता है और बनाए रखता है और प्रतिभा के सागर में उपलब्ध कौशल की गुणवत्ताएं को विकसित करते हैं।

भारत के संदर्भ में-

- वर्ष 2017 की 55वें स्थान की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 53वां है।
- देश ने अपने प्रतिभा टोकरी (तत्परता कारक, 30 वां स्थान) की गुणवत्ता के संदर्भ में औसत से ऊपर का प्रदर्शन किया है।
- दूसरी तरफ, इसकी शैक्षणिक प्रणाली की गुणवत्ता और सार्वजनिक शिक्षा में निवेश की कमी ने देश की प्रतिभा क्षमता (निवेश और विकास कारक, 63वां स्थान) को कठोर रूप से दंडित किया है।

टॉपिकजी. एस. पेपर-3 आर्थिक विकास

स्रोत- टाइम्स ऑफ इंडिया

22.11.2018

1. **<u>सेंटिनेलिस आदिवासी</u>**

- कथित तौर पर, अंडमान और निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में संरक्षित सेंटिनेलिस आदिवासियों से संबंधित लोगो द्वारा अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी गई है।

संबंधित जानकारी

सेंटिनेलिस कौन हैं?

- सेंटिनेलिस, एक नीग्रो जनजाति है जो अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहती है, इस द्वीप में प्रवेश करना प्रतिबंधित है और यह जनजाति बाहरी लोगों के प्रति हिंसक है।
- यहां के निवासी भौतिक एवं भाषाई समानताओं के आधार पर जरावा से संबंधित हैं।
- भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा की गई रसोई मिडेंस की कार्बन डेटिंग के आधार पर इस द्वीप पर पिछले 2,000 वर्षों से इस जनजाति की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी।

वे किस प्रकार संरक्षित हैं?

- जनजातियों द्वारा घेरे गए पारंपरिक क्षेत्र को रिजर्व घोषित करने और इस क्षेत्र में अनुज्ञा प्राप्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने हेतु भारत सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 जारी किया था।
- जनजातीय सदस्यों की तस्वीर खींचना अथवा उन्हें फिल्माना भी एक अपराध है।

आबादी

- वर्ष 1901 से वर्ष 1921 तक उनकी जनसंख्या 117 होने का अनुमान लगाया गया था।
- वर्ष 1931 में यह संख्या घटकर 50 हो गई थी, वर्ष 1961 की जनगणना के लिए भी इन्हीं आकड़ों का प्रयोग किया गया था।
- वर्ष 1991 में उनकी संख्या 23 दर्ज की गई थी।
- जनगणना 2001 ने 39 निवासियों की गणना की गई थी।

नोट: - अन्य भारतीय जनजातियां आंगेस, जरावा और ग्रेट अंडमानी हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

2. **<u>हिमाचल सरकार ने सशक्त महिला योजना को मंजूरी प्रदान की है।</u>**

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सशक्त महिला योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है।
- सशक्त महिला योजना का दृष्टिकोण ग्रामीण महिलाओं को संगठन और सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एक इंटरफेस प्रदान करके सशक्त बनाना है।
- यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका अवसरों से जोड़ेगी और प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल में सुधार करेगी।

संबंधित जानकारी

हिमाचल प्रदेश द्वारा महिला सशक्तिकरण से संबंधित अन्य योजनाएं

महिलाओं हेतु स्व रोजगार सहायता

- इस योजना में 35000 रूपए तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को किसी भी परियोजना अथवा उद्यम की स्थापना हेतु 2500 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

महिला विकास निगम

- महिला विकास निगम का उद्देश्य सब्सिडी ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके महिलाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्सहन योजना

- इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवाओं और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण हेतु काम कर रहे व्यक्तियों/ संगठनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

टॉपिक-जी.एस. पेपर 2–महिला सशक्तीकरण हेतु योजना

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (ए.क्यू.एल.आई.)</u>**

- हाल ही में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो (ई.पी.आई.सी.) में ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा ए.क्यू.एल.आई. जारी किया गया है।
- यह एक नया सूचकांक है जिसमें 'एल.' जोड़ा गया है - जो 'जीवन' को दर्शाता है- मानक वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) के लिए वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (ए.क्यू.एल.आई.) नामक नए सूचकांक को जारी किया गया है।
- यह सूचकांक उस अध्ययन पर आधारित है जो लंबे समय तक कणिका प्रदूषण में मानव के रहने और जीवन प्रत्याशा के मध्य सामयिक संबंधों को प्रमाणित करता है।
- इस सूचकांक में पाया गया है कि जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होने वाला कणिका वायु प्रदूषण, वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा को 1.8 वर्ष कम करता है।
- यह सूचकांक दर्शाता है कि जीवन प्रत्याशा पर कणिका प्रदूषण के प्रभाव, तपेदिक और एच.आई.वी./एड्स रोगों जैसी संक्रामक बीमारियों, व्यवहरिक धूम्रपान और युद्ध के प्रभावों से भी कहीं अधिक हैं।

संबंधित जानकारी

- यह सूचकांक उस अध्ययन पर आधारित है जो लंबे समय तक कणिका प्रदूषण में मानव के रहने और जीवन प्रत्याशा के मध्य सामयिक संबंधों को प्रमाणित करता है।
- अंतिम परिणामों तक पहुँचने के लिए इन अध्ययनों से प्राप्त परिणामों को उच्च-स्थानिक, वैश्विक कणिका तत्व मापकों के साथ संयुक्त करते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3–पर्यावरण

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

4. **<u>जलवायु परिवर्तन पर बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक</u>**

- हाल ही में पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में बेसिक समूह देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई है।
- यह बैठक दिसंबर, 2018 में कैटोवाइस, पोलैंड में होने वाले संयुक्त राष्ट्र पार्टी सम्मेलन (सी.ओ.पी.) से काफी पहले आयोजित की गई है।
- बेसिक समूह ने उन्नत देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते के प्रभावी कार्यान्वन में विकासशील देशों के प्रति अपने समर्थन को बढ़ाने का आग्रह किया है।

संबंधित जानकारी

बेसिक

- बेसिक देश, चार बड़े नए औद्योगिक देशों- ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का गुट (भूराजनीतिक संधि) है।
- यह नवंबर, 2009 में एक समझौते द्वारा गठित किया गया था।
- इस समूह ने कोपेनहेगन जलवायु शिखर सम्मेलन 2009 में संयुक्त रूप से कार्य करने का वचन लिया था, यदि जलवायु वार्ताओं के दौरान विकसित देशों द्वारा उनकी सामान्य न्यूनतम स्थितियां नहीं पाई जाती हैं तो इसमें संभावित संयुक्त वॉक आउट भी शामिल है।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.) को लागू करने का वचन लिया था।
- देशों ने विकसित देशों से संगठित करने हेतु वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उनके जलवायु वित्त वचनबद्धता को स्पष्ट करने का आग्रह किया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. **<u>इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018</u>**

- विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने शांति, अशस्त्रीकरण और विकास हेतु 2018 इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है।
- शांति, अशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए रचनात्मक प्रयासों को पहचानने में व्यक्तियों अथवा संगठनों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो यह सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता की भलाई और स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाने में किया जा रहा है।

संबंधित जानकारी

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र

- विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सी.एस.ई.) नई दिल्ली, भारत आधारित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक अनुसंधान एवं वकालत संगठन है।
- सी.एस.ई. भारत में पर्यावरण-विकास के मुद्दों पर एक विशेषज्ञ दल के रूप में कार्य करता है। खराब योजनाएं और जलवायु परिवर्तन भारत के सुंदरबनों को नष्ट कर रही हैं।
- इसके अतिरिक्त यह नीति परिवर्तनों और पहले से चल रही नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन की वकालत भी करता है।
- सी.एस.ई. समस्याओं और प्रस्तावित सतत समाधानों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु ज्ञान आधारित सक्रियता का उपयोग करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण पुरस्कार

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>कार्बन पदचिन्हों को कम करने हेतु एक वास्तविक जलवायु शिखर सम्मेलन</u>**

- माजुरो की राजधानी, मार्शल में आयोजित होने वाले एक अभिनव जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में पूरे विश्व के नेता भाग लेंगे।

- यह शिखर सम्मेलन पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, अत: यह कार्बन उदासीन है।
- यह कई अन्य अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक शिखर सम्मेलनों के कठोर विरोध में एक पारिस्थिकी-अनुकूल कार्यक्रम है, जिसमें पूरी दुनिया से हजारों प्रतिनिधि हवाई जहाजों से कार्यस्थल पर पहुँचते हैं और एयर-कंडीशंड कमरों में ठहरते है।
- वास्तविक जलवायु शिखर सम्मेलन, मार्शल द्वीप समूह के राष्ट्रपति हिलदा हीन के दिमाग की उपज है।
- वास्तविक शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देहली उद्देश्य को प्राप्त किया जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु अभूतपूर्व वैश्विक कार्रवाई नहीं हो पाएगी।

संबंधित जानकारी

पेरिस जलवायु समझौते 2016 के लक्ष्य

- इस शताब्दी के वैश्विक तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तर से अधिक और 2 डिग्री सेल्सियस से कम की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।
- 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयास करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु देशों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

देशों द्वारा CO2 का प्रतिशत उत्सर्जन

- चीन> संयुक्त राज्य अमेरिका> यूरोपीय संघ> भारत

गैसों का वैश्विक उत्सर्जन

- CO2> CH4> N2O > फ्लुओरीनकृत गैसें

कार्बन टैक्स

- कार्बन टैक्स, एक शुल्क है जो जीवाश्म ईंधन के उपयोगकर्ताओं को उनके ईंधन उपयोग से वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन द्वारा होने वाली जलवायु क्षति के लिए भुगतान करना होगा। यह स्वच्छ ऊर्जा के प्रति लागो को प्रेरित भी करेगा।

कार्बन पदचिह्न

- किसी भी व्यक्ति, समूह, संगठन इत्यादि द्वारा एक समयावधि के दौरान ग्रीनहाउस उत्सर्जनों का कुल उत्सर्जन है।

कार्बन समायोजन

- किसी भी स्थान पर होने वाले जी.एच.जी. के उत्सर्जन की भरपाई करने हेतु जी.एच.जी. के उत्सर्जन को कम करना अथवा जी.एच.जी. के उत्सर्जन को समायोजित करना।

कार्बन क्रेडिट

- यह मूल रूप से एक कार्बन बाजार है।
- देशों को जी.एच.जी. के कुछ निश्चित टनों का उत्सर्जन करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।
- इसके बदले में वे स्वयं की इकाईयों के अंतर्गत इस मात्रा को वितरित करते हैं।
- जो इकाइयां उत्सर्जन मात्राओं का उपयोग नहीं कर पाती हैं वे इसे अन्य खिलाड़ियों, निजी अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेंच सकती हैं।

नोट:

- मार्शल द्वीप समूह, जलवायु परिवर्तन से समुद्री स्तर बढ़ने के प्रति संवेदनशील राष्ट्र है, यह पहला देश है जिसने वर्ष 2025 तक वर्ष 2010 के स्तर से कम से कम 32 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वर्ष 2030 तक कम से कम 45 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र में दो संकल्प पत्र जमा किए हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –महत्वूपर्ण समिति

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>डब्ल्यू.एच.ओ. विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2018</u>**

- भारत अधिक समय तक मलेरिया के मरीजों की अधिक संख्या के कारण शीर्ष तीन देशों में नहीं रहेगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, 11 सबसे अधिक मलेरिया प्रभावित देशों में से केवल भारत ऐसा देश है

जिसने इस बीमारी के प्रभाव को घटाने के मामले में प्रगति दर्शायी है।

- वर्ष 2016 की तुलना में देश ने वर्ष 2017 में 24 प्रतिशत की कमी दर्ज कराई है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. ने पराग्वे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है, अमेरिका में 45 वर्षों में यह दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश है।
- तीन अन्य देशों अल्जीरिया, अर्जेंटीना और उज़्बेकिस्तान ने डब्ल्यू.एच.ओ. से आधिकारिक मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण का अनुरोध किया है।

संबंधित जानकारी

मलेरिया

- मलेरिया, एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम वर्ग से संबंधित परजीवी के कारण होती है, जो संक्रिमत मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के द्वारा फैलती है।
- मच्छर से होने वाले रक्त रोग की रोकथाम और इलाज उपलब्ध है।

मतिबाबू डिवाइस

- यह मलेरिया का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक गैर-आक्रामक परीक्षण किट है।
- यह एक कम लागत की और पुन:प्रयोग की जा सकने वाली डिवाइस है जिसका प्रयोग मलेरिया का शीघ्र परीक्षण करने हेतु किया जा सकता है।
- इसे युगांडा में विकसित किया गया था।
- यह मौजूदा परीक्षण विधियों के विपरीत है जिनमें परीक्षण के लिए खून की आवश्यकता होती है, 'मातीबाबू' एक "रक्तहीन" परीक्षण है।
- 'मतिबाबू' युगांडा जैसे कम आय वाले क्षेत्रों में मलेरिया का सहज इलाज प्रदान कर सकता है।
- इस डिवाइस और अनुप्रयोग को 'इंजीनियरिंग नवाचार हेतु अफ्रीका पुरस्कार' 2018 में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है- यह महाद्वीप में इंजीनियरिंग नवाचार को समर्पित एक पुरस्कार है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण रिपोर्ट

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>एच.आर.डी. मंत्रालय ने ए.आई.सी.टी.ई. में इनोवेशन सेल की स्थापना की है।</u>**

- एच.आर.डी. मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) में एक इनोवेशन सेल की स्थापना की है।
- इसका उद्देश्य पूरे देश में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एच.ई.आई.) में नवाचार संवर्धन के बारे में नए विचारों पर मंथन करना है।
- यह स्टार्ट-अप और उद्यम स्थापित करने हेतु नए विचारों और नवाचारों पर कार्य करने और उन्हें बढ़ावा देने हेतु हमारे छात्रों की रचनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा।
- एम.एच.आर.डी. का इनोवेशन सेल (एम.आई.सी.) पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो विचार-विमर्श से प्री इन्क्यूबेशन, इन्क्यूबेशन और सफल स्टार्ट-अप के समान धीरे-धीरे इन्क्यूबेटर के रूप में विचार उत्पादन से सभी शैक्षिक संस्थानों में नवाचार की परंपरा को बढ़ावा देगा।
- एम.आई.सी. नवाचार के अग्रभाग में संस्थानों की पहचान करने हेतु रैंकिंग प्रणाली को डिजाइन करने पर भी काम करेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –शिक्षा नीतियां

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

23.11.2018

1. **<u>यू.पी. सरकार ने नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया है।</u>**

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान अथवा महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया है।
- इस अभियान का उद्देश्य राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है।
- इसमें शिक्षा, स्व-रोज़गार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण जैसे कई मुद्दे शामिल हैं।
- अभियान के दौरान, राज्य सरकार की महिला अधिकारी और महिला कर्मचारी प्रत्येक जिले में अपने संबंधित ब्लॉक के गांवों में घरों में जाएंगी

और महिलाओं को उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सूचित और शिक्षित करेंगी।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महिला सशक्तीकरण

स्रोत- ए.आई.आर.

2. **<u>सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018</u>**

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एवं सेवाओं के नियमन और मानकीकरण के लिए सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 को मंजूरी प्रदान की है।
- इस विधेयक में एक भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद और संबंधित राज्य सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशों के लिए एक मानक निर्धारक और सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाएंगी।

संबंधित जानकारी

विधेयक के प्रमुख प्रभाव

- परिषद की स्थापना की तिथि से लेकर अगले कुछ वर्षों के दौरान सभी वर्तमान के सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल इससे जुड़ेंगे।
- यह सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की व्यावसायिकता को सक्षम बनाने के द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योग्य, अत्यंत कुशल और उपयुक्त रोजगारों को सृजित करने का अवसर प्रदान करेगा।
- आयुष्मान भारत के दृटिकोण के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली विविध स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो पाएंगी, जिससे'डॉक्टर आधारित' मॉडल के स्थान पर 'सुगम्य सेवा एवं टीम आधारित' मॉडल की ओर अग्रसर होना संभव हो पाएगा।
- स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यबल की वैश्विक मांग (किल्लत) पूरी करने का अवसर प्राप्त होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) की वैश्विक कार्यबल, 2030 रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यबल की वैश्विक मांग वर्ष 2030 तक लगभग 15 मिलियन रहने का अनुमान लगाया गया है।

लाभार्थी

- यह अनुमान लगाया गया है कि सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 से देश में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 8-9 लाख मौजूदा सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रोफेशनल लाभान्वित होंगे।
- इस विधेयक का उद्देश्य मुहैया कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक से देश की पूरी आबादी और समग्र रूप से समूचा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र लाभान्वित होगा।

इस विधेयक की आवश्यकता है?

- सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, स्वास्थ्य मानव संसाधन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं।
- कुशल और सक्षम सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, स्वास्थ्य सेवा की लागत को कम कर सकते हैं और गुणवत्ता संचालित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की वर्तमान स्थिति में यहां पर कई सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर मौजूद है, जो अज्ञात, अनियमित और न्यून उपयोगी हैं।
- इस विधेयक का ध्यान हमारी प्रणाली विभिन्न प्रोफेशनलों जैसे कि डॉक्टरों, नर्सों और अग्रणी पंक्ति में रहने वाले कामगारों (जैसे कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य सेवा सहायिका अथवा आशा, सहायक नर्स मिडवाइफ अथवा ए.एन.एम.) की सीमित श्रेणियों को सुदृढ़ करने पर अत्यंत केन्द्रित है।
- इसे ध्यान में रखते हुए विधेयक में एक सुदृढ़ नियामकीय रूपरेखा या व्यवस्था स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशों के लिए एक मानक-निर्धारक एवं नियामक की भूमिका निभाएगी।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **भारत और उजबेकिस्तान ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और उजबेकिस्तान के मध्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर किए गए समझौते से अवगत कराया गया है।
- इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

लाभ:

- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होगा, क्यों कि अब दोनों देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पारस्परिक हितों के महत्वपूर्ण अभिसरण से प्रेरित पूरक शक्तियों का लाभ उठाएंगे।
- हितधारकों में वैज्ञानिक संगठनों, अकादमियों, आर. एंड डी. प्रयोगशालाओं के शोधकर्ता और भारत और उजबेकिस्तान के उद्योग शामिल होंगे।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत-पी.आई.बी.

4. **भारत में ओटलन बंटिंग**

- ओटलन बंटिंग, एक छोटा सा पक्षी है जो मंगोलिया से यूरोप तक में पायी जाने वाली नस्ल है और मध्य पूर्व से होते हुए अफ्रीका में जा बसती है।

वितरण और निवास

- ये पक्षी अधिकांश यूरोपीय देशों और पश्चिमी एशिया के मूल निवासी हैं।
- यह उत्तर में स्कैंडिनाविया तक और आर्कटिक वृत्त के बाहर तक चले जाते हैं, जो उनके आवर्ती कॉर्नफील्ड और पड़ोसी हैं।
- लुप्तप्राय प्रजातियों की प्रकृति रेडलिस्ट के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ ने वर्ष 2018 में ओटलन बंटिंग पक्षी को "कम चिंता" की श्रेणी में रखा है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –जैवविविधता एवं पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

5. **भारत और पाकिस्तान, करतारपुर गलियारे के लिए प्रतिबद्ध हैं।**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण और विकास को मंजूरी प्रदान की है।
- यह गलियारा भारत के तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद करता है, जहां श्री गुरु नानक देव जी ने अठारह वर्ष बिताए थे।
- पाकिस्तान सरकार से सिख समुदाय की भावनाओं को समझने और अपने क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाओं के साथ एक गलियारे को विकसित करने का आग्रह किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

गुरु नानक

- गुरु नानक, सिक्ख धर्म के संस्थापक थे और दस सिक्ख गुरुओं में से पहले गुरू थे।
- उनके जन्मदिन को पूरे विश्व में कार्तिक पूर्णमासी के अवसर पर गुरु नानक गुरुपुरब के रूप में मनाया जाता है।
- गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, पाकिस्तान में उन्होंने 18 वर्षों तक विश्राम किया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

6. **मंत्रिमंडल ने समग्र योजना 'ए.सी.आर.ओ.ओ.एस.' का कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है।**

- मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने वर्ष 2017-2020 के दौरान समग्र योजना'एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च - मॉडलिंग आबर्जविंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज (ए.सी.आर.ओ.एस.एस.) की नौ उप-योजनाओं को जारी रखने की अनुमति प्रदान की है।
- इन योजनाओं का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.), नेशनल

सेंटर फॉर मीडियम रेंज वैदर फॉरकास्टिंग (एन.सी.एम.आर.डब्लयू.एफ.) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) जैसे अपने संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा।

- सी.सी.ई.ए. ने वर्ष 2020-21 और इससे आगे की अवधि के दौरान नेशनल फेसिलिटी फॉर एयरबोर्न रिसर्च (एन.एफ.ए.आर.) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है।

संबंधित जानकारी

'ए.सी.आर.ओ.ओ.एस.' योजना

- 'ए.सी.आर.ओ.ओ.एस.' योजना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है।
- यह मौसम और जलवायु सेवाओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएगा, जिसमें चक्रवात, तूफान की बढ़त, गर्म हवाएं, आंधी आदि के लिए चेतावनियां शामिल होंगी।
- 'ए.सी.आर.ओ.ओ.एस.' योजना का उद्देश्य समाज के सुधार के लिए एक विश्वसनीय मौसम एवं जलवायु पूर्वानुमान प्रदान करना है।
- इसके द्वारा सार्वजनिक मौसम सेवा, आपदा प्रबंधन, कृषि-मौसम सेवाओं, विमानन सेवाओं, पर्यावरण निगरानी सेवाओं, हाइड्रो-मौसम सेवाओं, जलवायु सेवाओं इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाओं को समान लाभ के हस्तांतरण को सुनिश्चित करना है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2–महत्वूपर्ण योजना

स्रोत-पी.आई.बी.

7. **<u>भारत को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार मिला है।</u>**

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार के अंतर्गत वन्यजीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरों को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है।
- यह पुरस्कार ब्यूरो द्वारा पारगमन पर्यावरण अपराध का मुकाबला करने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है।
- डब्ल्यू.सी.सी.बी. ने अभिनव प्रवर्तन तकनीकों को अपनाया है जिसने भारत में पारगमन पर्यावरणीय अपराधों के प्रवर्तन में वृद्धि की है।
- विशेष रूप से, इसे पूरे भारत में वन्यजीव अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों को खोजने और अपराध में रुझानों का विश्लेषण करने में मदद करने के क्रम में रियल-टाइम डेटा प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन वन्यजीवन अपराध डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली पर विकसित किया गया है।
- रुझानों का विश्लेषण करने, निवारक उपायों को खोजने में मदद करने के साथ-साथ ऑपरेशन सेव कुर्मा, थंडरबर्ड, वाइल्डनेट, लेस्नो, बिरबिल, थंडरस्ट्रॉम, लेस्नो-II जैसे ऑपरेशनों का सफलतापूर्वक कार्यान्वन करने में अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ इस प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

8. **<u>मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए यौन उत्पीड़न पोर्टल ''शी-बॉक्स'' को केंद्रीय/ राज्य मंत्रालयों और जिलों से लिंक किया गया है।</u>**

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल''शी-बॉक्स'' को सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से लिंक किया है।
- शी-बॉक्स पर शिकायतों के त्वरित निपटान हेतु ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले केंद्र/ राज्य प्राधिकारी के पास सीधे पहुंच जाता है।
- शी-बॉक्स पर मामलों की निगरानी शिकायतकर्ताओं और डब्ल्यू.सी.डी. मंत्रालय द्वारा की जा सकती है, इससे मामले के निपटान में कम समय लगेगा।

संबंधित जानकारी

शी-बॉक्स

- शी-बॉक्स, डब्ल्यू.सी.डी. मंत्री द्वारा शुरू किया गया है जो देश में सभी महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, इसमें सरकारी और निजी कर्मचारी शामिल हैं।
- जो लोग यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत गठित संबंधित आंतरिक शिकायत समिति अथवा स्थानीय शिकायत समिति में पहले ही लिखित शिकायत दर्ज करा चुके हैं वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने के पात्र हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महिला सशक्तीकरण
स्रोत-पी.आई.बी.

24.11.2018

1. **<u>ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट: डब्लू.एम.ओ.</u>**

- विश्व मौसम संगठन ने अपनी वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट 'ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन' जारी की है जो वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है।
- रिपोर्टों में पाया गया है कि वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का स्तर एक नए आंकड़े पर पहुँच गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते स्तर की प्रवृत्ति में परिवर्तन के कोई संकेत नहीं है।

संबंधित जानकारी

- ये रिपोर्टें, आई.पी.सी.सी. 1.5 डिग्री सेंटिग्रेट रिपोर्ट की मदद करती हैं, जिसमें यह चेतावनी दी गई थी कि विश्व को वर्ष 2050 तक अनिवार्य रूप से कार्बन उदासीन होना आवश्यक है।
- डब्लू.एम.ओ. बुलेटिन, कैटोविस, पोलैंड में सी.ओ.पी. 24 में जलवायु वार्तालाप के प्रारंभ होने के ठीक पहले अथवा एक सप्ताह पहले प्रकाशित की जाती है, जहां पर सभी देश, पेरिस जलवायु समझौते के प्रति अभ्यासों और गर्म गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रति अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
- कार्बन डाईऑक्साइड के अतिरिक्त, डब्लू.एम.ओ. ने मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन का क्षय करने वाली सी.एफ.सी.-11 जैसी अन्य शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते स्तरों पर भी प्रकाश डाला है।

सी.एफ.सी.-11 गैस

- सी.एफ.सी.-11 के संदर्भ में कई रिपोर्टें हैं कि यह घर तपावरोधन में प्रयोग की जाने वाली गैस है।
- सी.एफ.सी.-11 ओजोन परत का क्षय करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है जब कि ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देती है।
- ओजोन परत की रक्षा करने हेतु वैश्विक समझौते 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत सी.एफ.सी.-11 के उत्पादन को बंद कर दिया गया था।

मेथेन

- मेथेन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और वायुमंडल में इसका लगभग 60% हिस्सा मवेशी खेती, चावल की खेती और जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण जैसी मानव गतिविधियों से उत्पन्न होता है।

नाइट्रस ऑक्साइड

- नाइट्रस ऑक्साइड, प्राकृतिक और मानव स्रोतों से उत्पन्न होती है जिसमें उर्वरक उपयोग और उद्योग भी शामिल हैं।
- अब यह पूर्व-औद्योगिक स्तर की लगभग 122 प्रतिशत है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –पर्यावरण मुद्दे
स्रोत- बी.बी.सी. न्यूज

2. **<u>सी.सी.ई.ए. ने जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंडों के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है।</u>**

- आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने जूट पैकेजिंग सामग्री (जे.पी.एम.) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के दायरे को विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है।
- इसने मंजूरी दी है कि अनाजों का 100% और चीनी का 20% उत्पादन अनिवार्य रूप से विविध जूट बैग में पैक किया जाएगा।

- प्रारंभ में, जी.ईएम. पार्टल पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से खाद्य अनाजों को पैक करने के लिए जूट बैग के 10% इंडेंट रखे जाएंगे।
- यह कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने, जूट क्षेत्र का विविधीकरण करने और जूट उत्पादों की मांग को बढ़ाने और बनाए रखने में मदद करेगा।
- भारत, विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक अथवा निर्माता (लगभग 60%) है, इसके बाद बांग्लादेश और चीन हैं।
- शीर्ष जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा हैं।

सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय-

- जूट आई.केयर के नाम से प्रसिद्ध, सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए अनुयोजन के माध्यम से कच्चे जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है।
- जूट क्षेत्र के विविधीकरण का समर्थन करने हेतु राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ मिलकर काम किया है और गांधीनगर में एक जूट डिजाइन इकाई खोली गयी है।
- जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से दिसंबर, 2016 में जूट स्मार्ट नामक एक ई-सरकारी पहल शुरू की गई है, जो सरकारी संस्थाओं द्वारा बी.-ट्विल बोरे भरने के कार्य की खरीद के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान कर रही है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – महत्वूपर्ण उद्योग

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>भारत मारिजुआना से उत्पन्न दवाओं का अध्ययन करेगा।</u>**

- आयुर्वेदिक औषधियों में अनुसंधान के संवर्धन हेतु भारत में तीन प्रमुख विज्ञान प्रशासक-वैज्ञानिक एंव औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- इस प्रकार के अध्ययनों में पहली बार सी.एस.आई.आर.- भारतीय समग्र औषधि संस्थान (सी.एस.आई.आर.-आई.आई.आई.एम.) और टाटा मेमोरियल सेंटर (टी.एम.सी.), मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान शुरू करने की संभावना है।
- मारिजुआना की चिकित्सकीय क्षमता का अध्ययन एक बड़े सरकारी प्रयास का हिस्सा है, जो आयुर्वैदिक और अन्य पारंपरिक दवा ज्ञान प्रणालियों में उल्लिखित जड़ी बूटियों और पौधों से नई दवाएं प्राप्त करने हेतु किया जा रहा है।

संबंधित जानकारी

मारिजुआना

- मारिजुआना, कैनाबिस सैतिवा- गांजे के पौधे की सूखी, कटी हुई पत्तियों, तनों, बीज और फलों का हरा-ग्रे रंग का मिश्रण है।
- ज्यादातर लोग मारिजुआना से धूम्रपान करते हैं, इसे अन्य रूपों जैसे कि खाने, पाउडर और तेलों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इसे कैंसर, तंत्रिका तंत्र रोगों, ग्लूकोमा, माइग्रेन इत्यादि जैसे चिकित्सा मुद्दों में दर्द को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग जी मिचलाने और एच.आई.वी. अथवा अन्य गंभीर बीमारियों वाले मरीजों की भूख में सुधार करने हेतु किया जाता है।
- कैनाबिस, अधिकांश देशों में प्रतिबंधित है लेकिन हाल के वर्षों में कई देशों ने इसका उपयोग शुरू कर दिया है।

भारत में इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है?

- कैनाबिस, भारत में प्राचीन काल से 2000 ईसा पूर्व से उपयोग किया जा रहा है।
- कैनाबिस के पौधे को वेदों में पांच पवित्र पौधों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।
- भांग, कैनाबिस से तैयार की गई एक खाद्य सामग्री है जिसे 'या तो पेय या धूम्रपान के रूप में ग्रहण किया जा सकता है'। होली और

महाशिवरात्रि के हिंदू त्यौहारों के दौरान इसका प्रयोग सामान्यत: किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 - स्वास्थ्य

स्रोत-पी.आई.बी.

4. **<u>केंद्र सूची में ओ.बी.सी. का उप-वर्गीकरण</u>**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग के कार्यकाल को 31 मई, 2019 तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है।

संबंधित जानकारी

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ अक्टूबर, 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पांच सदस्यों के आयोग का गठन किया था।
- इस आयोग के अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी हैं।
- इसकी रिपोर्ट में ओ.बी.सी. के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित उप-कोटा की सिफारिश करने की उम्मीद है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

5. **<u>मणिपुर में सांगई महोत्सव प्रारंभ हुआ है।</u>**

- संगाई महोत्सव, मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करता है, हप्ताकांगजीबंग में रोमांचक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है जो इम्फाल का ऐतिहासिक महल परिसर है।
- यह राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है, इस राज्य का नाम संगाई, एक पशु के नाम पर रखा गया है।
- इस महोत्सव का उद्देश्य मणिपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है।
- इस महोत्सव में आकर्षण के प्रमुख केंद्र मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राज्य में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों का कला के प्रति प्यार हैं।
- इसके अतिरिक्त यह बांस नृत्य, माईबी नृत्य, कबुई नागा नृत्य, लाई हरौबा नृत्य, खंबा थोईबी नृत्य आदि जैसे विभिन्न अन्य लोक नृत्यों के साथ राज्य के शास्त्रीय नृत्य रूप 'रास लीला' का प्रदर्शन भी करता है

संबंधित जानकारी

संगाई हिरण

- संगाई हिरण (रूसरवुसेल्डी) को नृत्य हिरण भी कहा जाता है।
- यह मणिपुर का राज्य पशु है।
- यह मणिपुर की स्थानिक प्रजाति है, एक बार यह मणिपुर घाटी पर प्रचुर मात्रा में पाए गए थे लेकिन अब केवल इसके शेष प्राकृतिक निवासी कीबुललामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (के.एल.एन.पी.) में पाए जाते हैं जो विश्व का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई.यू.सी.एन.) द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- कीबुललामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर की लोकटक झील में एक तैरता हुआ बायोमास है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

6. **<u>भारत, वर्ष 2019 में हैदराबाद में फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वें केंद्रीय विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा।</u>**

- फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वें केंद्रीय विश्व सम्मेलन का हैदराबाद में आयोजन किया जाएगा जो इस क्षेत्र में काम करने वाला एक वैश्विक संगठन है।
- इस सम्मेलन की थीम: "आपातकाल समाप्त करना: विज्ञान, नेतृत्व, कार्य" है।
- इसे टी.बी. पर पहली बार आयोजित की जाने वाली संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) उच्चस्तरीय बैठक और छुआ-छूत की बीमारियों पर तीसरी बार आयोजित की जाने वाली संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक के बाद आयोजित किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

क्षय रोग (टी.बी.)

- क्षय रोग (टी.बी.), एक रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी है जो आज के समय में एच.आई.वी./ एड्स जैसी भयानक बीमारियों की तुलना में अधिक लागों की जान ले रही हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा संक्रामक रोग है।
- विश्व में भारत में टी.बी. के सबसे ज्यादा मरीज हैं, भारत में वैश्विक रूप से रहने वाले चार में से एक व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है।
- वर्ष 2030 तक तपेदिक को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध विश्व के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक घोषणा में इस बैठक का समापन किया गया है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने का वचन लिया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –स्वास्थ्य से संबंधित महत्वूपर्ण सम्मेलन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **<u>वानुआतु: एक छोटे द्वीप राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जीवाश्म ईंधन उद्योगों पर कार्यवाही करने की धमकी दी है।</u>**

- वानुआतु के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि द्वीप राष्ट्र, उन जीवाश्म ईंधन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है जो निरंतर रूप से पर्यावरण का शोषण करती रहेंगी।
- उन देशों के लिए भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जो पर्यावरण शोषण और जलवायु परिवर्तन के परिणामी प्रभावों को रोकने में विफल होने हेतु उद्योगों को सुविधा प्रदान करते हैं।

संबंधित जानकारी

वानुआतु

- वानुआतु, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रशांत द्वीप देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 260,000 है।
- इस देश में 82 ज्वालामुखीय द्वीप शामिल हैं जो 1,280 कि.मी. समुद्र में फैले हुए हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

8. **<u>एम.एच.-60 आर. मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (एम.आर.एच.)</u>**

- हाल ही में भारत ने नौसेना के लिए 24 एम.एच.-60 आर. मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (एम.आर.एच.) की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) से औपचारिक अनुरोध किया है।
- वर्तमान में भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टरों की गंभीर कमी का सामना कर रही है।
- यह खरीद फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर हेलीकॉप्टरों की कमी को आंशिक रूप से कम करने में मदद करेगी और एकीकृत वायु एंटी-सबमरीन वारफेयर (ए.एस.डब्लू.) क्षमता में नौसेना के परिचालन को शुरू करेगी।

एम.एच.-60 आर.

- यह अमेरिकी नौसेना के एंटी-सबमरीन वारफेयर (ए.एस.डब्ल्यू.) की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- एम.एच.-60आर., जो वर्तमान में अमेरिका के साथ कार्यरत है, एक आधुनिक और सिद्ध बहु-मिशन मंच है जो एंटी-शिप, एंटी-पनडुब्बी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को ले जाने में और नौसेना के लिए आवश्यक आसमान में परिणाम केंद्रित आक्रामक और रक्षात्मक भूमिकाओं को निभाने में भी सक्षम है।

संबंधित जानकारी

- पिछले दो महीनों में, भारत ने एस.-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों और चार स्टील्थ युद्धपोतों के लिए रूस के साथ बहु अरब डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह सौदे, प्रतिबंध अधिनियम कानून (सी.ए.ए.टी.एस.ए.) के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने के अंतर्गत अमेरिका के धमकी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि से आते हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत- द हिंदू

26.11.2018

1. **संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत शहर 2025 पहल में भाग लेने हेतु नोएडा को चयनित किया है।**

- संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अपनी पहल का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में 25 मॉडल शहरों को बनाना है जो वर्ष 2025 तक सतत विकास लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से अनुपालन करेंगे।
- मुंबई और बैंगलोर की जगह राष्ट्रीय राजधानी के निकट गौतम बुद्ध नगर जिले के जुड़वां शहरों को "यूनिवर्सिटी सिटी" श्रेणी में चुना गया है, जो भारत के एकमात्र आमंत्रण के रूप में पहल हेतु संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विचाराधीन है।
- पूरे विश्व में लगभग 25 शहरों को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास लक्ष्य शहर पहल द्वारा पांच श्रेणियों के अंतर्गत चुना जाएगा।
- "यूनिवर्सिटी सिटी" श्रेणी में नोएडा-ग्रेटर नोएडा कैम्ब्रिज, पालो अल्टो और हेडेलबर्ग जैसे कुलीन यूनिवर्सिटी शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- चैट्ज ने दर्शाया है कि एस.डी.जी. शहरों की पहल से विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, भागीदारों और कॉर्पोरेट समर्थकों के माध्यम से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वैश्विक ज्ञान, संसाधन और क्षमता निर्माण का "अभूतपूर्व प्रवाह" होगा।

संबंधित जानकारी

सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

- सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति वर्ष 2012 में रियो डी जेननेरियों में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुई थी।
- एस.डी.जी., 17 "वैश्विक लक्ष्यों" का एक सेट है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न 169 क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- एस.डी.जी. ने मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी.) को प्रतिस्थापित किया है, जिसने गरीबी के रोष से निपटने के लिए वर्ष 2000 में वैश्विक प्रयास शुरू किए थे।
- इसका उद्देश्य सार्वभौमिक लक्ष्यों का एक सेट तैयार करना था जो हमारी दुनिया द्वारा सामना किए जा रहे तत्काल पर्यावरणीय, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों को पूरा करते थे।
- ये 17 लक्ष्य मिलेनियम विकास लक्ष्यों की सफलताओं के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, जब कि इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, सतत खपत, शांति और न्याय जैसे अन्य क्षेत्रों सहित अन्य प्राथमिकताएं भी शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: भारत के जीवों की प्रजातियों के दसवें हिस्से का निवास स्थान है।**

- भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के एक प्रकाशन के अनुसार, यह द्वीप समूह, देश के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.25% है और देश के जीवों की प्रजातियों के 10% से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है।
- अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 8249 वर्ग कि.मी. है, जिसमें 572 द्वीप, टापू और चट्टानी बहिर्वाह शामिल हैं।
- इस द्वीप की जनसंख्या में छह विशिष्ट आलोचनीय जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.)- ग्रेट अंडमानी, ओंज, जरावा, सेंटिनेलिस, निकोबारीस और शोम्पेन्स शामिल हैं।
- द्वीपों पर पाए जाने वाले समुद्री जीवों की दस प्रजातियों में डुगोंग/ समुद्री गाय और भारत-प्रशांत हंपबैक डॉल्फिन, दोनों को आई.यू.सी.एन. (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) की लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची में आलोचनीय श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- 46 स्थलीय स्तनधारी प्रजातियों में से तीन प्रजातियां- अंडमान श्रू (क्रोसीड्यूरा अंडमानीस), जेनकिन के श्रू (सी. जेनकिंसी) और निकोबार श्रू (सी. निकोबारिका) को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सिलिरैक्टिनियन प्रवाल (सख्त अथवा पथरीले प्रवाल) की प्रजातियां, द्वीप पारिस्थितिक तंत्र में

पाई जाती हैं, इन सभी को डब्ल्यू.पी.ए. की अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

3. **<u>संविधान दिवस को चिह्नित करने हेतु ब्रेल लिपि में संविधान</u>**

- 26 नवंबर को संविधान दिवस से पहले, पहली बार भारत का संविधान ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह सावी फाउंडेशन और स्वागत थोरत के साथ अंधे लोगो हेतु बौद्ध संघ द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त परियोजना है।
- इसकी सीमाओं के कारण ब्रेल लिपि में लिखे गए संविधान की एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या 150 से अधिक नहीं हो सकती है।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए ब्रेल लिपि में लिखा गया संविधान पांच भागों में उपलब्ध होगा।

संबंधित जानकारी

- स्वागत थोरात, वर्ष 2008 से भारत का पहला ब्रेल लिपि का अख़बार 'स्पर्षदन्यन' प्रकाशित कर रहे हैं।
- यह अंधे समुदाय के यू.पी.एस.सी. उम्मीदवारों और वकीलों के लिए सहायक होगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. **<u>ओपन ट्रांजिट डेटा पोर्टल</u>**

- दिल्ली सरकार ने एक समर्पित ओपन ट्रांजिट डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम- delhi.gov.in. है।
- यह 10 सेकंड के अंतराल पर क्लस्टर बसों के स्थानों की लोकेशन का पता लगाने में मदद करेगा।
- सिटी बसों के पारगमन डेटा को खोलने हेतु दिल्ली, देश का पहला शहर बन गया है।

संबंधित जानकारी

- यह पोर्टल, आई.आई.आई.टी.-दिल्ली द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था।
- यह सरकार को बस स्टॉपों पर रियल टाइम यात्री सूचना प्रणाली (पी.आई.एस.) अथवा डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने में सक्षम बनाएगा और ये टर्मिनल किसी भी बस स्टॉप पर अनुमानित आगमन समय (ई.टी.ए.) प्रदान करेंगे।
- भविष्य में यह पोर्टल में मेट्रो ट्रेनों और अंतिम मील कनेक्टिविटी वाहनों सहित मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट डेटा फीड को भी निगमित करेगा।

टॉपिक-जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस: महत्वूपर्ण पोर्टल

स्रोत-लाइव मिंट

5. **<u>'झिरी मेला' महोत्सव जम्मू जिले के झिरी गांव में आयोजित किया गया है।</u>**

- झिरी मेला, प्रत्येक वर्ष 'बाबा जित्तू' नामक शहीद किसान की याद में मनाया जाता है।
- बाबा जित्तू, एक किसान था, जिसने लगभग 500 वर्ष पहले मकान मालिक की दमनकारी मांगों के विरोध में अपने प्राण त्याग दिए थे।

संबंधित जानकारी

अन्य महोत्सव

जंगलमहल महोत्सव

- 'जंगलमहल' महोत्सव, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों के आसपास के जंगली क्षेत्रों में शुरू हुआ था।
- यह महोत्सव 'जंगल महल उद्योग' द्वारा प्रारंभ और आयोजित किया गया था, इस महोत्सव का उद्देश्य जंगल महल की संस्कृति और विरासत को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाना है।

बाली यात्रा महोत्सव

- ऐतिहासिक बाली यात्रा महोत्सव की शुरूआत कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उड़ीसा के कटक में हुई थी।
- यह महोत्सव कटक में महानदी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, यह महोत्सव उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब प्राचीन सधाबास (प्राचीन नाविक) व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार के लिए बाली के दूरस्थ क्षेत्रों में जाना शुरू किया था।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

6. **<u>आई.एम.डी. ने जल स्तर के बढ़ने का मूल्यांकन करने के लिए नई तकनीक विकसित की है।</u>**

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) ने बारिश के कारण नदियों और जलाशयों में जल स्तर के बढ़ने का मूल्यांकन करने हेतु एक नई तकनीक विकसित की है।
- इस तकनीकि को 'प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण' के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व-परिणाम परिदृश्य को दर्शाती है, जो बारिश के प्रभाव की गहन निगरानी करने और रियल-टाइम निर्णय लेने में राज्य सरकार की मदद कर सकती है।
- प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण और चेतावनी सेवाओं का उद्देश्य संकट काल (बाढ़) में भूमिका अदा करने वाले हितधारकों और नागरिकों के मध्य तालमेल को बेहतर बनाना है।
- यह एक प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए चार घटकों के मध्य कमियों को दूर करके मदद करेगा:
  (a) जोखिम ज्ञान,
  (b) निगरानी और चेतावनी सेवा
  (c) प्रचार और संचार
  (d) प्रतिक्रिया क्षमता

संबंधित जानकारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार की एक संस्था है।
- यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है।
- आई.एम.डी. का मुख्यालय दिल्ली में है।
- आई.एम.डी., विश्व मौसम संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भविष्यवाणी, नामकरण और चेतावनी वितरण के लिए जिम्मेदार संस्था है, जिसमें मलक्का जलडमरूमध्य, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अरब की खाड़ी शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –आपदा प्रबंधन

स्रोत- ए.आई.आर.

7. **<u>मानव माइक्रोबिओम</u>**

- पुणे ने माइक्रोबिओम अनुसंधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, यह अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जो आज भी भारत में अपनी प्रथम अवस्था में है।
- इस सम्मेलन में वे पूरे देश में मानव माइक्रोबिओम का अध्ययन और मानचित्रण करेंगे।

संबंधित जानकारी

- मानव शरीर में सूक्ष्मजीवों के विविध समुदाय होते हैं, जो मुख्य रूप से जीवाणु संबंधी होते हैं, जिन्हें "मानव माइक्रोबिओम" के रूप में जाना जाता है।
- ये सूक्षमजीव, सामुदायिक शारीरिक क्रिया विज्ञान के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह आवश्यक विटामिन, प्रतिरोधक तंत्र को बनाए रखने हेतु अन्य जटिल अपाच्य कार्बोहाइड्रेट और वसा के मेटाबॉलिज्म और रोगजनकों के विरूद्ध रोकथाम की प्रथम श्रेणी के रूप में कार्य करते हैं।
- मानव माइक्रोबिओम पर किए गए अनुसंधान ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है-

1. किस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न भागों में विशेष माइक्रोबियल समुदाय रहते हैं और माइक्रोबिओम की संरचना को आकार देने में किस प्रकार विभिन्न कारक योगदान देते हैं।
2. इसमें आनुवंशिकी, आहार संबंधी आदतों, आयु, भौगोलिक स्थान और जातीयता का अध्ययन भी शामिल है।

- इस परियोजना में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से विभिन्न जातीय समूहों के 20,000 भारतीयों के लार, मल और त्वचा का संग्रह शामिल किया जाएगा।
- भारत 4,500 से अधिक जातीय समूहों और दो वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉटों (हिमालयी सीमा और पश्चिमी घाट) की उपस्थिति के साथ व्यापक अनुसंधान प्रदान करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि
स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. **<u>गोट प्लेग के लिए एक स्मार्ट टीका</u>**

- यू.के. और भारत के शोधकर्ताओं के साथ तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की एक टीम ने संयुक्त रूप से एक 'स्मार्ट' टीका विकसित किया है जिसमें गोट प्लेग को जड़ से समाप्त करने की क्षमता है।
- एक स्मार्ट टीका विकसित करने हेतु नमूना प्रदान करने में ब्रिटिश वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है, जिसे **दिवा (डी.आई.वी.ए.) टीका** के नाम से भी जाना जाता है।
- यह पहले स्मार्ट पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनैंट्स (पी.पी.आर.) टीकों में से एक है जो टीकाकृत और संक्रमित जानवरों के मध्य अंतर करने में मदद करता है, जो परंपरागत जीवित अथवा मरे हुए विषाणु टीकों के साथ असंभव है।
- ये टीकें प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं जो प्राकृतिक संक्रमण से प्रेरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से भिन्न होती हैं।

संबंधित जानकारी

- गोट प्लेग अथवा पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनैंट्स (पी.पी.आर.), एक बेहद संक्रामक विषाणुजनक बीमारी है जो देश के कई हिस्सों में बकरियों और भेड़ों को कष्ट प्रदान करती हैं।
- इस बीमारी से छोटे रूमिनैंट बड़ी संख्या में तब तक मारे जाते हैं जब तक उनका टीकाकरण नहीं हो जाता है।
- भारत के अतिरिक्त गोट प्लेग कई अफ्रीकी देशों, पश्चिमी एशिया, चीन और मंगोलिया में प्रचलित है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकी
स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

9. **<u>इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019</u>**

- यह एक वैश्विक प्रतिभा मूल्यांकन कंपनी, व्हीबॉक्स और एक प्रमुख एच.आर. तकनीकि कंपनी, पीपल स्ट्रांग और भारतीय औद्योगिक संघ की संयुक्त पहल है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.), अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) और भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) जैसे प्रतिष्ठित भागीदारों द्वारा समर्थन प्राप्त है।
- आंध्र प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक रोजगार क्षमता के साथ राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, पसंदीदा नियुक्त गंतव्यों में से एक है और पुरुष एवं महिला कर्मचारियों द्वारा काम के लिए सबसे पसंदीदा राज्यों में से एक है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर -3- आर्थिक विकास
स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

27.11.2018

1. **<u>ई-पशुहाट पोर्टल किसानों और प्रजनकों को रोग मुक्त रोगाणुओं में व्यापार करने हेतु जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।</u>**

संबंधित जानकारी
ई-पशुहाट पोर्टल

- कृषि मंत्रालय ने नवंबर, 2016 में डेयरी किसानों के लिए ई-पशुहाट पोर्टल लॉन्च किया है।
- यह पोर्टल किसानों, प्रजनकों और अन्य संस्थाओं को रोगमुक्त रोगाणुओं अर्थात जीवित जानवरों, जमे हुए वीर्य और भ्रूण का व्यापार करने हेतु जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- हाल ही में, एक मोबाइल एप्लिकेशन ई-पशुहाट (जी.पी.एम.एस. ट्रांसपोर्टल) भी बनाया गया है और इसे उमंग (नए आयु वर्ग शासन हेतु एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन) के साथ एकीकृत किया गया है।
- वर्तमान में वे अपने स्थान के 100 कि.मी. के दायरे के अंतर्गत रोग मुक्त जर्मप्लाज्म सेवाओं की उपलब्धता को जान सकते हैं।

संबंधित जानकारी
नए आयु वर्ग शासन हेतु एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (यू.एम.ए.एन.जी.)

- उमंग, सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक

केंद्रित सेवाओं तक पैन इंडिया ई-गॉव सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां नागरिक कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं।
- उमंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) की एक डिजिटल भारत पहल है।

डेयरी किसानों के उत्थान के लिए अन्य योजनाएं

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर.जी.एम.)
- यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना है जो स्वदेशी नस्लों के विकास, परिरक्षण और संरक्षण में मदद करती है।

पशुसंजीवनी
- योजना के पशु संजीवनी घटक के अंतर्गत, यू.आई.डी. (अद्वितीय पहचान डिवाइस) का उपयोग कर दुग्ध जानवरों की पहचान की जा रही है।

डेयरी प्रसंस्करण एवं ढांचा विकास निधि (डी.आई.डी.एफ.)
- इसका लक्ष्य 50,000 गांवों में 95 लाख दूध उत्पादकों को लाभान्वित करना है और कई कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है।
- डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत, दूध उत्पादन से मार्केटिंग तक विभिन्न गतिविधियों में स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण योजना

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया स्वास्थ्य सूचना मंच "आई.एच.आई.पी." लॉन्च किया है।</u>**

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने सात राज्यों में समेकित स्वास्थ्य सूचना मंच (आई.एच.आई.पी.) के सम्पूर्ण बीमारी निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) की शुरूआत की है।
- यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस प्रकार की पहली पहल है।
- आई.एच.आई.पी. नवीनतम तकनीकों और डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का उपयोग करता है।
- यह पहल, नीति निर्धारक बीमारी फैलने का पता लगाने, अस्वस्थता और मृत्यु दर को कम करने और आबादी पर बीमारी का बोझ हल्का करने के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली के लिए वास्तविक आंकड़े प्रदान करेगी।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>यूनेस्को ने कुश्ती के लिए उत्तर और दक्षिण कोरिया द्वारा लगायी गयी संयुक्त बोली को स्वीकार कर लिया है।</u>**

- यूनेस्को ने कोरियाई कुश्ती को विश्व के सर्वश्रेष्ठ निधि सांस्कृतिक अभ्यासों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु संयुक्त बाली को स्वीकार कर लिया है।
- दोनों कोरियाईओं ने अपनी कुश्ती के सांस्कृतिक रूप को संयुक्त राष्ट्र संस्था की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में मान्यता प्राप्त कराने हेतु मूल रूप से पृथक आवेदन दायर किए हैं।

संबंधित जानकारी

सीर्यूम
- सीर्यूम अथवा कोरियाई कुश्ती, एक लोक कुश्ती कला है और चौथी शताब्दी से कोरिया का राष्ट्रीय खेल है।
- आधुनिक समाज में, प्रत्येक प्रतियोगी एक बेल्ट (सतबा) पहनता है जो कमर और जांघ के चारों ओर पहनी जाती है।
- यह खेल कुछ हद तक जापानी सूमो से समानता रखता है।
- दक्षिण कोरिया में, पहलवान नंगे बदन रहते हैं और केवल कसे जांघिए पहनते हैं, जब कि उत्तर कोरिया में वे स्लीवलेस जैकेट पहनते हैं।
- दक्षिणी मैच, रेत पर आयोजित होते हैं जब कि उत्तरी मैच, एक गोल गद्दे पर आयोजित किए जाते हैं।
- यहां पर वर्ष 2003 से जेजू द्वीप के दक्षिण में केवल एक अंतर-कोरियाई कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

4. **पैसा पोर्टल**

- पी.ए.आई.एस.ए. (पैसा) (सस्ते ऋण एवं ब्याज आर्थिक सहायता पहुॅच हेतु पोर्टल"), राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन- दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता प्रसंस्करण हेतु एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच है।
- यह वेब मंच, इलाहाबाद बैंक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है जो कि एक प्रधान बैंक है।
- यह लाभार्थियों से सीधे जुड़ने में सरकार की मदद करती है और सेवाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता और क्षमता को सुनिश्चित करती है।
- सभी 35 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आर.आर.बी. और सहकारी बैंको द्वारा इस वर्ष के अंत तक पैसा पोर्टल को अपनाने की उम्मीद है।
- डे-एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत मासिक आधार पर आर्थिक सहायता का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने से समय-समय पर छोटे उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

संबंधित जानकारी

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है।
- इस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है।
- यह मिशन, शहरी सड़क विक्रताओं को उभरते हुए बाजार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त रिक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका चिंताओं को भी संबोधित करेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत-पी.आई.बी.

5. **आर.आई.एम.ई.एस. ने तितली चक्रवात को 'दुर्लभ से दुर्लभ' के रूप में श्रेणीबद्ध किया है।**

- अफ्रीका और एशिया के लिए क्षेत्रीय समाकलित बहु-संकट प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (आर.आई.एम.ई.एस.) ने 'तितली' को 'दुर्लभ से दुर्लभ' के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान है जिसने अक्टूबर में ओडिशा को बर्बाद कर दिया था।
- ओडिशा तट पर 200 से अधिक वर्षों के चक्रवात ट्रैक इतिहास से पता चलता है कि तितली तूफान अपनी विशेषताओं के आधार पर 'दुर्लभ से दुर्लभ' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है-
- भूमिगत होने के बाद पुनरावृत्ति
- भूमिगत होने के बाद अपनी विनाशकारी क्षमता को बनाए रखना
- दो दिनों से अधिक समय के लिए तटीय क्षेत्रों से दूर पुनरावृत्ति करना

संबंधित जानकारी

क्षेत्रीय समाकलित बहु-संकट प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (आर.आई.एम.ई.एस.)

- आर.आई.एम.ई.एस., एक अंतरराष्ट्रीय और अंतर सरकारी संस्थान है, जो प्रारंभिक चेतावनी सूचना के उत्पादन और आवेदन हेतु अपने सदस्य राज्यों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित है।
- यह 30 अप्रैल, 2009 को वर्ष 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद स्थापित किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ पंजीकृत किया गया था।
- आर.आई.एम.ई.एस. थाईलैंड के पाथुमथानी में स्थित एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में स्थित अपने क्षेत्रीय प्रारंभिक चेतावनी केंद्र से संचालित होता है।
- वर्तमान में भारत सरकार आर.आई.एम.ई.एस. परिषद अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –आपदा प्रबंधन

स्रोत- द हिंदू

6. **'हौसला- 2018'**

- बाल देखभाल संस्थानों (सी.सी.आई.) के बच्चों के लिए राष्ट्रीय उत्सव- "हौसला 2018" का नई

दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उद्घाटन किया गया है।

- यह पूरे भारत में सी.सी.आई. के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है जिससे कि वे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें और वे अपने अंदर छिपी प्रतिभा का एहसास कर सकें और जीवन में उनकी प्रतिभा को विकसित करने में उनकी मदद कर सके।
- इस कार्यक्रम की थीम "बाल सुरक्षा" है।
- सी.आई.एफ. (चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन) और एन.आई.पी.सी.सी.डी. कार्यक्रम के आयोजन में मंत्रालय की सहायता करेंगे।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान

- राष्ट्रीय सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में एक भारतीय सरकारी संस्था है।
- भारत में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्रवाई अनुसंधान, प्रशिक्षण और दस्तावेज़ीकरण के संवर्धन हेतु एन.आई.पी.सी.सी.डी. कार्यरत है।
- इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, इस संस्थान के चार क्षेत्रीय केंद्र- गुवाहाटी, बैंगलोर, लखनऊ और इंदौर में स्थित हैं।
- अप्रैल, 1985 में संस्थान को बच्चों, प्रशिक्षण, अनुसंधान और वकालत के लिए विकासशील सेवाओं में अपने काम के सम्मान में यूनिसेफ द्वारा मॉरीस पेट मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सी.आई.एफ.)

- यह पूरे देश में चाइल्डलाइन 1098 सेवा की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी हेतु मूल संगठन के रूप में कार्यरत है और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रधान संस्था है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महिला सशक्तीकरण

स्रोत-पी.आई.बी.

7. **<u>भारत और चीन ने डी.टी.ए.ए. में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।</u>**

- भारत और चीन की सरकारों ने दोहरे कराधान से बचने के लिए और आय पर कर के सापेक्ष वित्तीय परिहार की रोकथाम हेतु दोहरे कराधान परिहार समझौते (डी.टी.ए.ए.) में संशोधन किया है।
- यह प्रोटोकॉल नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को जानकारी के विनिमय हेतु मौजूदा प्रावधानों को भी अपडेट करता है।
- इसके अतिरिक्त यह प्रोटोकॉल, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बी.ई.पी.एस.) परियोजना की कार्य रिपोर्ट के अंतर्गत संधि से संबंधित न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों शामिल करता हैं, बी.ई.पी.एस. में भारत ने समान आधार पर भाग लिया था।

संबंधित जानकारी

दोहरा कराधान परिहार समझौता

- डी.टी.ए.ए., एक कर संधि होती है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित की जाती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन देशों में करदाता एक ही आय पर दो बार कर देने से बच सकते हैं।
- डी.टी.ए.ए. उन मामलों में लागू होता है जहां एक करदाता एक देश में रहता है और दूसरे में कमाता है।
- डी.टी.ए.ए. या तो आय के सभी स्रोतों को कवर करने के लिए व्यापक हो सकते हैं या शिपिंग, हवाई परिवहन, विरासत इत्यादि से प्राप्त आय पर कर जैसे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो सकते हैं।
- वर्तमान में, भारत ने विश्व के 80 से अधिक देशों के साथ दोहरा कराधान परिहार संधि की हुई है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- डी.टी.ए.ए. का उद्देश्य दोहरे कराधान पर राहत प्रदान करके देश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना है।
- विदेश में कमायी गई आय पर निवास करने वाले देश में कोई कर नहीं लिया जाएगा अथवा विदेश में पूर्व भुगतान किए जा चुके विस्तार करों का ऋण प्रदान करने जैसी सहायताएं प्रदान की जाएंगी।

- कुछ मामलों में डी.टी.ए.ए. कर की रियायती दरें भी प्रदान करता हैं।

डी.टी.ए.ए. से संबंधित समस्याएं

- डी.टी.ए.ए., कराधान से बचने के लिए निम्न कर शासनों के माध्यम से निवेश को बदलने हेतु वैध निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है।
- इससे देश के राजस्व कर में कमी आती है।

जनरल एंटी अवॉइडेंस नियम (जी.ए.ए.आर.)

- जनरल एंटी अवॉइडेंस नियम (जी.ए.ए.आर.), भारत का एक कर-विरोधी बचाव नियम है।
- यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- यह कर कानूनों में हेरफेर करके जानबूझ कर, टैक्स से बचने के लिए किए जाने वाले कार्यों की रोकथाम के लिए बनाया गया है।
- यह किसी भी बड़ी पूंजी वाले सौदे अथवा संयुक्त उद्यम की जांच करने में आयकर विभाग को सशक्त करता है।
- यह मॉरीशस, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स आश्रयों के माध्यम से निवेश को रूट करने के माध्यम से चोरी करने वाले कर चोरों को रोकता है।

कर आश्रय देशों

- कर आश्रय देश वे देश अथवा क्षेत्र होते हैं जहां पर शून्य अथवा बहुत कम कराधान दर होती है जो कर परिहार अथवा कर चोरी के व्यक्तिगत और व्यापारिक अवसर प्रदान करता है।

कर चोरी

- यह आय, व्यय आदि की सूचना न प्रदान करने के द्वारा कर का भुगतान न करने की गैरकानूनी कार्य है।

कर परिहार

- टैक्स कोड में शामिल विधियों का उपयोग करके करों का वैध न्यूनीकरण है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>ओडिशा ने सार्वजनिक साइकिल साझाकरण प्रणाली की शुरूआत की है।</u>**

- ओडिशा सरकार ने यातायात भीड़ को कम करने, स्थान दक्षता में वृद्धि करने और भुवनेश्वर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु एक सार्वजनिक साइकिल साझाकरण प्रणाली की शुरूआत की है।
- राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन और भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पी.बी.एस. के लिए एक साथ मिलकर काम किया है, जिसे 'एम.ओ. साइकिल' प्रणाली के रूप में नामित किया गया है।
- सवार, निकटतम एम.ओ. साइकिल स्टेशन का पता लगा सकता है और क्विक रिसपांस कोड स्कैन के माध्यम से साइकिल को अनलॉक कर सकता है।
- जी.पी.एस. और स्मार्ट लॉक जैसी प्रौद्योगिकी विशेषताएं इस प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-पी.आई.बी.

9. **<u>बिहार सरकार ने राजगिर में भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया है।</u>**

- बिहार के मुख्यमंत्री ने नालंदा जिले के राजगिर में भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया है।
- यह देश में बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है।
- यह प्रतिमा घोराकटोरा झील के मध्य में 16 मीटर त्रिज्या के मूर्तितल के ऊपर बनाई गयी है और यह प्रतिमा 4500 घन फुट गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाई गयी है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर -1 भारतीय भूगोल

स्रोत- ए.आई.आर.

28.11.2018

1. **<u>'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति'</u>**

- रक्षा उत्पादन विभाग ने 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' नामक एक नया ढांचा स्थापित किया है जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में आई.पी.आर. संस्कृति को बढ़ावा प्रदान करना है।

- यह बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) आवेदनों को सफलतापूर्वक भरने में मदद करेगा।

संबंधित जानकारी

बौद्धिक संपदा अधिकार

- बौद्धिक संपदा अधिकार, वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं पर प्रदान किए जाते हैं।
- ये सामान्यत: निर्माता को एक निश्चित समयावधि के लिए अपनी रचना के प्रयोग का विशेष अधिकार प्रदान करता है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों को साधारणतया दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

1. कॉपीराइट और कॉपीराइट से संबंधित अधिकार

- साहित्यिक लेखकों और कलात्मक कार्यों (पुस्तक और अन्य लेखों, संगीत रचनाओं, चित्रों, मूर्तिकला, कंप्यूटर प्रोग्रामों और फिल्मों) के कलाकारों के अधिकार उनकी मृत्यु के बाद न्यूनतम 50 वर्ष की समयावधि के लिए कॉपीराइट द्वारा संरक्षित होते हैं।
- कॉपीराइट के माध्यम से, संबंधित (कभी-कभी इन्हें "पड़ोसी" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है) अधिकारों को भी संरक्षित किया जाता है, संबंधित अधिकार, कलाकरों के अधिकार (जैसे अभिनेता, गायक और संगीतकार), फोनोग्राम के अविष्कारक (ध्वनि रिकॉर्डिंग) और प्रसारण संगठन के निर्माता के अधिकार हैं।
- कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों की सुरक्षा का मुख्य सामाजिक उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करना है।

2. औद्योगिक संपत्ति

- इसे विशिष्ट संकेतों, विशेष रूप से ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- इस प्रकार के विशिष्ट संकेतों की सुरक्षा का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बारे में विकल्पों की जानकारी प्रदान करके उन्हें सक्षम बनाकर उचित प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना है।
- अनंतकाल तक संरक्षण के बने रहने से यह विशिष्टता की निरंतरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
- नवाचार, डिजाइन और प्रौद्योगिकी के निर्माणों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रकार की औद्योगिक संपत्तियों का प्राथमिक रूप से संरक्षण करना चाहिए।
- इस श्रेणी में आविष्कार (पेटेंट द्वारा संरक्षित), औद्योगिक डिजाइन और व्यापारिक रहस्य शामिल हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –आर्थिक आई.पी.आर.

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **13वां जी-20 शिखर सम्मेलन**

- 13वें जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2018 तक अर्जेंटीना के ब्यूनॉस एयर्स शहर मे किया जाएगा।
- शिखर सम्मेलन की थीम "निष्पक्ष और सतत विकास हेतु आम राय बनाना" है।
- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक विशेष महत्व प्रदान करना है, जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है।

संबंधित जानकारी

जी20

- ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी 20), वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु केंद्रीय मंच है।
- जी 20 देशों से सकल विश्व उत्पाद के 4/5 और वैश्विक व्यापार का तीन-चौथाई से अधिक भाग प्राप्त होता है और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी इन देशों में निवास करती है।
- इसके निर्णय प्रभावशाली होते हैं और राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय स्तरों पर सुधार लाने में मदद करते हैं।
- जी20, 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना हैं।
- ये देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण समिति

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **लॉजिक्स इंडिया- 2019**

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ने नई दिल्ली में लॉजिक्स इंडिया 2019 का प्रतीक चिन्ह और विवरणिका लॉन्च की है।
- लॉजिक्स इंडिया 2019 नई दिल्ली में आयोजित होना निर्धारित हुआ है।
- रसद लागत प्रभावशीलता और भारत के वैश्विक व्यापार हेतु परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ.आई.ई.ओ.) द्वारा एक प्रमुख पहल के रूप में वृहद रसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
- लॉजिक्स इंडिया, प्रभावी अंतरराष्ट्रीय व्यापार रसद को सक्षम करेगा और कुशल एवं उत्पादों का लागत-प्रभावी प्रवाह प्रदान करके अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों की मदद करेगा।
- एफ.आई.ई.ओ., बुनियादी ढांचे के विकास, गोदाम समेकन, प्रौद्योगिकी एकीकरण और आई.टी. सक्षमता और श्रमशक्ति को कुशल बनाने के क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

संबंधित जानकारी

- विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के रसद उद्योग के अगले दो वर्षों में बढ़कर 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की संभावना है।
- यह क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के 10.5 प्रतिशत की दर से प्रगति करने की उम्मीद है।

भारत में एकीकृत रसद क्षेत्र विकास की आवश्यकता-

- भारत को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और आसियान के देशों के साथ अधिक मजबूत व्यापार संबंधों की आवश्यकता है।
- उच्च रसद लागत, घरेलू और निर्यात बाजार दोनों क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को कम कर देती है।
- रसद, एक्जिम व्यापार की रीढ़ की हड्डी है और व्यापार के अवसर और रोजगारों का निर्माण करती है। वर्तमान में 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रसद क्षेत्र के वर्ष 2032 तक 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

भारतीय निर्यात संगठन संघ

- भारतीय निर्यात संगठन संघ, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और निजी व्यापार एवं उद्योग के अंतर्गत भारत में एक व्यापार संवर्धन संगठन है।
- यह संगठन विदेशी बाजारों में भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों के प्रतिनिधित्व और सहायता हेतु जिम्मेदार है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत-पी.आई.बी.

4. **सी.एस.आई.आर., चंडीगढ़ में एक हाइ इंड कौशल विकास केंद्र स्थापित कर रहा है।**

- भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला सी.एस.आई.आर.-माइक्रोबियल तकनीकि संस्थान ने सी.एस.आई.आर.-आई.एम.टी.ई.सी.एच., चंडीगढ़ में 'हाई-इंड कौशल विकास केंद्र' स्थापित करने हेतु एक अग्रणी जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनी, मर्क के साथ नई साझेदारी की घोषणा की है।
- यह चंडीगढ़ में इस प्रकार की पहली, अकादमी-उद्योग नेतृत्व वाली 'हाई इंड कौशल विकास केंद्र' प्रयोगशाला है, जिसे जीवन विज्ञान के क्षेत्र में भारत को कुशल बनाने हेतु भारत सरकार की पहल को बढ़ाने हेतु स्थापित किया गया है।
- यह जीन एडिटिंग और एकल अणु बायोमार्कर निर्धारण जैसी अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित होगी।
- यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में तेजी लाने और भारतीय छात्रों एवं शोधकर्ताओं को नवीनतम जीवन विज्ञान प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने और उन्हें उद्योग हेतु तैयार करने में मदद करेगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि
स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. **<u>वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2018</u>**

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) द्वारा वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2018 प्रकाशित की गई है।
- वर्ष 2017 में दक्षिण एशिया में भारत में सबसे तेज़ मजदूरी वृद्धि हुई थी।
- वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2017 में मजदूरी में वृद्धि की दर वर्ष 2008 से लेकर तब तक के निम्नतम स्तर पर जा चुकी थी, लेकिन वर्ष 2008-17 की अवधि के दौरान दक्षिण एशिया में भारत में 5.5% की उच्चतम औसत वास्तविक मजदूरी वृद्धि दर थी।

रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष-

- प्रति घंटे की मजदूरी के आधार पर भारत के लिए औसत लिंग वेतन अंतर 34.50 प्रतिशत और पाकिस्तान के लिए 34 प्रतिशत रहा है जो कि 73 देशों के लिए उपलब्ध डाटा में सबसे खराब था।
- वैश्विक स्तर पर महिलाएं को पुरुषों की तुलना में लगभग 20% कम भुगतान किया जा रहा है।
- उच्च आय वाले देशों में मजदूरी में लिंग अंतर सबसे कम और निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में मजदूरी में लिंग अंतर सबसे अधिक है।
- सभी क्षेत्रों में से एशिया और प्रशांत क्षेत्र के श्रमिकों ने 2006-17 की अवधि के दौरान चीन, भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों के साथ उच्चतम वास्तविक मजदूरी वृद्धि का आनंद लिया है।
- वर्ष 1999 से 2017 तक की लंबी अवधि के दौरान जी 20 के उभरते हुए और विकासशील देशों में वास्तविक मजदूरी लगभग तीन गुना हो गई है, जब कि समान अवधि के दौरान उन्नत जी20 देशों में वास्तविक मजदूरी में केवल 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वैश्विक स्तर पर, वैश्विक वित्तीय संकट से पहले 3.4% के स्तर से काफी नीचे वर्ष 2016 में मजूदरी में वास्तविक वृद्धि (अर्थात मूल्य मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) 2.4% से घटकर पिछले वर्ष 1.8% हो गई थी।

संबंधित जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करती है और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और कार्य के अवसरों को बढ़ावा देती है।
- आई.एल.ओ. में 187 सदस्य राज्य हैं: 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों में से 186 सदस्य हैं और कुक द्वीप समूह आई.एल.ओ. का सदस्य हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है।
- वर्ष 1969 में, संगठनों को राष्ट्रों के मध्य भाईचारे और शांति स्थापित करने, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य और न्याय करने और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –महत्वूपर्ण रिपोर्ट
स्रोत- टी.ओ.आई.

6. **<u>अब, ओडिशा में दुर्लभ जनजातीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोष उपलब्ध है।</u>**

- ओडिशा सरकार ने दुर्लभ जनजातीय भाषाओं के लिए 21 आदिवासी शब्दकोश और दक्षता मॉड्यूल का अनावरण किया है।
- राज्य सरकार ने अपनी जनजातीय भाषा एवं संस्कृति अकादमी (ए.टी.एल.सी.) के माध्यम से जनजातीय भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने हेतु बहुभाषी शिक्षा के लिए जनजातीय द्विभाषीय शब्दकोष और जनजातीय त्रिभाषीय दक्षता मॉड्यूल स्थापित किए हैं।
- ओडिशा, देश का एकमात्र राज्य हैं जिसने सभी जनजातीय द्विभाषीय शब्दकोशों और त्रिभाषीय जनजातीय भाषा दक्षता मॉड्यूल तैयार किए हैं।

संबंधित जानकारी

अद्वितीय जनजातीय प्रोफ़ाइल

- ओडिशा, भारत के जनजातीय मानचित्र पर एक अद्वितीय स्थान है जहां पर अधिकतम संख्या में अनुसूचित जनजाति समुदाय निवास करते हैं।
- इस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों सहित 62 विभिन्न जनजातीय समुदाय निवास करते हैं।
- ये जनजातियां 21 भाषाएं और 74 बोलियां बोलती हैं।
- 21 जनजातीय भाषाओं में से सात की अपनी लिपि है।
- शब्दकोष में संचार के माध्यम के रूप में उडिया का प्रयोग किया गया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – समाज के कमजोर वर्ग हेतु कल्याण योजनाएं

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>दुधवा बाघ रिजर्व का गश्त करने हेतु एस.एस.बी.</u>**

- दुधवा बाघ रिजर्व और सशस्त्र सीमा बल ने दुधवा वनों और इसके समृद्ध वन्यजीवन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु साझा समझौता किया है।
- यह सहमति हुई कि एस.एस.बी., केंद्रीय और स्थानीय खुफिया अधिकारियों, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों, विशेष बाघ संरक्षण बल और रिजर्व का फील्ड स्टाफ नियमित अंतराल पर संयुक्त लंबा मार्ग गश्ती में शामिल होगा।

संबंधित जानकारी

दुधवा टाइगर रिजर्व

- दुधवा बाघ रिजर्व, उत्तर प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है जो मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है।
- इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- यह नेपाल के साथ उत्तर-पूर्वी सीमा साझा करता है, जो काफी हद तक मोहाना नदी द्वारा परिभाषित है।

नोट: दुधवा बांध, भारत के छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। यह बांध, दुधवा गांव में महानदी नदी पर बनाया गया है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

8. **<u>यूक्रेन ने मार्शल लॉ (फौजी कानून) की घोषणा की है।</u>**

- यूक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्को ने रूस के साथ तनाव के कारण अपने देश के कुछ हिस्सों में मार्शल लॉ घोषित किया है।
- 25 नवंबर को क्राइमीनन प्रायद्वीप से दूर नौसेना के संघर्ष के बाद यह निर्णय लिया गया है, इस संघर्ष में आजोव सागर पर रूसी तटरक्षक ने तीन यूक्रेनी जहाजों और उनके 23 चालक दल के सदस्यों को बंदी बना लिया था।
- रूस ने दो यूक्रेनी तोपखाना नौकाओं पर बिना किसी अनुमति के कर्च जलसंधि के किनारे अपने जलनिकाय को पार करने का आरोप लगाया है, इसके बावजूद दोनो देशों ने काला सागर को साझा सीमा के रूप में पारित होने पर सहमति जताते हुए 2003 समुद्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

संबंधित जानकारी

- यूक्रेन में वर्ष 1945 से लेकर अब तक पहली बार 10 रणनीतिक सीमा क्षेत्रों में मार्शल लॉ राज्य घोषित किया गया है।
- यूक्रेन, पूर्वी यूरोप का एक बड़ा देश है जो इसके परंपरागत चर्चों, काला सागर तटरेखा और जंगली पहाड़ों के लिए जाना जाता है।
- इसकी राजधानी कीव है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संकट

स्रोत- द हिंदू

29.11.2018

1. **<u>हिमाचल प्रदेश के लिए आपातकाल प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ई.आर.एस.एस.) शुरू की है।</u>**

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए आपातकाल प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ई.आर.एस.एस.) शुरू की है।

- हिमाचल प्रदेश, ई.आर.एस.एस. के अतंर्गत पैन इंडिया एकल आपातकाल नंबर '112' लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र से तत्काल सहायता के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र में पंजीकृत स्वयंसेवकों से तत्काल सहायता प्राप्त करने हेतु '112 इंडिया' मोबाइल ऐप में एक शाउट फीचर पेश किया गया है।
- शाउट, फीचर महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है।

संबंधित जानकारी

आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ई.आर.एस.एस.)

- ई.आर.एस.एस., गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के अंतर्गत एक राष्ट्रीय परियोजना है। जिसे दिसंबर, 2012 में निर्भया बलात्कार जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया है।
- पुलिस, अग्नि और एम्बुलेंस इत्यादि जैसी सभी प्रकार की आकस्मिक कॉलें करने के लिए यह एक पैन इंडिया आपातकाल प्रतिक्रिया नंबर '112' है।

उद्देश्य

- पूरे देश में एक आपातकाल प्रतिक्रिया नंबर प्रदान करना।
- 24x7 कुशल और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान करना जो संकट में नागरिकों की मदद करने हेतु वॉयस कॉल, एस.एम.एस., ईमेल, थिंग्स ऑफ इंटरनेट, सार्वजनिक परिवहन में पैनिक बटन आदि जैसी विभिन्न बॉयस और डेटा सेवाओं से इनपुट प्राप्त कर सकता है।
- प्रणाली का प्रयोग करते हुए घटना के स्थान के लिए क्षेत्र संसाधनों (पुलिस) को समय पर प्रेषित करने हेतु स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली है।
- मौजूदा डायल 100, डायल 108 और अन्य आपातकाल प्रतिक्रिया प्रणालियों के साथ एकीकृत करना और सी.सी.टी.एन.एस. आदि जैसे अन्य प्रासंगिक प्रणालियों के साथ एकीकृत करना।
- इस परियोजना के अंतर्गत एम.एच.ए. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
- यह सहायता कंप्यूटर हार्डवेयर, सी-डैक संपर्क केंद्र समाधान स्टैक के रूप में प्रदान की जा रही है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महिला सुरक्षा/ सशक्तिकरण
स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>सतत ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन 2018</u>**

- अफ्रीका, केन्या की राजधानी नैरोबी में पहले सतत ब्लू सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
- इसकी थीम: 'ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा' है।
- यह मुख्य रूप से केन्या सरकार द्वारा सह-मेजबान कनाडा और जापान के साथ आयोजित किया गया था और बहु-दाता बॉस्केट निधि के माध्यम से यू.एन.डी.पी. द्वारा समर्थित था।
- सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र का 2030 एजेंडा, पेरिस में 2015 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 'कॉल टू एक्शन' के संवेग के आधार पर सतत ब्लू इकोनोमी सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

संबंधित जानकारी

ब्लू इकोनॉमी और इसका महत्व

- सतत ब्लू इकोनॉमी, एक समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती है।
- यह समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, उत्पादकता और लचीलेपन को पुनर्स्थापित, संरक्षित और बनाए रखने में मदद करता है और यह स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, अक्षय ऊर्जा और परिपत्र सामग्री प्रवाह पर आधारित है।

नोट:

एस.डी.जी. लक्ष्य 14: जल के नीचे जीवन, "सतत विकास हेतु समुद्रों, महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रयोग" से संबंधित है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

3. **<u>समावेशी संपत्ति रिपोर्ट 2018</u>**

- समावेशी संपत्ति रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के नेतृत्व में किया जाने वाला एक द्विवार्षिक प्रयास है।
- यह अर्थव्यवस्था की स्थिरता और वहां के लोगों की अच्छाई को मापने के लिए पूरे विश्व के देशों की क्षमताओं और प्रदर्शनों का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
- देशों में वर्तमान सांख्यिकीय प्रणाली, उन्हीं पर्यावरण एवं आर्थिक खातों की प्रणाली का उपयोग कर रही हैं जो प्रवाह आय को मापने के लिए तैयार हैं।
- प्रवाह गंभीर रूप से निर्मित पूंजी, मानव पूंजी और प्राकृतिक पूंजी जैसी पूंजीगत संपत्तियों के स्वास्थ्य और लचीलेपन पर निर्भर करेगा।
- किसी देश की समावेशी संपत्ति, उसकी सभी पूंजी संपत्तियों का सामाजिक मूल्य (डॉलर मूल्य नहीं) होता है जिसमें प्राकृतिक पूंजी, मानव पूंजी और उत्पादित पूंजी शामिल होती है।
- आई.डब्ल्यू.आर. 2018, रिपोर्ट के पिछले संस्करणों (आई.डब्ल्यू.आर. 2012 और आई.डब्ल्यू.आर. 2014) के आधार पर बनाए गए हैं और यह अर्थव्यवस्था के आधार (सभी प्रकार की पूंजी) को मापने के तरीकों को उन्नत करता है।
- यह वर्ष 1990 से 2014 तक की 25 वर्ष की अवधि को कवर करता है, जो कि 25 लगभग एक पीढ़ी में पूंजीगत संपत्तियों में बदलाव की तस्वीर प्रदान करता है।

गणना की पद्धति

- यह मानव पूंजी (शिक्षा और स्वास्थ्य) के प्रतिछाया वैकल्पिक मूल्य के साथ आता है, जो गैर-पैरामेट्रिक पद्धति पर आधारित होता है जिसे फ्रंटियर विश्लेषण कहते हैं।

रिपोर्ट के परिणाम-

140 देशों को कवर करने वाली आई.डब्ल्यू.आर. 2018 रिपोर्ट के परिणाम बताते हैं कि:

- वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2014 में 135 देशों में समावेशी संपत्ति (आई.डब्ल्यू.) बढ़ गई थी और सांकेतिक अवधि के दौरान आई.डब्ल्यू. की वैश्विक प्रगति दर 44 प्रतिशत थी, जो 1.8% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर को दर्शाती है।
- इसी अवधि के दौरान प्रति वर्ष वैश्विक जी.डी.पी. वृद्धि दर 3.4% थी, जो आई.डब्ल्यू. में वृद्धि की वार्षिक वृद्धि दर के दो गुने के लगभग है।
- प्रति व्यक्ति समावेशी संपत्ति और प्रति समायोजित व्यक्ति समावेशी संपत्ति के पदों में अध्ययन अवधि के दौरान 140 देशों में से 89 देशों और 96 देशों ने वर्ष 1990 में अपने स्तर की तुलना में वृद्धि देखी है।

नोट:

समावेशी संपत्ति रिपोर्ट 2018 दर्शाती है कि प्राकृतिक पूंजी का आकलन और मूल्यांकन और दिए गए समय के दौरान प्रति व्यक्ति समावेशी/ व्यापक संपत्ति में होने वाले परिवर्तनों में अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) पर प्रगति को बनाए रखने की क्षमता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण रिपोर्टें

स्रोत- टी.ओ.आई.

4. **<u>नेपाल ने औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है।</u>**

- नेपाल सरकार ने काठमांडू में औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है।
- इस योजना को राज्य के जनता के प्रति उत्तरदायित्व के मुद्दे को संबोधित करने के लिए पेश की गई है।
- यह योजना औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगी और फिर आगे चलकर इसे अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी लागू किया जाएगा।
- यह योजना 22 मई, 2019 से लागू की जाएगी और एक योगदान आधारित योजना होगी जहां निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा निधि (एस.एस.एफ.) में अनिवार्य रूप से अपने

मूल वेतन का 11 प्रतिशत देना होगा जब कि नियोक्ता को कर्मचारी के मूल वेतन का अन्य 20 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देना होगा।

- इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षित मातृत्व, दुर्घटना और शारीरिक अक्षमता सुरक्षा, परिवार के निर्भर सदस्यों की सुरक्षा और बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने की सुविधा शामिल है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. **अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग**

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) की एक टीम उत्तरी सेंटिनल द्वीप में एक संरक्षित और समावेशी जनजाति द्वारा अमेरिकी नागरिक की हत्या के मुद्दे की जांच करने हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाएगी।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- यह एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान (89 वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है।
- इस संशोधन के साथ पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को दो विभिन्न आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया- जिनके नाम (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.), (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) हैं।

रचना

- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) शामिल होते हैं।
- आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने से तीन वर्ष की अवधि तक का होता है।

कार्य

- संविधान के अंतर्गत अथवा सरकार के किसी भी आदेश के अंतर्गत अथवा सरकार के किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यान्वन का मूल्यांकन करना है।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और संघ एवं किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत होना और ऐसे समयों पर प्रस्तुत होना जब आयोग उन सुरक्षा उपायों पर किए गए काम की रिपोर्ट पेश करता है।
- ऐसी रिपोर्टों में, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संघ अथवा किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों हेतु सिफारिश करना।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –संवैधानिक निकाय

स्रोत- द हिंदू

6. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का 14वां स्थापना दिवस**

- गृह राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के 14वें स्थापना दिवस का अनावरण किया है।
- इस वर्ष के स्थापना दिवस की थीम 'आपदाओं हेतु प्रारंभिक चेतावनी' है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

- वर्ष 2005 में, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित किया था, जिसके कारण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना हुई थी।
- भारत में आपदा प्रबंधन हेतु समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का नेतृत्व और कार्यान्वयन करने के लिए एन.डी.एम.ए. का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है।

टॉपिक- जी. एस.पेपर 3 –आपदा प्रबंधन

स्रोत-पी.आई.बी.

7. **<u>अलनीनो पहले से परेशान भारतीय किसानों को हानि पहुंचा सकता है।</u>**

- इस सत्र में छह भारतीय राज्यों ने सूखा घोषित कर दिया है और गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई अन्य राज्य भी वर्षा की भारी कमी के साथ शीघ्र ही इस सूची में शामिल हो जाएंगे।
- आई.एम.डी. का कहना है कि सामान्य अलनीनो दक्षिणी दोलन (ई.एन.एस.ओ.) स्थितियां वर्तमान में भूमध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में प्रचलित हैं और अगले दो महीनों में अलनीनों के विकसित होने की संभावना है।
- यदि अलनीनो, वसंत और ग्रीष्म ऋतु के मौसम में जारी रहता है तो यह वर्ष 2019 के मानसून के दौरान औसत वर्षा को कम कर सकता है और सामान्य गर्मियों के तापमान से अधिक गर्म हो सकता है।
- सितंबर में असामान्य रूप से कम वर्षा होने और भारत में मानसून के बाद महीनों के में कम वर्षा हेतु अलनीनो के विकसित होने का कारण हो सकता है।
- सितंबर 2018 में देश में 24 प्रतिशत की बारिश की कमी देखी गई, मानसून के बाद के महीनों में यह बढ़कर 49 प्रतिशत (1 अक्टूबर- 21 नवंबर) हो गई है।
- सबसे खराब स्थिति मध्य भारत में हैं जहां पर सामान्य से 64 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।
- पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में क्रमशः 58 प्रतिशत और 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

संबंधित जानकारी

- 1880 और 2014 के बीच 135 वर्षों में, सभी विकसित अलनीनो वर्षों के लगभग 90 प्रतिशत वर्षों में सामान्य वर्षा से कम वर्षा देखी गई है और उनमें से 65 प्रतिशत वर्षों सूखा पड़ा है।
- वर्ष 1871 के बाद से देश में सबसे खराब 6 सूखे का कारण अलनीनो था- हाल ही में वर्ष 2009 में सूखे का कारण अलनीनो था।
- दुनिया भर के सभी मौसम मॉडलों ने इस वर्ष के अंत तक अथवा अगले वर्ष की शुरुआत में अलनीनो घटना की उच्च संभावना की भविष्यवाणी की थी।
- हिंद महासागर द्विध्रुव (आई.ओ.डी.), बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य एक और समुद्री तापमान गतिरोध भी वर्तमान में अपने सकारात्मक चरण में है।
- लेकिन आई.एम.डी. भविष्यवाणी करता है कि यह स्थिति अस्थायी है।
- एक सकारात्मक आई.ओ.डी. का अर्थ है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से अधिक गर्म है और यह सामान्यत: अलनीनो घटना से संबंधित है।

अलनीनो के संदर्भ में जानकारी-

- सामान्य वर्ष में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में एक सतह निम्न दबाव विकसित होता है और पेरू के तट पर एक उच्च दबाव प्रणाली विकसित होती है।
- अलनीनो, केंद्रीय और पूर्व-केंद्रीय भूमध्य प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने को संदर्भित करता है जो केंद्रीय प्रशांत के बड़े क्षेत्रों और दक्षिण अमेरिका के तट पर वायु दाब के घटने का कारण बनता है।
- प्रशांत महासागर के गर्म पानी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में हवाएं पलट जाती हैं।
- हवा की दिशा में हुए इस बदलाव के कारण गर्म सर्दियां, गर्मी पड़ती है और मानसून के दौरान कम वर्षा होती है।

- अधिकतर समय में इसके कारण सूखा पड़ता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3- पर्यावरणीय मुद्दे

स्रोत- डाउन टू अर्थ

8. **<u>आर.बी.आई. ने भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है।</u>**

- भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के स्टार्टअप क्षेत्र (एस.आई.एस.एस.) पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है।
- इसका उद्देश्य इन व्यवसायों के प्रोफाइल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना और अन्य कारकों के साथ उनकी लाभप्रदता के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना है।
- यह सर्वेक्षण, देश के लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण तक पहुँच को आसान बनाने हेतु आर.बी.आई. को प्राप्त प्रार्थनाओं के आधार पर शुरू किया गया है।

संबंधित जानकारी

सरकारी पहल

- सरकार ने पहले से ही पी.एम.एम.वाई. (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना), मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक, 200 अरब रुपये की पुनर्वित्त निधि के साथ सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त गतिविधियों हेतु एक नया संस्थान स्थापित कर रही है।
- स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, एक अभियान है जो भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप कार्य योजना पर आधारित है। जिसका उद्येश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- स्टैंडअप इंडिया पहल का उद्देश्य भी उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, लेकिन यह एस.सी./ एस.टी. महिला समुदायों के मध्य ही बढ़ावा देने तक सीमित है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- टी.ओ.आई.

30.11.2018

1. **<u>कोंकण 18 - भारत - यू.के. नौसेना युद्धाभ्यास</u>**

- भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के मध्य द्विपक्षीय कोंकण युद्धाभ्यास का गोवा में शुभारंभ किया गया है।
- यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास दो नौसेनाओं के लिए समय-समय पर समुद्र और बंदरगाह में युद्धाभ्यास करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे कि दोनों देशों के मध्य अंतःक्रियाशीलता का निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके।
- रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में सकारात्मक जलवायु सुनिश्चित करने हेतु नौसेना सहयोग दोनों देशों की प्रतिबद्धता का ठोस प्रतीक है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **<u>जम्मू-कश्मीर, सरकारी कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में सजा के कानून को जेल के साथ संशोधित कर रहा है।</u>**

- सरकार ने वर्तमान में लागू रणबीर दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (वकालती) के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- इस प्रावधान के अंतर्गत, जम्मू-कश्मीर में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा की गयी अवांछित यौन गतिविधि शीघ्र ही एक दंडनीय अपराध होगी, जिसमें यौन सूचक आचरण और किसी लाभ के बदले किसी महिला को छूना शामिल है। इस अपराध की सजा में कम से कम 3 वर्ष की जेल और जुर्माने का प्रावधान होगा।
- मसौदे संशोधन के अनुसार, प्राधिकार के पद में स्थित अथवा किसी प्रत्ययी संबंध में अथवा ऐसे पद का दुरूपयोग करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी अथवा भरोसेमंद संबंधों का दुरुपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति उत्पीड़न करने हेतु शारीरिक अथवा गैर-शारीरिक रूप से जबरदस्ती करने का प्रयास करता है अथवा लाभ के बदले

किसी महिला से यौन संबंधो की मांग करता है तो ऐसा व्यक्ति "छेड़छाड़ (सेक्सटार्शन)" के अपराध के दोषी के रूप में माना अथवा प्रक्रियारत होगा।

संबंधित जानकारी

- रणबीर दंड संहिता अथवा आर.पी.सी., जम्मू-कश्मीर में लागू एक आपराधिक संहिता है।
- यह संहिता डोगरा वंश में रणबीर सिंह के शासन के दौरान पेश की गई थी।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत यहां भारतीय दंड संहिता लागू नहीं की जा सकती है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महिला सुरक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

3. **<u>एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक भारत भी है।</u>**

- लैंसेट काउंटडाउन 2018 के द्वारा स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1986 से 2005 के मध्य की आधारभूत अवधि की तुलना में वर्ष 2000 से 2017 के मध्य वैश्विक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति 1.4 दिनों की अतिरिक्त ऊष्मा तरंगो के संपर्क में रहा था।
- वर्ष 2014-2017 तक, भारत में ऊष्मा तरंगों की औसत लंबाई, 0.8-1.8 दिनों के वैश्विक औसत की तुलना में 3-4 दिन रही थी।
- वर्ष 2016 में भारतीयों ने लगभग 60 मिलियन ऊष्मा तरंगों की घटनाओं का सामना किया है जो कि वर्ष 2012 से लगभग 40 मिलियन अधिक है।
- यह रिपोर्ट भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ के साथ संयुक्त रूप से बनाई गई है, यह रिपोर्ट जलवायु स्थितियों के संबंध में मौजूदा व्यावसायिक स्वास्थ्य मानकों, श्रम कानूनों और कार्यकर्ता सुरक्षा के क्षेत्रीय नियमों की समीक्षा का आग्रह भी करती है।
- कृषि क्षेत्र, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की तुलना में अधिक कमजोर था क्यों कि इस क्षेत्र में श्रमिकों को अधिक समय तक धूप के संपर्क में रहना पड़ता है।

रिपोर्ट में भारत के लिए सिफारिशें-

- वर्ष 2012-2016 की अवधि के दौरान देश में ऊष्मा लहर की घटनाओं के संपर्क में वृद्धि होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति बढ़े हुए जोखिम और कम हुए कार्यकारी घंटों की हानि को कम करने के लिए भारतीय नीति निर्माताओं को अवश्य ही पहलों की एक श्रृंखला शुरू करनी होगी।
- इसमें मौसम संबंधी डेटा की उचित ट्रैकिंग के माध्यम से "गर्म हॉट-स्पॉट" की पहचान करना भी शामिल है।
- "रणनीतिक अंतर-संस्था समन्वय के साथ स्थानीय ऊष्मा कार्यवाही योजना के कार्यान्वन और सामयिक विकास और सबसे कमजोर समूहों को लक्षित करने वाली प्रतिक्रियाओं" का संवर्धन करना।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया था कि वर्ष 1901 से 2007 तक औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हुई थी, जिसमें काफी भौगोलिक विविधताएं थी। अनुसंधान समूहों द्वारा किए गए जलवायु पूर्वानुमान में 21वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी, केंद्रीय और पश्चिमी भारत के तापमान में 2.2-5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि का अनुमान लगाया है।

संबंधित जानकारी

सरकार किस प्रकार आपदाओं/ प्राकृतिक आपदाओं को वर्गीकृत करती है?

- 10वें वित्त आयोग (1995-2000) ने एक प्रस्ताव की जांच की जिसमें एक आपदा को "दुर्लभ गंभीरता की राष्ट्रीय आपदा" कहा गया था, यदि वह आपदा राज्य की एक तिहाई आबादी को प्रभावित करती है।
- पैनल ने "दुर्लभ गंभीरता की आपदा" को परिभाषित नहीं किया है लेकिन पैनल ने इसके संदर्भ में कहा कि दुर्लभ गंभीरता की आपदा को केस-टू-केस आधार के साथ ही आपदा की तीव्रता और परिमाण, आवश्यक सहायता के स्तर, समस्या से निपटने के लिए राज्य की क्षमता, सहायता और राहत प्रदान करने हेतु योजना में उपलब्ध विकल्प और सुविधाएं आदि के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एन.सी.सी.डी.)

- सातवीं अनुसूची में उल्लिखित उत्पादों के मामले में, निर्मित या उत्पादित उत्पाद होने के कारण केंद्र के उद्देश्य हेतु वसूल और एकत्र किए जाने वाले अधिभार, सीमा शुल्क को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क कहा जाता है (बाद में इसे राष्ट्रीय आपदा शुल्क के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

4. **<u>कर्च जलसंधि टकराव</u>**

- यूक्रेनी जहाज और नाविकों को क्रीमियां में रूस ने बंदी बना लिया है।
- रूस ने जेट और हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया है और यहां तक कि नाव के माध्यम से कर्च जलसंधि के मार्ग को बंद कर अज़ोव के सागर तक पहुंच के मार्ग को भी बंद कर दिया।

संबंधित जानकारी

कर्च जलसंधि

- कर्च जलसंधि, रूस देश और क्रीमिया के मध्य एक जलमार्ग है, जिसे रूस ने वर्ष 2014 में यूक्रेन से अपने कब्जे में ले लिया था।
- यह अजोव सागर में मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो रूस और यूक्रेन के मध्य की सीमा है।
- एक द्विपक्षीय संधि दोनों देशों को पानी में गश्त करने का अधिकार प्रदान करती है।
- रूस ने वर्ष 2014 से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को काफी हद तक बढ़ाया है।

रूस-यूक्रेन संबंधों की स्थिति क्या है?

- यूक्रेन में एक क्रांति के बाद पिछले राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, रूस ने क्रीमिया के प्रायद्वीप को कब्जे में ले लिया है और दक्षिण-पूर्व यूक्रेन में अलगाववादी विद्रोह का समर्थन किया है।
- यूक्रेन ने रूस के साथ संधियों को समाप्त करने के द्वारा प्रतिक्रिया दी है और पश्चिम से समर्थन देने के लिए कहा है।
- वर्ष 2014 से दक्षिण-पूर्व यूक्रेन में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और संघर्ष अभी भी चल रहा है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

5. **<u>अनुवांशिक अध्ययन ने हॉग डियर की दुर्लभ उप प्रजातियों की उपस्थिति का पता लगाया है।</u>**

- भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में लुप्तप्राय हॉग डियर की एक उप-प्रजाति की खोज की है, जिन्हें पहले केंद्रीय थाईलैंड के पूर्वी हिस्से तक सीमित माना जाता था।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून (डब्ल्यू.आई.आई.) के शोधकर्ताओं ने कीबुललामजाओं राष्ट्रीय उद्यान (के.एल.एन.पी.), मणिपुर में हॉग डियर की एक छोटी आबादी की उपस्थिति का पता लगाया है।
- इसकी श्रेणी से हॉग डियर की दो उप-प्रजातियों को पता लगाया है:

1. पश्चिमी जाति, पाकिस्तान और तराई के घास के मैदानों में वितरित है (हिमालयी तलहटी के साथ, पंजाब से अरुणाचल प्रदेश तक)।
2. हॉग डियर की पूर्वी जाति, थाईलैंड, भारत-चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में पाई जाती है।

संबंधित जानकारी

हॉग डियर

- हॉग डियर, अन्य देशों में विलुप्त हो रहें हैं, कीबुललामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक रूप से विशिष्ट और विकासशील महत्वपूर्ण आबादी पायी गयी है।
- हॉग डियर को भारत-म्यांमार सीमा पर एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है जो संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
- हॉग डियर अथवा पाडा, आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियां हैं।
- वे भारतीय वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित हैं।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –जैवविविधता

स्रोत- डाउन टू अर्थ

6. **<u>इसरो के पी.एस.एल.वी.-सी.43 ने सफलतापूर्वक एच.वाई.एस.आई.एस. और 30 विदेशी उपग्रहों को उनकी सापेक्षिक कक्षाओं में भेजा है</u>**।

- इसरो के पी.एस.एल.वी.-सी.43 ने सफलतापूर्वक एच.वाई.एस.आई.एस. और 30 विदेशी उपग्रहों

को सूर्य के मार्ग को पार करने वाले प्रक्षेप पथ में स्थापित किया है।

- 30 उपग्रहों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन में से प्रत्येक का एक उपग्रह और संयुक्त राज्य अमेरिका से 23 उपग्रह शामिल हैं।

संबंधित जानकारी

हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट (एच.आई.एस.आई.एस.)

- एच.आई.एस.आई.एस. उपग्रह अथवा उन्नत की गई 'शार्प आई, भारत का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है जो उन्नत पृथ्वी अवलोकन के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसे पी.एस.एल.वी.-सी.43 लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया था।
- एच.आई.एस.आई.एस. लगभग 5 वर्षों के मिशन जीवन के साथ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यमान, निकट अवरक्त और न्यूनतरंगीय अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेगा।
- इसमें एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा है जो अंतरिक्ष में अच्छी तरह से परिभाषित छवियां प्रदान कर सकता है जो नियमित प्रकाशीय अथवा रिमोट सेंसिंग कैमरों की तुलना में पृथ्वी पर वस्तुओं की पहचान करने में मदद कर सकता हैं।
- इस तकनीकि का रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, भूमि उपयोग, तटीय क्षेत्रों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष से भारत को देखने का एक अतिरिक्त लाभ होगा।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

7. **<u>ग्रेट बैरियर रीफ पर सबसे बड़ी प्रवाल शोधन परियोजना शुरू की गई है।</u>**

- वैज्ञानिकों ने उनके वार्षिक वंश वृद्धि के दौरान लाखों जीवों के अंडों और शुक्राणुओं की कृषि के द्वारा लुप्तप्राय ग्रेट बैरियर रीफ पर प्रवाल को पुन: उत्पन्न करने का सबसे बड़ा प्रयास शुरू किया है।
- शोधकर्ता, प्राप्त किए गए अंडो से प्रवाल लार्वा उगाने और जलवायु संबंधित प्रवाल विरंजन के द्वारा बुरी तरह से नष्ट हुए चट्टान के इन दो क्षेत्रों को लौटाने की योजना बना रहे हैं।
- "लार्वा बहाली परियोजना" के लॉन्च का समय, चट्टान पर वार्षिक प्रवाल वंश वृद्धि के समय पर ही है, जो इस हफ्ते के प्रारंभ में शुरू हो जाएगा और केवल 48 से 72 घंटों तक ही चलेगा।
- 2,300 किलोमीटर (1,400 मील) चट्टान के बड़े क्षेत्र के किनारे रहने वाले प्रवाल जलवायु परिवर्तन से संबंधित बढ़ते हुए समुद्र तापमान से मारे गए हैं, इस प्रक्रिया में कंकाल के शेष बचने को प्रवाल विरंजन के नाम से जानते है।
- चट्टान के उत्तरी क्षेत्रों में वर्ष 2016 और 2017 में लगातार दो वर्ष अभूतपूर्व गंभीर विरंजन का सामना किया है, ऐसा डर है कि इससे होने वाले नुकसानों की भरपाई नहीं की जा सकेगी।

संबंधित जानकारी

प्रवाल विरंजन

- प्रवाल विरंजन अथवा प्रवाल का सफेद होना, प्रवाल के सहजीवी शैवाल (ज़ोक्सेंथैल) के नुकसान होने अथवा शैवाल के प्रकाश संश्लेषक रंग के हल्के होने के परिणामस्वरूप होता है।
- विरंजन, प्रवाल चट्टानों के नष्ट होने से संबंधित है, जो लगभग सभी समुद्री प्रजातियों के 25 प्रतिशत का निवास स्थान है।

कोरल ब्लीचिंग के कारण

- यह समुद्री जल तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप, विशेषकर सौर विकिरण (पराबैंगनी विकिरण) के ऊंचे स्तरों से संबंधित होने पर ऐसा होता है।
- यह समुद्री जल के संघटन (समुद्री अम्लीयता अथवा प्रदूषण) में परिवर्तन होने के कारण भी हो सकता है।
- ऐसा तब ही होता है जब समुद्री जल में गंदगी के स्तर में वृद्धि होती है अथवा प्रवाल के सोडियम साइनाइड प्रवाल चट्टान मछलियों को पकड़ने में प्रयोग किया जाने वाला एक रासायन) के संपर्क में आाने पर होता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2- जैवविविधता

स्रोत- टी.ओ.आई.

8. **<u>बैंगलोर में डाटासिटी 'शहरी चुनौती की शुरूआत की गई है।</u>**

- कर्नाटक सरकार ने फ्रांस स्थित उपयोगिता कंपनी सुएज़ और स्टार्ट-अप प्रेरक नुमा के साथ भागीदारी में 'डेटासिटी' नामक एक पहल की शुरूआत की है।
- यह डाटा और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए शहर की चुनौतियों और विकास समाधानों का पता लगाने हेतु शहर के अधिकारियों, निगमों और स्टार्ट-अप को एक स्थान पर लाने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय ओपेन नवाचार कार्यक्रम होगा।
- यह 7 महीने का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य आवेदनों के समूह से संबंधित नवाचार स्टार्ट अप की पहचान करना और डाटा का प्रयोग करते हुए समाधानों के साथ परीक्षण करने हेतु बैंगलोर और निगमों को एक साथ लाना है।
- 'डेटासिटी' के दौरान बढ़ने वाले अवसर के क्षेत्रों में स्मार्ट गतिशीलता,जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा, स्मार्ट भवन, सुरक्षा और प्रदूषण प्रबंधन हैं।

संबंधित जानकारी

- बैंगलोर ऐसी पहलों में अकेला नहीं है।
- कोयंबटूर, शहर के निवासियों के लिए स्थायी जल प्रबंधन हेतु सिद्धांत विकसित करने के लिए फ्रौनहोफर आई.जी.बी., इंस्टीट्यूट फॉर सोशल-इकोलॉजिकल रिसर्च जैसे जर्मन वाटर, वेस्ट वाटर प्रौद्योगिकियों और संस्थानों के साथ काम कर रहा है।
- सुएज़, जल उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन समाधान प्रदान करता है।

टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

***

gradeup

Banking, SSC, GATE, JEE, NEET & other Online Mock Test Series

- Based on Latest Exam Pattern
- Available in Hindi & English
- Get all India rank & result analysis
- Detailed Solutions
- Can be taken on web & mobile

ANDROID APP ON Google play

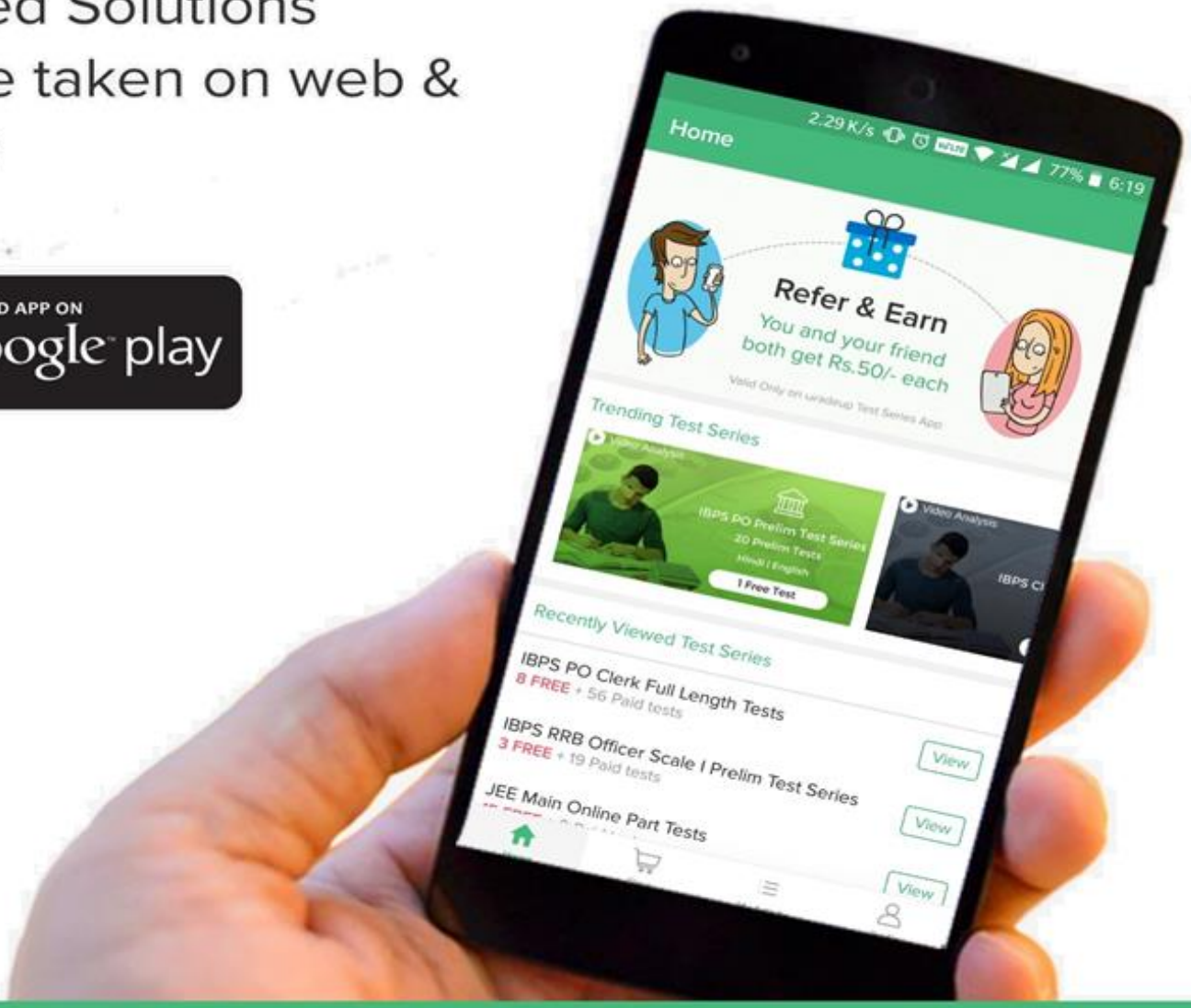

www.gradeup.co